चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

भंवर में अन्ना

पेज-3

उफ़, ये कोहरा!

पेज-6

वनों में प्रकाश की किरण

पेज-7

साई की महिमा

पेज-12

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 05 दिसंबर-11 दिसंबर 2011 | मूल्य 5 रुपये

विजय माल्या और सियासत का गठजोड़

आसमान में घोटाला

फोटो-प्रभात पाण्डेय

विजय माल्या को फ़ायदा पहुंचाने के लिए प्रफुल्ल पटेल ने सरकारी इंडियन एयर लाइंस को तबाह करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी. इंडियन एयर लाइंस की सभी उड़ानों को घाटे वाले रूट पर डाल दिया गया और उसकी सर्विस इतनी अनियमित कर दी गई कि यात्रियों ने इसकी उड़ानों का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया. प्रफुल्ल पटेल ने रही सही कसर 111 विमानों की एक साथ ख़रीद करके पूरी कर दी, वह भी क़र्ज़ लेकर. सीएजी की रिपोर्ट में भी प्रफुल्ल पटेल के कार्यकाल में एयर इंडिया में हुई विमानों की ख़रीद-फ़रोख्त पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं.

रूबी अरुण

यह भारतीय लोकतंत्र का बाज़ारू चेहरा है, जो कॉर्पोरेट्स के हितों के मुताबिक़ फ़ैसले लेता है. जहां लोकतंत्र के पहरुवे, भूख से मरते किसानों के लिए रोटी का इंतज़ाम करने का अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करते, लेकिन उद्योग जगत के महारथियों के क़दमों में लाल क़ालीन बनकर बिछ जाना अपनी शान समझते हैं. इस लोकतंत्र के बाज़ारवाद का इससे बड़ा नंगा सच और क्या होगा कि जब देश में हर आठ घंटे पर एक किसान भुखमरी और महज़ पचास रुपये के क़र्ज़ का शिकार होकर ख़ुदकुशी कर रहा है, तब सरकार बाईस हज़ार करोड़ की संपत्ति के मालिक किंग फिशर एयर लाइंस के चेयरमैन विजय माल्या को और भी मालामाल करने की क़वायद में जुटी है. सवाल यह है कि सरकार विजय माल्या को हज़ारों करोड़ रुपये का सहारा देने की बजाय ख़स्ताहाल हो चुके एयर इंडिया के संचालन को लेकर इतनी सतर्क और चिंतित क्यों नहीं है? आख़िर सरकार विजय माल्या के प्रति इतनी नरम क्यों है?

दरअसल, मनमोहन सरकार की नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाने वाले मंत्री और नेताओं के साथ-साथ भाजपा की गणमान्य हस्तियां भी विजय माल्या के सियासी प्यादों की भूमिका में हैं. कांग्रेस के राजीव शुक्ला, मुरली देवड़ा, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, व्यालार रवि, एसएम कृष्णा, राकांपा के शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और राम जेठमलानी सरीखे नेता पार्टी के दायरे से परे जाकर बड़ी निष्ठा से विजय माल्या के राजनीतिक और व्यापारिक मोहरों का किरदार निभा रहे हैं.

इन नेताओं को अरबपति विजय माल्या के ग्यारह सौ चौतीस करोड़ का सरकारी क़र्ज़ माफ़ कराने के लिए देश की जनता के हलक़ से निवाला छीनने तक से गुरेज़ नहीं है. लिहाज़ा किंग फिशर एयर लाइंस को सरकार बेल आउट पैकज देने की तिकड़म में लग चुकी है. हालांकि सरकार की, इस लाभ के निजीकरण और घाटे के राष्ट्रीयकरण की जनविरोधी कोशिश का विरोध राहुल बजाज जैसे सांसद-उद्योगपति कर रहे हैं. लेकिन सरकार और विपक्ष ने आशिक़ी और रंगीन-मिज़ाजी के लिए मशहूर विजय माल्या की अय्याशियों को और भी परवान देने के लिए कमर कस ली है. इन सबके बीच भी एक अहम कड़ी है सतीश ओहरी. सतीश ओहरी एक पत्रकार है, जो एक पत्रिका निकालते हैं, जिसका का नाम है बिजनेस ऐट जीरो ऑवर. शिवालिक, पंचशील, गीतांजलि रोड, नई दिल्ली से निकलने वाली यह पत्रिका बाज़ार में नहीं मिलेगी. पर इस पत्रिका के संपादक, मुद्रक और प्रकाशक के तौर पर सतीश ओहरी पावर गैलरी में संपर्क बनाता और दलाली करता हुआ ज़रूर मिल जाएगा. दलाली भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों की, जिसमें विजय माल्या जैसे उद्योगपतियों का नाम ख़ास तौर पर शामिल है. टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले में जब दलाल नीरा राडिया से सीबीआई पूछताछ कर रही थी, तब नीरा ने सतीश का नाम जांच अधिकारियों को बताया था. नीरा के मुताबिक़, सतीश ओहरी को घोटाला और उसकी जांच से संबंधित सभी प्रक्रियाओं की जानकारी पहले से ही होती थी. उसी सतीश ओहरी ने ज़मीन से आसमान तक सपनों को बेचने वाले विजय माल्या के लिए भी कई मंत्रालयों और मंत्रियों के बीच बिचौलिये का काम किया है. सतीश ओहरी को पावर गैलरी में दाख़िला भी देश के दो बड़े पत्रकारों की बदौलत ही मिला था.

देश के लोगों का दुर्भाग्य देखिए, महाराष्ट्र के जिस विदर्भ क्षेत्र के किसान दाने-दाने को तरस रहे हैं, उसी प्रदेश का केंद्र में प्रतिनिधित्व करने वाले मराठा क्षत्रप शरद पवार, विजय माल्या के ऊपर इस तरह मेहरबान हैं कि वह विजय माल्या के साथ व्यापार में भी साझीदार हो गए. विजय माल्या की आईपीएल टीम में शरद पवार की 16 फ़ीसदी की हिस्सेदारी भी रही है. शरद के अलावा जो बड़े सियासी कारिंदे विजय माल्या के पहलू में हैं, उनमें राजीव शुक्ला, प्रफुल्ल पटेल और मुरली देवड़ा का नाम सबसे ऊपर आता है.

बहरहाल, हर साल ख़ूबसूरत मॉडलों के नंगे कैलेंडर बनवाने में करोड़ों रुपये उड़ाने और आलीशान पार्टियों पर पानी की तरह पैसा बहाने वाले इस शख़्स ने, अपने संसाधनों और भौतिक सुविधाओं के मार्फ़त भारतीय राजनीति की आला हस्तियों और सरकार पर इस क़दर शिकंजा कस रखा है कि वह बड़े गुरुर के साथ यह ऐलान करता है कि किंग फिशर एयर लाइंस को घाटे से उबारना और उसे मुनाफ़े का सौदा बनाना सरकार का काम है, उसका नहीं. और उसकी इस बात पर हमेशा मौन साधे रहने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी इस संकट से रास्ता निकलने की बात कह रहे हैं. कमाल की बात तो यह है कि सरकार पर छोटी से छोटी बात पर धावा बोलने को तैयार बैठी विपक्षी पार्टियों ने भी बिलकुल ही चुप्पी साध रखी है. विजय माल्या के ख़िलाफ़ एक भी विरोध का स्वर मुखर नहीं है.

विमानन मंत्री व्यालार रवि, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से इस मसले पर गहन मंत्रणा करते देखे जा रहे हैं. मुरली देवड़ा और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, सीधे प्रधानमंत्री के निर्देशन में सभी राष्ट्रीय बैंकों के साथ बैठकें कर रहे हैं, ताकि विजय माल्या को इस तथाकथित संकट से उबारा जा सके.

थोड़े ही समय में इसके परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं. कंपनियों ने बिना बक़ाया वसूले तेल की सप्लाई शुरू कर दी है, जबकि तेल कंपनियों के लगभग नौ सौ करोड़ रुपये विजय माल्या पर बक़ाया हैं. सीधी सी बात है, यहां न सिर्फ़ मनमोहन सरकार दोषी है, बल्कि देश की तमाम विपक्षी पार्टियां भी बराबर की गुनाहगार हैं. ये सभी मिलकर जनता के पैसे को देश के धन-पशुओं में बांटकर देश चलाने का धंधा कर रही हैं. मीडिया और बैठकों के ज़रिये शगूफ़ा यह छोड़ा जा रहा है कि अगर किंगफिशर बंद हो गया तो देश पर बेरोज़गारी का बोझ बढ़ेगा. मगर हक़ीक़त यह है कि यह बेरोज़गारी उस आंकड़े की महज़ एक फ़ीसदी होगी, जो पिछले साढ़े सात सालों के मनमोहन राज में किसानो की भूख और क़र्ज़ के तले दबकर आत्महत्याओं की है.

देश के लोगों का दुर्भाग्य देखिए, महाराष्ट्र के जिस विदर्भ क्षेत्र के किसान दाने-दाने को तरस रहे हैं, उसी प्रदेश का केंद्र में प्रतिनिधित्व करने वाले मराठा क्षत्रप शरद पवार, विजय माल्या के ऊपर इस तरह मेहरबान हैं कि वह विजय माल्या के साथ व्यापार में भी साझीदार हो गए. विजय माल्या की आईपीएल टीम में शरद पवार की 16 फ़ीसदी की हिस्सेदारी भी रही है. शरद के अलावा जो बड़े सियासी कारिंदे विजय माल्या के पहलू में हैं, उनमें राजीव शुक्ला, प्रफुल्ल पटेल और मुरली देवड़ा का नाम सबसे ऊपर आता है.

ज़रा ग़ौर कीजिए कि किस तरह इन लोगों ने विजय माल्या को बीयर के बादशाह से आसमान का भी शहंशाह बना दिया. 2003 में किंगफिशर वजूद में आया. 2006 में यह लिस्टेड हुआ. तभी से विजय माल्या ने उधारी का खेल खेलना शुरू कर दिया. 2008 में तेल कंपनियों ने पहली बार पैसा न चुकाने का सवाल उठाया, लेकिन तब तक तत्कालीन उड्डयन मंत्री और विजय माल्या के क़रीबी संबंधी प्रफुल्ल पटेल ने विजय माल्या को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की स्थायी समिति का सदस्य नामित कर दिया था. मतलब यह, जिनकी प्राइवेट एयर लाइंस थी, उन्हें ही एयर लाइंस के धंधों पर नज़र रखने के लिए नियुक्त कर दिया गया. ज़ाहिर है कि ऐसे में न तो तेल कंपनियों की हिम्मत हुई कि वे विजय माल्या से बक़ाया वसूलने की बात करें और न ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फीस वसूलने का साहस दिखाया. ऊपर से बैंकों ने भी विजय माल्या को मुंहमांगा लोन देने में पूरी उदारता बरती. दरअसल, जब तक पटेल विमानन मंत्री रहे, तब तक उन्होंने विजय माल्या से ख़ूब रिश्तेदारी निभाई. पटेल के निर्देश पर कमाई के अधिकतर रूट किंग

(शेष पृष्ठ 2 पर)

कृष्णा, जिन्होंने 19 अन्य पूर्व बाबुओं के साथ एक स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है, के अनुसार विनोद राय को लेकर सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच चल रहा विवाद बेतुका है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

सूचना आयोग के बाबू

आरटीआई कार्यकर्ताओं को हमेशा इस बात की शिकायत रहती है कि अधिकारियों को ही सूचना आयुक्त क्यों बनाया जाता रहा है. 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया, लेकिन उस समय से देखा जाए तो कई सूचना आयुक्त यहां तक कि मुख्य सूचना आयुक्त भी सिविल सेवा के अधिकारी रहे हैं. उदाहरण के तौर पर वजाहत हबीबुल्ला, एएन तिवारी, अमीता पॉल, ए पी के जरवाल तथा सत्येंद्र मिश्रा का नाम लिया जा सकता है. लेकिन अब स्थितियां बदलने वाली हैं. अभी इस विभाग में सूचना आयुक्त के दो पद रिक्त हैं. सूत्रों के अनुसार, डीओपीटी ने इन रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को पहले से अधिक पारदर्शी बनाया है. इसने पद के उम्मीदवारों के नाम अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं, ताकि लोग इसे देख सकें. इसका एक मतलब यह भी है कि अब बाबू के अतिरिक्त अन्य लोग भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. लगता है, इस आयोग में कुछ बदलाव आने वाला है.

बाबुओं की ज्ञान बैठक

प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय के बाबुओं की बैठक होती है, जिसमें नियमित कार्यों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर चर्चा की जाती है, ताकि कुछ सुधार हो सके. इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी. उस समय डी. सुब्बाराव वित्त सचिव और पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे. इस बैठक में उपसचिव या उससे ऊपर स्तर के लगभग सत्तर बाबू हिस्सा लेते हैं. इस बार यह बैठक जनवरी, 2012 की शुरुआत में हरियाणा के सोहना में आयोजित की जानी है. सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में काम की बातें तो कम ही होती हैं, जबकि मनोरंजन ज़्यादा होता है. इस बार बैठक जनवरी में होने वाली है. अगर इन बाबुओं ने इस बैठक की अहमियत को समझा और सही मुद्दों पर बातचीत की तो इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि आगामी बजट में इसका फ़ायदा दिखाई दे सकता है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यह ज्ञान बैठक बेकार साबित होगी.

बाबुओं की एकता

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की सहायता करने के लिए कई सेवानिवृत बाबू सामने आ गए हैं. ग़ौरतलब है कि कैग ने 2जी स्पेक्ट्रम में जो घाटा दिखाया था, उससे सरकार सहमत नहीं है. सरकार ने इसे चैलेंज किया था. उनका मानना है कि विनोद राय के साथ सरकार ग़लत कर रही है तथा इस संस्था को कमज़ोर करना चाहती है. वित्त मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव एस. कृष्णा, जिन्होंने 19 अन्य पूर्व बाबुओं के साथ एक स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है, के अनुसार विनोद राय को लेकर सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच चल रहा विवाद बेतुका है. एस. कृष्णा के अलावा पूर्व जल संसाधन सचिव रामास्वामी आर. अय्यर, लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के पूर्व मंत्री निलांबर श्रीवास्तव, पूर्व अतिरिक्त सचिव बीएस रामास्वामी तथा पूर्व उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लक्ष्मीनारायण, डॉ. बीपी माथुर, आर. परमेश्वर, धरम वीर, आईपी सिंह, विजय कुमार ने भी विनोद राय का साथ दिया है.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

अशोर कुमार जेएस बने

1991 बैच के आईएएस अधिकारी जी. अशोक कुमार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह रोहित नंदन की जगह लेंगे, जिन्हें एयर इंडिया में सीएमडी बनाया गया है.

ज्योति संयुक्त सचिव बनीं

1987 बैच की आईएएस अधिकारी ज्योति अरोड़ा को ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह सुधीर कुमार की जगह लेंगी.

अमिताभ एएस बने

1979 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. अमिताभ रंजन को राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है. वह के. जोसे की जगह लेंगे, जिन्हें केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग में सचिव बनाया गया है.

शैलेष कोयला मंत्रालय जाएंगे

1991 बैच के आईएएस अधिकारी शैलेष कुमार सिंह को कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया जाएगा. वह रजनीश कुमार महाजन की जगह लेंगे.

रीतेश निदेशक बनेंगे

1997 बैच के आईटीएस अधिकारी रीतेश कावडीय को रक्षा मंत्रालय में निदेशक बनाया जाना है.

रहाटे वित्तीय आयुक्त बने

1990 बैच के आईएएस अधिकारी एसकेजी रहाटे को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वित्तीय आयुक्त बनाया गया है. वह राजीव दत्त की जगह लेंगे

आसमान में घोटाला

पृष्ठ एक का शेष

फिशर को ही मिलते रहे. विजय माल्या को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पटेल ने सरकारी इंडियन एयर लाइंस को तबाह करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी. इंडियन एयर लाइंस की सभी उड़ानों को घाटे वाले रूट पर डाल दिया गया और उसकी सर्विस इतनी अनियमित कर दी गई कि यात्रियों ने इसकी उड़ानों का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया. प्रफुल्ल पटेल ने रही सही कसर 111 विमानों की एक साथ ख़रीद करके पूरी कर दी, वह भी क़र्ज़ लेकर. सीएजी की रिपोर्ट में भी प्रफुल्ल पटेल के कार्यकाल में एयर इंडिया में हुई विमानों की ख़रीद–फ़रोख्त पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. सीएजी ने साफ़ तौर पर कहा है कि क़र्ज़ लेकर की गई 111 विमानों की ख़रीद ही एयर इंडिया की तबाही के लिए ज़िम्मेदार है.

सीएजी के मुताबिक़, प्रफुल्ल पटेल के नागरिक उड्डयन मंत्री रहते तत्कालीन एयर इंडिया लिमिटेड ने 50 विमानों की ख़रीद–फ़रोख्त के लिए बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक के साथ समझौता किया था. सीएजी के अनुसार जो 111 विमान ख़रीदे गए, उससे एयर इंडिया पर 38,423 करोड़ रुपये का क़र्ज़ हो गया. यह ख़रीद–फ़रोख्त एयर इंडिया की ज़रूरत से नहीं, बल्कि मंत्रालय के फ़ैसले से प्रभावित थी. वहीं दूसरी तरफ़ पटेल ने विजय माल्या को बेहद फ़ायदे का सौदा कराया. विजय माल्या ने प्रफुल्ल पटेल की मदद से उस वक़्त की सबसे सस्ती मानी जाने वाली फ्लाइट एयर डक्कन के 21 जहाज़ों के बेड़े को ख़रीदा और उसे किंगफिशर रेड के नाम से रनवे पर उतारा. उस समय भी विमान ईंधन के दाम और एयरपोर्ट सरचार्ज हमेशा 3000 करोड़ से ऊपर ही रहा, पर चूंकि पटेल मंत्री थे, इसलिए किसी की मजाल नहीं थी कि वह विजय माल्या की तरफ़ उंगली भी उठा सके.

विजय माल्या, वैसे भी दोस्ती के ज़रिये सियासी गलियारों में अपनी धमक बनाने में माहिर हैं और किसे माध्यम बनाकर किसकी गर्दन तक पहुंचना है, यह भी उन्हें बख़ूबी आता है. वैसे तो विजय माल्या फैशन डिजाइनर रीना ढाका, भारत सुंदरी नेहा धूपिया, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, समीरा रेड्डी, बी ग्रेड हीरोइन पायल रोहतगी, क्लाउडिया सेस्सल, डिम्पल कपाड़िया, एम टीवी वीजे सोफी चौधरी जैसी अनगिनत बिंदास बालाओं के ख़ास दोस्तों में शुमार होते हैं. मगर इन सबसे इतर उनके बेहद नज़दीकी पारिवारिक संबंध रिलायंस समूह के मालिक मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी से भी हैं.

केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी के पिट्ठू माने जाते हैं. 2006 में जब मणिशंकर अय्यर को हटाकर मुरली देवड़ा को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया तो उनकी पीठ पर मुकेश अंबानी का ही हाथ था. इसलिए मुरली देवड़ा बतौर मंत्री भी अक्सर यह कहते रहे कि उनके लिए मुकेश अंबानी कितने अहम हैं. और तो और 2008 में जब अमेरिका में गैस की क़ीमत 3.70 डॉलर थी, तब भी रिलायंस भारत में गैस की क़ीमत 4.20 डॉलर लगा रहा था और मुरली देवड़ा न सिर्फ़ राष्ट्रीय धरोहर को कौड़ियों के मोल मुकेश अंबानी को बेच रहे थे, बल्कि उनके साथ आंध्र प्रदेश के त्रिमूला मंदिर में पूजा–अर्चना करने भी खुलेआम जा रहे थे.

लिहाज़ा मुकेश की पत्नी नीता अंबानी की सिफ़ारिश पर मुरली देवड़ा की भूमिका भी विजय माल्या के इस उधारी के खेल में ज़बरदस्त रही. देवड़ा के कहने पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नियम–क़ानूनों को परे रखकर घाटे में चल रही विजय माल्या की कंपनी को 600 करोड़ रुपये का तेल उधार दे दिया, जिससे सरकार और निगम को हज़ारों करोड़ रुपये का नुक़सान पहुंचा. फ़िलहाल केंद्रीय सतर्कता आयोग इस मामले की जांच कर रहा है. कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला से विजय माल्या की दोस्ती की वजह भी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ही हैं.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

विजय माल्या के हित में भाजपा के बड़े नेताओं का सौहार्द्र भी कमाल का है. माल्या की कंपनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय अस्तित्व में आई. एनडीए सरकार का वरदहस्त पाकर माल्या भारतीय बाज़ार पर छा गए. जब येदुरप्पा की सरकार पर संकट आया तो विजय माल्या ने अपना फ़र्ज़ निभाया और नितिन गडकरी के कहने पर माल्या, सुषमा स्वराज के साथ कर्नाटक में धन–बल के साथ डटे रहे. झारखंड में भी उनकी भूमिका भाजपा के लिए तारणहार की रही. जब राम जेठमलानी की राज्यसभा सीट फंसी, तब विजय माल्या का पैसा सर चढ़कर बोला. माल्या और जेठमलानी दोनों ही जीते, पर माल्या की जीत के नतीजे चौंकाने वाले रहे. उन्हें सभी पार्टियों से वोट मिले थे. हालांकि विजय माल्या ने इस सौदेबाज़ी में देहरादून की अपनी उस कोठी को भी बचा लिया, जिस पर 27 करोड़ रुपये का टैक्स बक़ाया था. इसमें उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने उनकी मदद की. देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित यह कोठी माल्या की मां लीला और उनकी दो बहनों के नाम थी.

वैसे तो विजय माल्या ने अपने पैसों और शानदार ख़ातिरदारी की बदौलत सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं को अपना मुरीद बना रखा है, पर भाजपा पर वह कुछ ज़्यादा मेहरबान दिखते हैं. विजय माल्या के दोबारा राज्यसभा सदस्य बनने के पीछे भाजपा का निर्विवाद समर्थन रहा है. विजय माल्या ने भी इस वफ़ा का सिला वक़्त–वक़्त पर ख़ूब दिया है. पिछले साल जब भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की नागपुर में शादी हुई तो ख़ास मेहमानों को लाने–ले जाने के लिए 30 चार्टर्ड प्लेन का इंतज़ाम किया गया था, जिनमें किंग फिशर एयर लाइंस के नाइन सीटर बिजनेस प्लेन मेहमानों की ख़िदमत के लिए ख़ास तौर पर मौजूद थे. मतलब यह कि विजय माल्या ने अपने इर्द–गिर्द सभी पार्टियों के नेताओं की ऐसी फ़ौज खड़ी कर रखी है, जो उनकी दुश्वारियों को दूर करने के लिए स्वतः ही तत्पर है. ऐसे में लाज़िमी है कि विजय माल्या अपनी मुसीबतों का ठीकरा बड़ी ही बेफ़िक्री से सरकार के सर फोड़ेंगे और सरकार स्वतः स्फूर्त उनका समाधान तलाशेगी. हो भी यही रहा है.

मनमोहन सरकार के एक ताक़तवर मंत्री नाराज़गी के अंदाज़ में कहते हैं कि यह मुक्त अर्थ–व्यवस्था का दौर है, तो फिर ऐसे में निजी क्षेत्र की कंपनी के घाटे की भरपाई सरकार बेल आउट पैकेज देकर क्यों करे? दूसरी बात यह कि विजय माल्या कोई भूखे नंगे व्यापारी तो हैं नहीं. दुनिया के सबसे बड़े शराब व्यापारियों में उनकी गिनती होती है. वह देशी और विदेशी खिलाड़ियों की ख़रीद पर अरबों–खरबों रुपये लुटा सकते हैं. चीयर गर्ल्स के ऐशो–आराम और राजनेताओं के लिए नए साल की पार्टी कर गोवा में वह करोड़ों रुपये दिखावे में ख़र्च कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं वह अपना घाटा अपनी दूसरी कंपनियों से पूरा करते हैं?

दरअसल, यह एक सोची–समझी योजना के तहत किया जा रहा है. जब तक विजय माल्या के सगे पटेल का राज था, तब तक माल्या ने ख़ूब ऐश किए. लेकिन अब जबकि सीएजी के पास विमानन मंत्रालय से संबंधित अनियमितता के कई मामले जांच के लिए हैं, तब माल्या पर भी उधारी चुकाने का दबाव है. अब ईंधन के दाम और एयरपोर्ट सरचार्ज हर क़ीमत पर हर तिमाही में क्लीयर करने के फ़रमान का उन्हें पालन करना ही है. ऐसी स्थिति में उनके पास सबसे आसान रास्ता यही है कि वह ख़ुद को दिवालिया घोषित करें और देनदारी से बच जाएं.

ruby@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 39
दिल्ली, 05 दिसंबर–11 दिसंबर 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226004
फोन : 0522–2204678, 9415005111

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)
सी–20, ट्रांस यमुना, एनएच–2, आगरा
फोन : 0526–4064901, 9837082462

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने होटल गणराज के बाजू में टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर–440012
फोन नं : 0712–2544988, 2549846

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

सरकार अन्ना की इस कमज़ोरी को भली-भांति जानती है. यही वजह है कि सरकार एक लुंजपुंज लोकपाल बनाकर अन्ना के आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है.

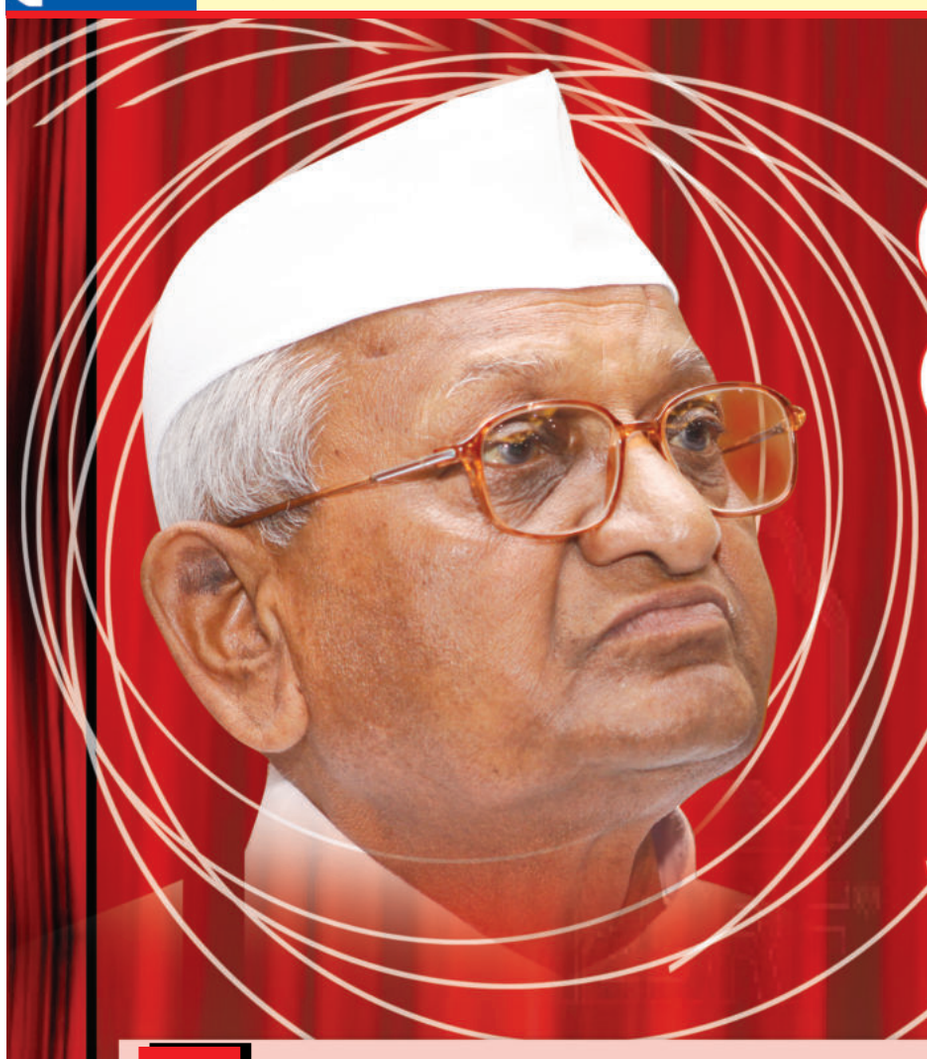

भंवर में अन्ना

कोई भी आंदोलन दलील से नहीं, बल्कि जनभावना से बड़ा बनता है. जन लोकपाल के मामले में भी यही बात लागू होती है. जनभावना के सहारे अन्ना और उनकी टीम सरकार पर भारी पड़ गई. लेकिन जब बात समझौते तक पहुंची, तब दलील के आगे जनभावना कमज़ोर पड़ गई. लोकपाल बिल पास कराने की जल्दबाज़ी में जो कुछ हुआ, उसमें आम आदमी कहीं नहीं है. उधर, अन्ना भी संशय की स्थिति में हैं. भारत भ्रमण और जन जागरण का उनका कार्यक्रम अब तक अधर में है. दूसरी ओर, वह ख़ुद लोकपाल बिल के भविष्य को लेकर दुविधा में हैं.

मनीष कुमार

एक सच्ची घटना है– कुत्ता क्यों मरा? पंजाब के सबसे क़द्दावर मुख्यमंत्री थे सरदार प्रताप सिंह कैरो. स्वतंत्रता सेनानी के साथ-साथ बड़े क़द्दावर नेता थे. एक बार दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे. उनके साथ उनके संसदीय सचिव देवीलाल भी थे. सरदार कैरो की गाड़ी तेज़ी से भाग रही थी कि एक कुत्ता बीच में आ गया. कुत्ते की मौत हो गई. सरदार कैरो ने थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रुकवाई. सड़क किनारे दो चक्कर लगाए और देवीलाल जी को बुलाया. उन्होंने पूछा, देवीलाल ये बताओ कुत्ता क्यों मरा? काफ़ी सोचने के बाद देवीलाल ने कहा कि कुत्ते तो मरते रहते हैं, यूं ही मर गया होगा. सरदार प्रताप सिंह कैरो ने फिर पूछा, बताओ कुत्ता क्यों मरा? देवीलाल जी ख़ामोश रहे, फिर कहा कि आप ही बताइये. तब सरदार प्रताप सिंह कैरो ने देवीलाल से कहा कि यह कुत्ता इसलिए मरा, क्योंकि यह फ़ैसला नहीं कर पाया कि सड़क के इस किनारे जाना है या उस किनारे. फ़ैसला न लेने की वजह से वह बीच में खड़ा रह गया. अगर इसने फ़ैसला कर लिया होता तो सड़क के इस किनारे या उस किनारे चला गया होता और बच जाता. फ़ैसला नहीं लेने की वजह से यह कुत्ता मारा गया. देवीलाल को राजनीति का मंत्र मिल गया. उन्होंने जीवन भर इसका पालन किया. वह कभी बीच में नहीं रहे. राजनीति में उन्होंने हमेशा फ़ैसला लिया. हमेशा इधर या उधर खड़े रहे. इसी सीख की वजह से वह देश के उपप्रधानमंत्री भी बने.

अन्ना की समस्या बिल्कुल यही है. वह फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें? इधर जाएं या उधर जाएं. वह कभी यात्रा पर निकलने की बात करते हैं, फिर बीच में यात्रा करने का इरादा छोड़ देते हैं. उन्होंने बड़े ज़ोर-शोर से यह ऐलान किया कि संसद सत्र में लोकपाल बिल पास नहीं हुआ तो फिर से आंदोलन करेंगे, फिर अचानक से चुप हो गए. अन्ना तय नहीं कर पा रहे हैं कि आंदोलन करना है या नहीं. सरकार का समर्थन करना है या नहीं. उत्तर प्रदेश में यात्रा करनी है या नहीं. अन्ना हजारे के फ़ैसला नहीं लेने की वजह से भ्रम की स्थिति बनती जा रही है. इस बीच अन्ना का बयान आया कि अगर सरकार मज़बूत लोकपाल बिल लेकर आ जाएगी तो वह कांग्रेस का समर्थन करेंगे और अगर लोकपाल बिल नहीं आया तो वह भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे. अन्ना अब तक यह फ़ैसला नहीं कर पाए हैं कि सरकार का समर्थन करना है या नहीं. अन्ना भंवर में हैं. अब तक उन्हें यह समझ में ही नहीं आया है कि सरकार लोकपाल के साथ क्या करना चाहती है, जबकि यह दिन के उजाले की तरह साफ़ है कि सरकार जन लोकपाल बिल लाने के पक्ष में नहीं है. सवाल यह उठता है कि इस तरह के बयान का क्या मतलब है? क्या अन्ना हजारे की नज़र में जनता की ताक़त का कोई महत्व नहीं है? क्या जनता की ताक़त में उनका भरोसा नहीं है? जो लोग अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल हुए वे न तो कांग्रेस के थे और न ही भारतीय जनता पार्टी के थे. यह आम जनता थी. सरकारी तंत्र में मौजूद भ्रष्टाचार से त्रस्त और नाराज़ जनता थी. तो अब यह कहना कि कांग्रेस का समर्थन कर दूंगा, का क्या मतलब है. क्या अन्ना को लगता है कि वह जिसका समर्थन कर देंगे, वह चुनाव जीत जाएगा या जिसका विरोध करेंगे वह चुनाव हार जाएगा. इससे तो दिग्विजय सिंह की यह दलील सही लगती है कि अन्ना और उनकी टीम को चुनाव लड़ना चाहिए.

जब से अन्ना हजारे ने जन लोकपाल के लिए आंदोलन शुरू किया है, तब से लेकर आज तक ऐसे कई मौक़े आए, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अन्ना ठोस फ़ैसले नहीं ले पाते हैं. आंदोलन की शुरुआत से ही सरकार ने यह साफ़ कर दिया कि अन्ना हजारे जिस तरह का लोकपाल बनाना चाहते हैं, वह उसके पक्ष में नहीं है. सरकार के पक्ष को जानते हुए भी जंतर-मंतर के आंदोलन के पहले और बाद में उन्होंने कई चिट्ठियां लिखीं, लेकिन कोई हल नहीं निकला. हल इसलिए नहीं निकला, क्योंकि सरकार अपनी ज़िद पर अड़ी थी. जंतर-मंतर के आंदोलन के बाद संयुक्त बैठक में जो हुआ उससे भी यह साफ़ हो गया कि सरकार टाल-मटोल कर रही है. फिर भी अन्ना हजारे और उनकी टीम यह ठोस फ़ैसला नहीं कर सकी कि सरकार के ख़िलाफ़ जाना है या नहीं. इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार ने अपनी मनमानी की. मजबूर होकर अन्ना को रामलीला मैदान में अनशन करना पड़ा. इस आंदोलन के दौरान सरकार ने उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया. आंदोलन के लिए जगह देने में कई रुकावटें खड़ी कीं. इतना सबकुछ होने के बावजूद अन्ना यह फ़ैसला नहीं कर सके कि सरकार से किस तरह से लड़ना है. इसका नतीजा यह हुआ कि तेरह दिनों तक चला अन्ना का अनशन सरकार के साथ बातचीत में उलझ कर रह गया.

अन्ना हजारे को यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि रामलीला मैदान के अनशन से वह कुछ हासिल नहीं कर पाए. इस बात पर ग़ौर करने की ज़रूरत है कि रामलीला मैदान के अनशन से पहले जो जन लोकपाल बिल की स्थिति थी और जो स्थिति आज है, उसमें कोई अंतर नहीं है. अन्ना हजारे को देश भर में जो समर्थन मिला, उसका फ़ायदा टीम अन्ना नहीं उठा सकी. या यूं कहें कि इस अपार जन समर्थन की ताक़त को आंकने में अन्ना हजारे से चूक हो गई. अब हालत यह है कि सरकार वैसा ही बिल लेकर आ रही है, जैसा वह पहले लाना चाहती थी. सरकार ने जो मसौदा तैयार किया है, उसमें प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे से बाहर हैं. सरकारी लोकपाल बिल में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा और केंद्रीय सतर्कता आयोग को लोकपाल से बाहर रखा गया है. सरकार ने निचले स्तर के अधिकारियों को भी लोकपाल के दायरे से बाहर कर दिया. न्यायपालिका में होने वाला भ्रष्टाचार भी लोकपाल के दायरे में नहीं है. सरकार तो अपनी जगह से हिली नहीं, वह जैसा लोकपाल लाने के लिए पहले से तैयार थी, वैसा ही बिल तैयार किया है. तो अब सवाल पूछना लाज़िमी है कि टीम अन्ना को अनशन से क्या हासिल हुआ. प्रधानमंत्री से पटवारी तक लोकपाल के दायरे में हों, यह मांग कहां ग़ायब हो गई. प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में हों? इस पर अनशन ख़त्म करने से पहले समझौता क्यों नहीं हुआ? साधारण सा सवाल है. सरकार का जो लोकपाल बिल है, वह क्या जन लोकपाल बिल है. इस सवाल का साधारण सा जवाब है ही नहीं. इसका मतलब यही है कि अन्ना का पिछला आंदोलन सफल नहीं रहा. अन्ना ने पिछला आंदोलन शुरू किया था, तो यह नारा दिया कि जन लोकपाल बिल पास करो. लेकिन तेरह दिनों के बाद टीम अन्ना ने जन लोकपाल बिल को छोड़ दिया और सिर्फ़ तीन मांगों तक सीमित रहकर अनशन तोड़ दिया. इन तीन मांगों में प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, सीबीआई, सीवीसी और निचले स्तर के अधिकारी कहां हैं? मामला संसद में चला गया. संसद में बहस हुई, लेकिन किस क़ानून के तहत हुई, यह किसी को पता नहीं है. इस बहस की क़ानून की नज़र में क्या प्रासंगिकता और मान्यता है? राजनीतिक दलों ने इसे सेंस ऑफ द हाउस बताया. लोकसभा की प्रक्रिया के मुताबिक़ इस प्रस्ताव को स्पीकर के समक्ष पेश करना था. क्या इस प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने रखा? नहीं, इसे प्रणव मुखर्जी ने रखा. लोकसभा में क्या इन मांगों पर मतदान हुआ? नहीं, सरकार ने पूरी बहस को स्टैंडिग कमेटी के पास भेज दिया. हैरानी की बात तो यह है कि इससे पहले भी अन्ना हजारे स्टैंडिंग कमेटी में अपनी बात कह चुके थे. एक सांसद ने तो जन लोकपाल बिल को ही स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया. मतलब यह है कि जो सुझाव अनशन के बाद स्टैंडिंग कमेटी को दिया गया, वह स्टैंडिंग कमेटी के पास पहले से ही था. इससे साफ़ पता चलता है कि टीम अन्ना से चूक हुई है. इसे भी स्वीकार करने की ज़रूरत है.

जिस वक़्त अन्ना हजारे रामलीला में अनशन कर रहे थे, उस समय देश के हर कोने में अनशन चल रहा था. अन्ना के समर्थन में देश में कहां-कहां आंदोलन हुए, यह तो टीम अन्ना को भी पता नहीं होगा. भारतीय नागरिकों ने तो अमेरिका में भी अनशन किया. गांवों और क़स्बों में जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने तो आंदोलन से पहले अन्ना का नाम तक नहीं सुना था. फिर भी आंदोलन में शामिल हुए. उनकी नाराज़गी सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ थी. महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली आदि समस्याओं से जूझ रहे लोगों को लगा कि इस आंदोलन की वजह से बदलाव आएगा. सबकुछ बदल जाएगा. यही वजह है कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें, अमीर-ग़रीब, हर जाति और वर्ग के लोगों ने अन्ना हजारे को समर्थन दिया. हर राजनीतिक दल के समर्थकों के साथ-साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अन्ना के आंदोलन में थे. ये लोग सिर्फ़ जन लोकपाल के लिए अन्ना को समर्थन नहीं दे रहे थे. अन्ना में लोग गांधी देख रहे थे, जो भारत की तस्वीर बदलने की आशा जगा रहा था. अन्ना के पास यह एक मौक़ा था कि वह इस आंदोलन को सिर्फ़ लोकपाल की बजाय व्यवस्था परिवर्तन और सरकारी तंत्र के तौर-तरीक़ों को बदलने का आंदोलन बना सकते थे. लेकिन अन्ना ने लोगों को निराश किया. अनशन के बाद हॉस्पिटल और वहां से वापस अपने गांव जाकर बैठ गए. अगर अन्ना देश की यात्रा पर निकल जाते. हर राज्य में निस्वार्थ रूप से आंदोलन करने वाले युवाओं और जनता से मिलते तो आज सरकार को एक लुंजपुंज लोकपाल क़ानून बनाने की हिम्मत नहीं पड़ती. फिर कभी अन्ना को आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ती तो उनकी एक आवाज़ पर देश के हर कोने में आंदोलन शुरू हो जाते. वह लोगों की इस ताक़त को समझ नहीं पाए. वह यह नहीं समझ पाए कि लोगों की आकांक्षाओं और सपनों से जुड़ने के बाद अपनी मर्ज़ी नहीं चलती. जनता की भावनाओं के साथ उन्हें चलना पड़ता है, लेकिन अन्ना हजारे ने ठीक उल्टा किया. जिस तरह सरकार लोगों की भावनाओं का मज़ाक़ उड़ा रही है, वैसा ही अन्ना हजारे कर रहे हैं.

सरकार अन्ना की इस कमज़ोरी को भली-भांति जानती है. यही वजह है कि सरकार एक लुंजपुंज लोकपाल बनाकर अन्ना के आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है. सरकारी बिल में जन लोकपाल बिल के कई मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है. बिल में सिर्फ़ उन्हीं मुद्दों को शामिल किया गया है, जिससे सरकार टीवी चैनलों और संसद में बहस के दौरान विपक्ष के सवालों का गोलमोल जवाब दे सके. सरकार जानती है कि लोकपाल बिल पेश करने के साथ ही टीम अन्ना का समर्थन आधा हो जाएगा. अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए सरकार के साथ अन्ना हजारे भी ज़िम्मेदार होंगे. सरकार ने टीम अन्ना से निपटने के लिए दूसरे रास्ते भी खोल दिए हैं. सरकार उनके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करना चाहती है. पहले कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने अन्ना हजारे को भ्रष्ट बताया. शशि भूषण और प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ सीडी निकल जाती है. अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाया जाता है और किरण बेदी को हवाई सफ़र के टिकट के लिए ज़लील किया जाता है. सरकार हर तरीक़े से अन्ना हजारे और टीम अन्ना के सदस्यों को परेशान कर रही है. इसके बावजूद टीम अन्ना के सदस्य टेलीविजन कैमरे को देखते ही भ्रम फैलाने वाले बयान दे देते हैं. वे मीडिया के दबाव में आ जाते हैं. उन बातों पर ध्यान देने लग जाते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है. एक तरफ़ सरकार एक लुंजपुंज लोकपाल क़ानून ला रही है, तो दूसरी तरफ़ अन्ना हजारे और उनकी टीम ऐसे कामों में लगी है, जिसकी ज़रूरत नहीं है. यह समय सरकार पर दबाव देने का है तथा ऐसी योजनाएं बनाने का है कि अगर सरकार अपनी बात पर अडिग रही तो क्या करना होगा. हैरानी तो इस बात से होती है कि अन्ना हजारे अपनी टीम में पारदर्शिता लाने और संगठन में प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए समाज के और लोगों को भी शामिल करने में समय नष्ट कर रहे हैं. लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि अगर सरकार मज़बूत लोकपाल क़ानून नहीं लाई, तब क्या होगा. क्या फिर से देश में पहले जैसा आंदोलन खड़ा हो सकेगा? ऐसे महौल में राजनीति और चुनावों पर अन्ना भी चौंकाने वाले बयान दे देते हैं. सरकार देश को गुमराह कर रही है, लेकिन टीम अन्ना भी इसमें पीछे नहीं है. लोकपाल के मुद्दे पर सरकार ने पब्लिक ओपिनियन यानी जनमत का अनादर किया है. संसद में लोकपाल पर हुई चर्चा के दौरान राजनीतिक दलों और सरकार ने लोगों की भावनाओं के साथ मज़ाक़ किया है. सरकार के इस अपराध में अन्ना भी शामिल हैं. प्रजातंत्र में लोकमत सर्वोपरि होता है. देश की जनता भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक कड़ा क़ानून चाहती है. यही जनमत है. देश की जनता घोटालों, महंगाई, भ्रष्टाचार, कालाधन, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और रोज़गार की कमी से त्रस्त हो चुकी है. अन्ना ने लोगों में आशा जगाई, इसलिए लोग अन्ना के आंदोलन से जुड़े. देश की आर्थिक स्थिति ख़राब हो रही है. राजनीति का भी वही हाल है. उत्तर प्रदेश में चुनाव है. कुछ लोग यह मान रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव भी ज़्यादा दूर नहीं है. यह वक़्त फ़ैसला लेने का है. अन्ना को यह फ़ैसला लेना है कि भ्रष्टाचार और मज़बूत लोकपाल की लड़ाई में वह कहां खड़े हैं. कुत्ता क्यों मरा-के ज़रिए प्रताप सिंह कैरो ने जो सीख देवीलाल को दी, वही सीख अन्ना हजारे को लेने की ज़रूरत है.

अन्ना हजारे को यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि रामलीला मैदान के अनशन से वह कुछ हासिल नहीं कर पाए. इस बात पर ग़ौर करने की ज़रूरत है कि रामलीला मैदान के अनशन से पहले जो जन लोकपाल बिल की स्थिति थी और जो स्थिति आज है, उसमें कोई अंतर नहीं है. अन्ना हजारे को देश भर में जो समर्थन मिला, उसका फ़ायदा टीम अन्ना नहीं उठा सकी. या यूं कहें कि इस अपार जन समर्थन की ताक़त को आंकने में अन्ना हजारे से चूक हो गई.

आंदोलन की शुरुआत से ही सरकार ने यह साफ़ कर दिया कि अन्ना हजारे जिस तरह का लोकपाल बनाना चाहते हैं, वह उसके पक्ष में नहीं है. सरकार के पक्ष को जानते हुए भी जंतर-मंतर के आंदोलन के पहले और बाद में उन्होंने कई चिट्ठियां लिखीं, लेकिन कोई हल नहीं निकला. हल इसलिए नहीं निकला, क्योंकि सरकार अपनी ज़िद पर अड़ी थी. जंतर-मंतर के आंदोलन के बाद संयुक्त बैठक में जो हुआ उससे भी यह साफ़ हो गया कि सरकार टाल-मटोल कर रही है.

manish@chauthiduniya.com

बुंदेलखंड में लगातार टूटते पुल, पलायन और बेरोज़गारी से त्रस्त जनता कराह रही है. ऐसे में मायावती की बुंदेलखंड राज्य का सपना दिखाकर वोटों को अपनी झोली में झटकने की कोशिश कितनी कामयाब होती है.

बसपा में कलह

सुरेंद्र अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुर्ख़ियों में है. वोटों की महाभारत में सबकी नज़र बुंदेली भूमि पर है. वर्ष 1987 के राठ विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी सूबे में पहली बार दूसरे नंबर पर आई थी. यहीं से बुंदेलखंड में बसपा के पैर जमने शुरू हुए और आज वह सत्ता में है. लेकिन अब बसपा में सबकुछ ठीक-ठाक नहीं है. इसी बात पर नज़र रखते हुए राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश रण विजय का रास्ता बुंदेलखंड से चुना है.

लोकसभा के चुनाव में एक सीट जीतने के साथ दूसरी सीट पर नंबर दो की पोजीशन पाने वाली कांग्रेस का सीधा मुक़ाबला बसपा से है. झांसी गढ़ में बसपा से मात खाने के बाद इस बार कांग्रेस ने कभी बसपा से विधायक रहे बृजेंद्र व्यास उर्फ़ डमडम व्यास को प्रत्याशी बनाया है, तो ललितपुर की मेहरौनी विधानसभा क्षेत्र से बसपाई रहे रमेश खटीक को मैदान में उतारा है. बसपा भी पीछे नहीं है. उसने झांसी से कांग्रेसी रहे सीताराम कुशवाहा और गरौठा से पालीवाल को प्रत्याशी बनाया है. बुंदेलखंड के सबसे ताक़तवर बहुविभागीय मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी के सगे भाई हसनउद्दीन ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है. यही हालत बुंदेलखंड के कई इलाक़ों में है. 2007 के चुनाव में गयाचरण दिनकर और बाबूलाल ने अपनी हार का ज़िम्मेदार दद्दू प्रसाद और नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी को माना था. शह-मात का खेल खुलेआम चल रहा है, जिसके कारण प्रदेश सरकार के एक मंत्री समाचार-पत्रों में एक प्रभारी के ख़िलाफ़ खबरें छपवा रहे हैं, तो बांदा और लखनऊ से प्रकाशित समाचार-पत्रों में नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी और बाबू सिंह कुशवाहा के विरुद्ध आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है. बुंदेलखंड में लगातार टूटते पुल, पलायन और बेरोज़गारी से त्रस्त जनता कराह रही है. ऐसे में मायावती की बुंदेलखंड राज्य का सपना दिखाकर वोटों को अपनी झोली में झटकने की कोशिश कितनी कामयाब होती है. यह कहना कठिन है, क्योंकि उपेक्षा का दंश सहते मायावती के क़रीबी रहे दीवान रघुनाथ सिंह लोधी, बाबू रामदीन, के आर शशि का कहीं अता-पता नहीं है. हालांकि नसीममुद्दीन सिद्दीक़ी, बाबूलाल, बाबू सिंह कुशवाहा, गयाचरण दिनकर, सेवाराम, विशंभर प्रसाद निशाद, मास्टर प्रताप सिंह, बृजेंद्र व्यास, ब्रजलाल खाबरी, तिलक अहिरवार, पी.एन. भास्कर आदि राजनीति में पैठ बना गए, लेकिन बाबूराम दीन, केआर शशि, विशंभर प्रसाद निशाद, मास्टर प्रताप सिंह, बृजेंद्र व्यास आदि किनारा कर चुके हैं. ग्रामीण विकास मंत्री दद्दू प्रसाद सवालों के घेरे में हैं. लोकायुक्त के सामने आय से अधिक संपत्ति, पद के दुरुपयोग तथा सरकारी एवं निजी ज़मीनों पर क़ब्ज़ा करने के आरोपों की शिकायत पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, बादशाह सिंह के साथ-साथ वर्तमान मंत्री दद्दू प्रसाद, रतनलाल अहिरवार के विरुद्ध की गई है. इस संदर्भ में जांच चल रही है. बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर बृजलाल खाबरी की कार्यप्रणाली को लेकर एक काबीना मंत्री के इशारे पर आरोपों का दौर शुरू होने पर उनके निकट सूत्र सवाल करते हैं कि गयाचरण दिनकर की हार में किसने भूमिका अदा की है. इसका टेप सामने आ जाएगा तो बड़ों-बड़ों की छुट्टी हो जाएगी. बांदा संसदीय क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी भैरो प्रसाद मिश्र की हार के पीछे कौन था? दद्दू प्रसाद को क्षेत्र से किनारा कराने के लिए गोरखपुर मंडल से लोकसभा प्रत्याशी बनाने के साथ-साथ उनकी पत्नी हीरा देवी को मानिकपुर क्षेत्र से विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया था. बाद में मुख्यमंत्री द्वारा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को सामान्य सीट से न लड़ाने की नीति के तहत हीरा देवी का टिकट काट दिया गया. दद्दू प्रसाद अपने विरुद्ध कमला द्वारा अस्मत लूटने का आरोप लगने के साथ-साथ आय से अधिक संपत्ति जैसे अनेक मामलों को एक षडयंत्र का हिस्सा मानते हैं. कांग्रेस से ललितपुर विधानसभा सीट से वीरेंद्र बुंदेला अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, फिर भी उन्हें जिताने को बसपा से कमज़ोर प्रत्याशी रमेश कुशवाहा को चुनाव में खड़ा करने का आरोप निराधार है. झांसी विधानसभा सीट से डमडम व्यास को बसपा से किसने निकलवाया था. अब डमडम व्यास कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो इसमें खाबरी का क्या दोष है? सीटिंग विधायक कैलाश साहू का टिकट काटकर बसपा ने सीताराम कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित किया है. गरौठा विधानसभा सीट से कांग्रेस के रणजीत सिंह जूदेव के मुक़ाबले बसपा ने संजीव पालीवाल को प्रत्याशी बनाया है. माधवगढ़ सीट से कांग्रेस के विनोद चतुर्वेदी को जिताने को सीटिंग विधायक हरिओम उपाध्यक्ष को हराने की रणनीति बनाई जा रही है. हमीरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी केशव शिवहरे के मुक़ाबले में लोकमंच से घोषित फ़तेह ख़ान को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है. बांदा से मंत्री नसीमुद्दीन के साले मुमताज़ अली के साथ ठेकेदारी करने वाले दिनेश शुक्ल को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है. कानपुर देहात के बाशिंदे और प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री भगवती सागर को पुन: मऊरानीपुर से उम्मीदवार बनाने पर पार्टी में तक़रार हो गई है. चित्रकूट से बसपा से निष्कासित पूर्व लोकसभा सचिव राजेंद्र कुशवाहा ने कमला मामले में मंत्री दद्दू प्रसाद के प्रति उकसाने व पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के जोनल कोऑर्डिनेटर बृजलाल खाबरी के आरोप की निंदा की है. उन्होंने कहा है कि मामले में समझौता कराने पर असमर्थता जताने की स्थिति में उन्हें पार्टी से निकाला गया है. दलितों को अपमानित करने वाले पाल को पाल भाईचारा समाज का कोऑर्डिनेटर बना दिया गया, जबकि उन्हें खाबरी के ज़रिये पार्टी से निकाला जा रहा है. इससे मंत्री दद्दू का दोहरा चरित्र सामने आता है. भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग में लोकायुक्त की जांच में फंसकर श्रम मंत्री का पद गंवाने वाले बादशाह सिंह विधानसभा का आगामी चुनाव लड़ेंगे. मुख्यमंत्री मायावती ने बादशाह सिंह को विधानसभा का टिकट देने से मना कर दिया था. वह विधानसभा का पिछला चुनाव हमीरपुर ज़िले की मौदहा सीट से जीते थे. सिंह के प्रत्याशी होने की घोषणा से बुंदेलखंड में बसपा के समीकरण गड़बड़ होने की आशंका पैदा हो गई है. लगभग ढाई दशक में राजनीति की बुलंदियों को छू लेने वाले बुंदेलखंड के क़द्दावर नेता बादशाह सिंह ने इंसाफ़ सेना नामक संगठन बनाया था और इसके बैनर तले ही बुंदेलखंड के अलग राज्य के लिए संघर्ष करने का भी ऐलान किया था. वहीं सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले बादशाह सिंह अब राजनीति में लौट आए हैं. उन्होंने कहा कि वह अपने विरोधियों को चुनाव में सबक़ सिखाएंगे. परिसीमन के बाद मौदहा सीट ख़त्म कर दी गई है. कुशवाहा समाज के लोगों ने बाबू सिंह कुशवाहा के मंत्री पद से हटते ही अब इसी बसपा को धोखेबाज़ बताना शुरू कर दिया है. पद छिनने से बौखलाए लोगों ने कुशवाहा समुदाय के चिंतन शिविर के माध्यम से अब इसी थाली को तोड़ने का कुचक्र शुरू किया है, जिसमें वह भरपेट खाना खाने लायक़ हुए हैं. हाल में चित्रकूट ज़िले में संपन्न कुशवाहा समाज के चिंतन शिविर में कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष राकेश मौर्य, धनीराम बलदानी एक तरफ़ तो पूरे कुशवाहा समाज को बसपा का एकमुश्त वोट बैंक बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सम्मेलन के ज़रिये पार्टी और उसकी मुखिया दोनों को चुनौती दे रहे हैं.

महरोनी, ललितपुर, झांसी, बबीना, मऊरानीपुर, कोच, माधवगढ़, कालपी, नरेनी, मानिकपुर, कर्वी, चरखारी, महोबा, मोदहा, राठ सहित बुंदेलखंड की 21 में से 15 पर बसपा क़ाबिज़ है, जबकि चार पर समाजवादी पार्टी तथा दो पर कांग्रेस क़ाबिज़ है. कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी द्वारा बुंदेलखंड के विकास के लिए विशेष पहल के तहत दिलाया गया पैकेज और इस पैकेज की बंदरबांट को चुनावी मुद्दा बनने के कारण बुंदेलखंड में आमने-सामने की लड़ाई कांग्रेस और बसपा की है. बसपा द्वारा प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव विधानसभा में लाने के बाद बुंदेलखंड राज्य का विरोध सपा के लिए ख़तरनाक साबित होने वाला है. भाजपा की बुंदेलखंड राज्य के मामले में चुप्पी के कारण ही सूपड़ा साफ़ हो चुका है. नए परिसीमन में 21 में 19 विधानसभा सीटें रह गई हैं. देखना यह है कि आपसी रार में डूबी बसपा चुनावी संग्राम में अपने कितने गढ़ खोती है और कितने नए गढ़ों पर क़ब्ज़ा करती है.

feedback@chauthiduniya.com

नसीमुद्दीन सिद्दीक़ी

ब्रजलाल खाबरी

दद्दू प्रसाद

हरीओम उपाध्याय

बाबू सिंह कुशवाहा

बादशाह सिंह

रतन लाल अहिरवार

कोड़ा प्रकरण पर सियासत गरमाई

प्रशांत कुमार झा

झारखंड के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में राज्य के पूर्व मंत्री मधु कोड़ा के साथ हुए हादसे के बाद सूबे में राजनीतिक हलचल तेज़ हो गई है. कभी अपने विधायकों का समर्थन देकर कोड़ा को मुख्यमंत्री का ताज पहनाने वाली कांग्रेस का भी पुराना कोड़ा प्रेम जाग उठा. बस फिर क्या था, कोड़ा प्रकरण पर राज्य के कांग्रेसी नेता सत्तासीन सरकार की खिंचाई करते नज़र आए. कोड़ा की पिटाई की जानकारी मिलते ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय भी भावुक हो गए. सहाय, राजेंद्र प्रसाद सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता देवकांत धान व सिसई विधायक गीता उरांव ने रिम्स पहुंचकर घायल मधु कोड़ा का हाल-चाल पूछा. नेताओं ने घटना पर अफ़सोस जताते हुए सरकार की कुव्यवस्था पर चोट की. अगले ही दिन पर्यटन मंत्री के नेतृत्व में राज्य के विपक्षी दलों के गिने-चुने विधायकों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन का आशय मामले की निष्पक्ष जांच कराना व जेल की व्यवस्था को दुरुस्त कराना था. वहीं मधु कोड़ा ने भी राज्यपाल को अपनी पत्नी गीता कोड़ा के माध्यम से एक ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जेल में मेरी जान को ख़तरा है. मुझ पर व मेरे साथ जेल में बंद भूतपूर्व मंत्रियों पर हमला एक साज़िश थी. कुछ लोग चाहते हैं कि जनता के लिए जो आवाज़ मैं उठा रहा हूं, वह सदा के लिए शांत हो जाए.

सूत्रों के हवाले से यह भी ख़बर आई कि एक हत्या के आरोप में जेल में बंद, खिजरी विधायक सावना लकड़ा (जो मधु कोड़ा के साथ अनशन में भी शामिल थे) ने डीआईजी के समक्ष यह बयान दिया कि अनशन के दौरान आम क़ैदियों के साथ हमलोगों की मुठभेड़ हो गई थी. गाली-गलौज के साथ हाथापाई शुरू हो गई. बाद में सैप के जवानों ने लाठी भांजते हुए, हम सभी वीआईपी क़ैदियों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया. तभी मधु कोड़ा गिर गए और उन्हें चोट लग गई.

कांग्रेस ने मधु कोड़ा प्रकरण के विरोध में राजभवन के समक्ष धरना दिया. इस धरने में सुबोधकांत सहाय, गीताश्री उरांव, गीता कोड़ा व मेमन एक्का ने एक सुर में अर्जुन मुंडा सरकार को बर्ख़ास्त करने की मांग की. झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने भी मधु कोड़ा मामले में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का इस्तीफ़ा मांगा. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मधु कोड़ा पर हुए हमले के विरोध में रांची में जगह-जगह मुख्यमंत्री के पुतले फूंके. वहीं मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच रिटायर्ड जस्टिस से करवाने की बात कही है.

बहरहाल, यह पूरा प्रकरण कई सवालों को जन्म दे रहा है. कोड़ा 4000 करोड़ रुपये के घोटाले एवं 180 करोड़ की अवैध संपत्ति रखने के आरोपी हैं. उनके ख़िलाफ़ चल रही जांच में यह बात भी सामने आई कि 2009 में हुए आम चुनाव में उन्होंने वोट ख़रीदे थे. 10 लाख रुपये की तो केवल मोटरसाइकिलें, चुनाव-प्रचार में बंटने वाले पंपलेट की तरह कोड़ा ने बांटीं. संभव है कि उपरोक्त आरोपों में पूर्ण सत्यता न हो. लेकिन धुंआ तो वहीं से उठता है, जहां आग होती है. कई संगीन आरोपों से घिरने से झारखंड में कोड़ा को पंसद करने वाले लोगों की संख्या नगण्य हो गई है. जहां तक जनाधार की बात है, तो कोड़ा की पार्टी जयभारत समानता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन पर हुए हमले के विरोध में पूरा कोल्हान क्षेत्र बंद रखने का ऐलान किया था. इस बंद का कोई असर इस क्षेत्र में देखने को नहीं मिला. जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां से मधु कोड़ा की पत्नी विधायक हैं, वहां भी बंद पूरी तरह निष्फल रहा. ऐसे में मधु कोड़ा के राजनीतिक भविष्य का अंदाज़ा आसानी से लग सकता है.

यह बात स्मरणीय है कि दो वर्ष पूर्व जब कोड़ा के घर पर प्रवर्तन निदेशालय व निगरानी का छापा पड़ा था, तो हज़ारों करोड़ रुपये के घोटाले का मामला सार्वजनिक हुआ. इस ख़ुलासे के बाद पूरे देश में सनसनी मच गई थी कि क्या मुख्यमंत्री इतना बड़ा घोटाला कर सकता है? इसी दरम्यान कांग्रेस पर भी चौतरफ़ा वार होने लगे कि उसकी सरपरस्ती में ही कौड़ा ने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया. लेकिन कांग्रेस ने इससे पल्ला झाड़ते हुए कहा कि कोड़ा सरकार के गठन में उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी. उन्होंने कोड़ा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया. कोड़ा जब मुख्यमंत्री थे, तब राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर था. झारखंड लोक सेवा आयोग ने रेवड़ियों की तरह नौकरियां बांटीं. मेधावी छात्रों की जगह रसूख व पैसे वाले छात्र बीडीओ व सीओ के पद को सुशोभित करने में सफल हुए. यह बात निगरानी जांच में सामने आ चुकी है. सरकार के कई मंत्रियों ने भी भ्रष्टाचार की बहती गंगा में जमकर डुबकियां लगाईं. यही कारण है कि कोड़ा की सरकार के आधा दर्जन मंत्री किसी न किसी घोटाले में, अभी उनके साथ ही जेल में दिन काट रहे हैं. कोड़ा के कथित दलाल विनोद सिन्हा भी उन्हीं के साथ जेल में हैं. कोड़ा के पैसों को विदेश में निवेश करने वाला हवाला कारोबारी संजय चौधरी भी दुबई में इंटरपोल के हत्थे चढ़ गया है. ऐसे में कांग्रेस का कोड़ा की मदद के लिए आगे आना क्या साबित करता है. यह बात सर्वमान्य है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री का जेल में घायल होना कोई मामूली बात नहीं है. यह घटना जेल व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाती है. लेकिन सरकार ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का फ़ैसला लिया है. केंद्र सरकार ने भी मामले की पूरी जानकारी राज्य सरकार से तलब की है. राज्य सरकार दोषियों को दंडित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है. इसके बाद भी सरकार को बर्ख़ास्त करने की मांग हैरान करने वाली है. सवाल यह भी उठता है कि कोड़ा प्रकरण के अलावा क्या विपक्ष के पास, सरकार पर हल्ला बोलने के लिए कोई दूसरा मुद्दा नहीं था. झारखंड में मुद्दों की कमी नहीं है. 15 नवंबर, 2011 को झारखंड के गठन को 11 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी राज्य के 56 प्रतिशत गांवों में सड़कें नहीं है. बिजली के अभाव में 68 प्रतिशत गांववासी अंधकार में रहने को विवश हैं. शिक्षा का हाल यह है कि सूबे के 24 ज़िलों में से 12 ज़िलों में साक्षरता दर 50 प्रतिशत से भी कम है. इसके अतिरिक्त झारखंड की ग़रीबी लगातार बढ़ रही है, वहीं माननीयों के वेतन में निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है. इस बारे में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है. राज्य में नक्सलवाद बेलगाम होता जा रहा है. ऐसा कोई भी माह नहीं होता, जिसमें नक्सलियों द्वारा पुलिसकर्मियों व निरीह नागरिकों की हत्या के मामले सामने न आते हों. इन आतंकवादियों के आगे सरकार बेबस नज़र आती है. तब सरकार को बर्ख़ास्त करने की मांग क्यों नहीं की जाती है? सवाल, सरकार को हटाने की मांग करने या नहीं करने का नहीं है. प्रश्न यह है कि कोड़ा के दर्द से परेशान होने वाले नेताओं को क्या झारखंड की अवाम का दर्द महसूस नहीं होता है. वीआईपी कोड़ा के लिए तो नेतागण धरना-प्रदर्शन व अनशन करते हैं. झारखंड की जनता के लिए ऐसा क्यों नहीं हो पाता है. राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ कहते हैं कि जिस समय कोड़ा का मुद्दा उछला, उसी समय मुख्यमंत्री झारखंड की बदहाल सड़कों का जायज़ा लेने के लिए सड़क-यात्रा पर निकलने वाले थे. इस यात्रा की महत्ता कम करने के लिए ही विपक्ष (कांग्रेस) ने कोड़ा मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है.

मुंडा की सड़क यात्रा के समानांतर कोई कार्यक्रम शुरू कर कांग्रेस जनता में अपनी अलग छवि बना सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने कोड़ा का हितैषी बनकर कुछ दूसरी ही तस्वीर पेश कर दी. देशव्यापी स्तर पर लोकपाल को लाने के प्रस्ताव के मुद्दे पर कांग्रेस ने अपने प्रति जनता के रुख़ को पहले ही देखा है. ऐसे में आम आदमी के दुख-दर्द को बांटने की जगह कोड़ा के दर्द में कराह कर झारखंड कांग्रेस किसका कल्याण करना चाहती है?

feedback@chauthiduniya.com

कार्टून के ज़रिये रथ यात्रा का विरोध यहीं नहीं थमा. भोपाल तक इस कार्टून की धूम मचती रही. भोपाल में पहले से ही कई जगहों पर यह कार्टून चर्चा का विषय बन चुका था.

बिहार

ज़मीन आवंटन के नाम पर

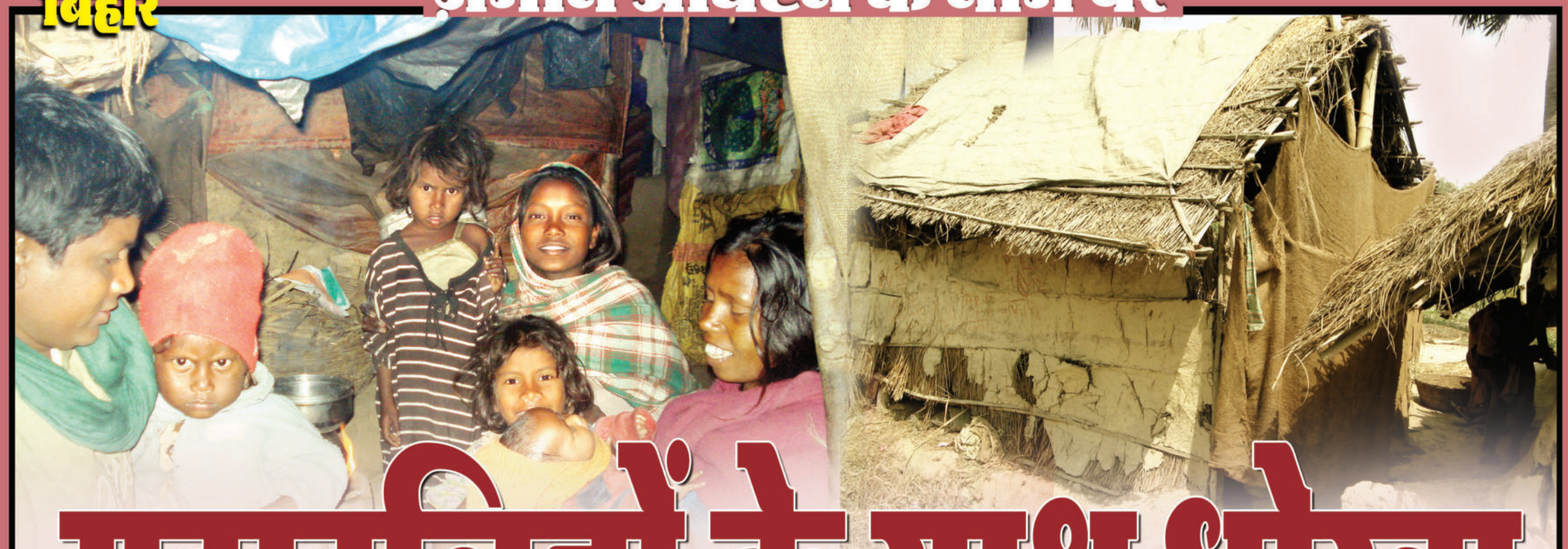

महादलितों के साथ धोखा

महादलितों के सिर पर छत देने के मामले में सरकार द्वारा छलावा किया जा रहा है. भूमिहीन महादलितों को घर बनाने के लिए ज़मीन देने की सरकार की घोषणा हवा-हवाई होने लगी है. ज़मीन देने की बजाय 20 हज़ार रुपये हाथ में थमाने की क़वायद तेज़ कर दी गई है. मात्र 20 हज़ार रुपये में ज़मीन मिलती ही नहीं है. वहीं सरकार द्वारा बार-बार भूमि में कटौती करने को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

आलोक कुमार

सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 6 साल के शासनकाल में महादलित आयोग क गठन किया. उसी तरह भूमि सुधार आयोग का भी गठन किया. इन आयोगों के अध्यक्षों द्वारा सरकार को भूमिहीन महादलितों को आवासीय भूमि देने की अनुशंसा की गई थी. महादलित आयोग के पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ ऋषि ने 12 से 15 डिसमिल ज़मीन देने की सिफ़ारिश की थी. वहीं भूमि सुधार आयोग के अध्यक्ष देवव्रत बंधोपाध्याय ने 10 डिसमिल ज़मीन देने की सिफ़ारिश की. इन दोनों अध्यक्षों की सिफ़ारिशों को सरकार ने फ्रीज कर दिया. राज्य सरकार द्वारा बिहार प्रिविलेज्ड होमस्टिड टिनेंसी एक्ट, 1947 बनाया गया है. निर्मित अधिनियम के मुताबिक़, आवासीय भूमिहीनों को 12.5 डिसमिल ज़मीन देनी है. इस अधिनियम में कई बार संशोधन किया गया. कालातंर में इसमें 2.5 डिसमिल ज़मीन घटाकर 10 डिसमिल ज़मीन कर दी गई. इसके बाद मनमौजी राज्य सरकार ने एकाएक 6 डिसमिल ज़मीन घटाकर आवासीय भूमिहीनों को 4 डिसमिल ज़मीन देने लगी. सरकार ने आवासीय भूमिहीनों को दी जाने वाली ज़मीन की हिस्सेदारी में 1 डिसमिल ज़मीन कटौती कर 3 डिसमिल ज़मीन कर दी. अभी आवासीय भूमिहीनों को 3 डिसमिल ज़मीन दी जा रही है. अब तो मौजूदा सरकार 3 डिसमिल ज़मीन देने में कटौती करने जा रही है. कैबिनेट की बैठक में इस आशय की जानकारी दी गई कि अब बिहार के भूमिहीन ग़रीबों को रहने के लिए सरकार 250 वर्ग फीट से लेकर 625 वर्ग फीट ज़मीन देगी. इसका विरोध जन संगठन एकता परिषद द्वारा किया गया.

चौथी दुनिया के पास उपलब्ध दस्तावेज़ के मुताबिक़, ख़ुद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रमई राम ने स्वीकार किया है कि राज्य में 1.93 लाख महादलित परिवारों के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है. सरकार की कथनी और करनी में कितना विरोधाभास है, यह ख़ुद सरकार के आकड़ें ही साबित कर रहे हैं. पटना ज़िले के मसौढ़ी अंचल के 21 गांवों के 803 महादलितों को ज़मीन देने की बात सरकार कर रही है. इसमें 625 मुसहर, 8 डोम, 7 नट, 155 पासी और 8 धोबी को जाति के अनुसार लाभान्वित कराया गया है. कुल 803 लाभान्वितों में से 389 महादलितों को 2 डिसमिल ज़मीन ही दी गई. उनके हिस्से की 1 डिसमिल की हक़मारी की गई. उसके बाद सिर्फ़ 194 महादलितों को ही सरकारी पैमाने के मुताबिक़ 3 डिसमिल ज़मीन दी गई. वहीं जन संगठनों के दबाव और उनकी मांगानुसार 86 महादलितों को 4 डिसमिल ज़मीन दी गई. दुर्भाग्य उन 74 महादलितों का है, जिन्हें मात्र 1 डिसमिल ज़मीन ही उपलब्ध कराई गई. 12 महादलितों को सवा दो डिसमिल ज़मीन दी गई. 9 महादलितों को डेढ़ डिसमिल ज़मीन दी गई है. 7 महादलितों को ढाई डिसमिल ज़मीन दी गई है. इसके बाद नौकरशाहों ने 15 महादलितों को सिर्फ़ 2 धुर ही ज़मीन देकर संतुष्ट करा दिया. वहीं 12 महादलितों को साढ़े 3 धुर ज़मीन दी गई. 3 को 4 धुर और 2 दो साढ़े तीन धुर ज़मीन दी गई है. इस तरह की ज़मीन वितरण ने सरकार की कलई खोलकर रख दी है. इसमें नौकरशाहों की मनमर्ज़ी दिखाई दी. सरकारी दावे 3.3 डिसमिल देने का पर्दाफ़ाश हो गया है. जिन महादलितों को 1 डिसमिल ज़मीन मिली है, उनके हिस्से में सिर्फ़ साढ़े छह धुर पड़ी. जिन्हें 3 डिसमिल ज़मीन मिली है, उन्हें 19 धुर ज़मीन दी गई है. जिन्हें 4 डिसमिल ज़मीन मिली है, उन्हें 26 धुर ज़मीन दी गई है. 20 धुर का ही एक कट्ठा होता है. सरकार ने रेवा में स्थित ग़ैर मजरूआ आम भूमि पर 132 महादलित मुसहर को केवल 2 डिसमिल रहने योग्य ज़मीन दी है. बिहटा में 53 चौधरी नामक महादलित को ज़मीन दी गई है. केवल दो लोगों को 3 डिसमिल ज़मीन दी गई है. 14 को 2 और 37 को 1 डिसमिल ज़मीन दी गई है. एकता परिषद के नेतृत्व में बिहार के विभिन्न अंचलों में 10 हज़ार 590 आवासीय भूमिहीनों का आवेदन दिया गया. उसमें सिर्फ़ 136 लोगों का परिणाम सामने आया यानी उनको ज़मीन दी गई. शेष 10 हज़ार 454 लोगों के आवेदन प्रक्रिया में हैं अथवा लालफ़ीताशाही के शिकार हो गए हैं.

पटना ज़िले के मसौढ़ी अंचल के 21 गांवों के 803 महादलितों को ज़मीन देने की बात सरकार कर रही है. इसमें 625 मुसहर, 8 डोम, 7 नट, 155 पासी और 8 धोबी को जाति के अनुसार लाभान्वित कराया गया है. कुल 803 लाभान्वितों में से 389 महादलितों को 2 डिसमिल ज़मीन ही दी गई. उनके हिस्से की 1 डिसमिल की हक़मारी की गई.

जी हां, यह सरकारी खेल है. यह इसलिए किया रहा है कि आज भी भूमि एक ऐसी अहम पूंजी है, जो जीवन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तंत्र का मूल आधार है. गांव, क़स्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के जीवन का आधार आज भी भूमि व प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित व्यवसाय पर ही टिका हुआ है. भूमि अधिकार व प्राकृतिक संसाधनों तक आम आदमी की पहुंच केवल आर्थिक अधिकार का प्रश्न ही नहीं, वरन ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले सभी लोगों के आत्मविश्वास से जुड़ा अधिकार है. इसी तरह का मसला ग़रीबों के निवास अधिकार को लेकर रहता है, जिसकी सरकार और ग़ैर सरकारी स्तर पर ज़ोरदार ढंग से चर्चा की जाती है. इसके कारण उनके इस अधिकार को मान्यता भी मिली है. मगर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास व निवास भूमि के अधिकार को लेकर कोई ठोस क़दम नहीं उठाया गया है. इसलिए सरकार बेफ़िक्र और प्रशासन बेलगाम होकर महादलितों को ज़मीन वितरित कर रहा है. ग़रीबों के बुनियादी अधिकारों के दायरे में बेघर व भूमिहीन परिवारों के निवास व निवास भूमि के अधिकार को मान्यता देना भी आवश्यक है. ग्राम सभा की देखरेख व सहमति से प्राथमिकता के आधार पर बेघर व भूमिहीन परिवारों की सूची बनाई जानी चाहिए. कम से कम 10.15 डिसमिल भूमि हरेक परिवार को दी जानी चाहिए. ग्रामीण क्षेत्रों की ग़रीबी, पिछड़ापन व ख़ुशहाली के सभी प्रश्न भूमि के स्वामित्व व नियंत्रण से जुड़े हैं. ग्रामीण ग़रीबी का विवेकपूर्ण संसाधन एक व्यापक भूमि सुधार कार्यक्रम के बग़ैर संभव नहीं है. ग्रामीण क्षेत्रों में निवास व निवास भूमि के अधिकार को लेकर कोई ठोस क़दम नहीं उठाया गया है. सवाल यह उठता है कि अगर सरकार और उनके नौकरशाह ही ग़रीबों के हिस्से में हक़मारी करना शुरू कर दें तो इंसाफ़ के लिए वे कहां जाएंगे? सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं की जा सकती है. यहां तक कि स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गठित महादलित आयोग और भूमि सुधार आयोग के अध्यक्षों द्वारा अनुशंसाओं को लागू नहीं किया गया.

(लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं)

feedback@chauthiduniya.com

मध्य प्रदेश

आडवाणी की रथ यात्रा

जब चौथी दुनिया में प्रकाशित कार्टून बन गया विपक्ष का हथियार

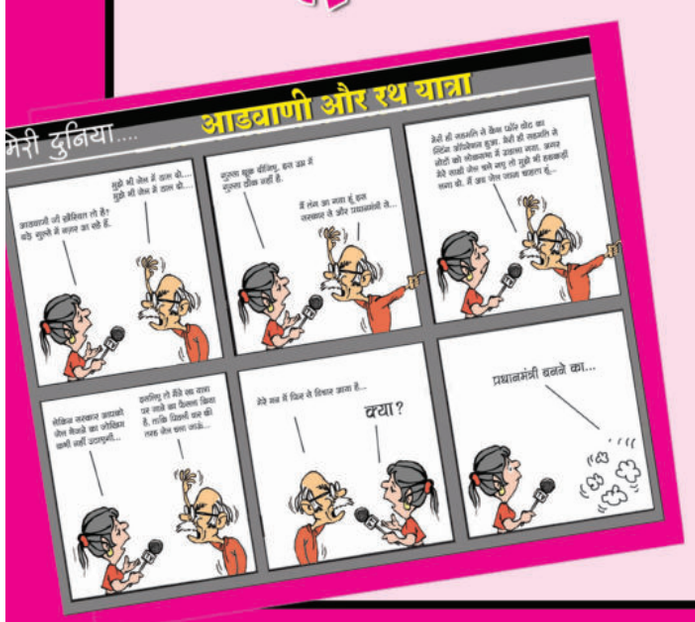

पत्रकारिता की ही एक विधा कार्टून अपनी तीक्ष्ण भाषा और कल्पना के सहारे बड़ी से बड़ी कहानी को आसानी से लोगों के दिलो-दिमाग़ तक पहुंचा देता है. राजनीति की कठिन और अबूझ पहेलियों को सुलझाने में कार्टून का एक बड़ा रोल है. राजनीतिक सरोकार को आम आदमी और आम आदमी के सरोकार को राजनीति तक पहुंचाने के एक सशक्त माध्यम के रूप में चौथी दुनिया में मेरी दुनिया कॉलम के तहत प्रकाशित कार्टून भी अपनी भूमिका बख़ूबी निभा रहा है. उदाहरण के लिए, चौथी दुनिया में आडवाणी की रथ यात्रा पर प्रकाशित कार्टून (आडवाणी और रथ यात्रा...) ने न सिर्फ़ आम आदमी के मन को बल्कि राजनीतिक परिदृश्य को भी झकझोरने का काम किया. आडवाणी की रथ यात्रा जैसे ही मध्य प्रदेश की सीमा में घुसी वैसे ही उनकी यात्रा का विरोध कर रहे वहां के कुछ स्थानीय नेताओं ने चौथी दुनिया में प्रकाशित कार्टून को दिखाकर उनका विरोध करना शुरू कर दिया. कटनी के कांग्रेस नेता राकेश जैन को चौथी दुनिया में प्रकाशित यह कार्टून रथ यात्रा के विरोध के लिए इतना उपयुक्त लगा कि उन्होंने हज़ारों की संख्या में इसकी कॉपी करवा ली. इसके बाद रथ यात्रा के रूट यानी सतना, मैहर, बरही, कटनी, उमरिया, जबलपुर के रास्ते में इसे सार्वजनिक जगहों पर लगवा दिया. हालांकि बाद में पुलिस ने राकेश जैन को गिरफ्तार भी किया और जब तक रथ यात्रा कटनी ज़िले को पार नहीं कर गई, उन्हें छोड़ा नहीं गया. लेकिन कार्टून के ज़रिये रथ यात्रा का विरोध यहीं नहीं थमा. भोपाल तक इस कार्टून की धूम मचती रही. भोपाल में पहले से ही कई जगहों पर यह कार्टून चर्चा का विषय बन चुका था. राज्य भर के मीडिया में भी चौथी दुनिया में प्रकाशित इस कार्टून की चर्चा हुई और यह कार्टून अख़बारों की सुर्ख़ियां बना.

कटनी के कांग्रेस नेता राकेश जैन को चौथी दुनिया में प्रकाशित यह कार्टून रथ यात्रा के विरोध के लिए इतना उपयुक्त लगा कि उन्होंने हज़ारों की संख्या में इसकी कॉपी करवा ली. इसके बाद रथ यात्रा के रास्ते में इसे सार्वजनिक जगहों पर लगवा दिया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कोहरे के कारण धूप न पहुंचने से फ़सल व सब्ज़ियों का उत्पादन भी प्रभावित होता है. प्रकृति के इस क़हर को उत्तर भारत की लगभग 30 करोड़ की आबादी एक से दो माह तक झेलती है.

किस बात की चेतावनी दे रहा है कोहरा?

उफ़, ये कोहरा!

एल. मोहन कोठियाल

पिछले काफ़ी समय से मौसम का मिज़ाज लगातार बदल रहा है. पृथ्वी के किसी क्षेत्र में बहुत अधिक बाढ़ आ रही है, कहीं बहुत अधिक तूफ़ान आ रहे हैं, तो कहीं बहुत अधिक ठंड व गर्मी पड़ने लगी है. भारत में भी यह असर बाढ़, सूखे व ठंड में तीव्रता के रूप में देखा जा सकता है. उत्तरी भाग में सबसे अधिक तीक्ष्ण प्रभाव यहां की कष्टप्रद सर्दी है. दिसंबर शुरू होते ही उत्तर भारत के अनेक राज्य घने कोहरे से ग्रस्त होने लगते हैं. इस बीच यदि बारिश हो जाए तो यह प्रभाव और अधिक व तीव्र हो जाता है. पंजाब व हरियाणा से इसकी शुरुआत होने के बाद यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान के अलावा हिमाचल, उत्तराखंड राज्यों में कहीं पूर्ण तो कहीं आंशिक रूप से छाने लगता है. कोहरे का यह प्रभाव विभिन्न स्थानों पर 25 से 45 दिनों तक रहता है. जनवरी की समाप्ति के साथ इसका प्रभाव कम होने लगता है. कोहरे का यह असर भारत के अलावा निकटवर्ती देशों पाकिस्तान व नेपाल की तराई में समान रूप से दिखता है.

कोहरा कई समस्याओं को लेकर आता है. कोहरा न छंटने का जनजीवन पर चौतरफ़ा प्रभाव पड़ता है. परिवहन तंत्र से लेकर कृषि, बाग़वानी पर तो असर होता ही है. साथ ही इससे आर्थिक गतिविधियां भी बुरी तरह से प्रभावित होती हैं.

यूं कहें कि कोहरे का सबसे ज़्यादा प्रभाव परिवहन तंत्र पर पड़ता है तो ग़लत न होगा. इससे हवाई, रेल व सड़क परिवहन पटरी से पूरी तरह उतर जाता है. रनवे पर दृश्यता में कमी से उत्तर भारत के ज़्यादातर हवाई अड्डों तथा दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर, चंडीगढ़, इलाहाबाद के अलावा पटना तक आने जाने वाली अनेक उड़ानें या तो देरी से चलती हैं और कई बार इनको रद्द कर दिया जाता है. रेल परिवहन के लिए कोहरा सबसे बड़ी समस्या होता है. इससे सैकड़ों रेलगाड़ियां रद्द कर दी जाती हैं और अनेक रेलगाड़ियां कई-कई घंटे देरी से चलती हैं. कोहरे का असर सड़क परिवहन पर भी होता है. इसकी गति कम हो जाती है. सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग मारे जाते हैं व घायल होते हैं.

कोहरे के कारण धूप न पहुंचने से फ़सल व सब्ज़ियों का उत्पादन भी प्रभावित होता है. प्रकृति के इस क़हर को उत्तर भारत की लगभग 30 करोड़ की आबादी एक से दो माह तक झेलती है. उत्तर भारत में 15 साल पूर्व जाड़े में यह असर सामान्य धुंध के रूप में ही नज़र आता था, लेकिन अब यह मानसून के आगमन जैसी नियमित प्रक्रिया बन चुकी है. कोहरे के बावजूद तापमान में कमी का रिकॉर्ड बनना भी आश्चर्यजनक है. दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश में हर साल न्यूनतम तापमान के रिकॉर्ड टूटते रहे हैं. अब शून्य अंश तापमान पहाड़ के अतिरिक्त मैदान में रिकॉर्ड हो रहा है. मौसम में इस बदलाव को समझने के अभी तक बहुत ही कम प्रयास हुए हैं. वैज्ञानिक समुदाय अभी तक एक लघुकालिक मौसम परिवर्तन के रूप में देखता आया है. भारत में कोहरे को लेकर अलग-अलग विचारधाराएं हैं. धुर पर्यावरणवादी विचारधारा के अनुसार, इसके लिए मानवीय हलचलें ही ज़िम्मेदार हैं, जो दुनिया भर में मौसम परिवर्तन का कारण हैं. उधर, मौसम वैज्ञानिक कई प्रकार के प्रभावों को इसका कारण बताते हैं, जबकि भूगोलविदों की नज़र में कोहरे के भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं.

सामान्य रूप से कोहरा तब बनता है, जब वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प वायु के अणुओं पर जमता है. कोहरा कई प्रकार का होता है. किसी स्थान पर ठंडा होने का मतलब यह नहीं है कि वहां पर भी कोहरा लगे. कोहरे के लिए आर्द्रता और कम तापमान व वायुमंडलीय परिस्थितियां मैदानी क्षेत्र में शीतकाल में नवंबर से दिसंबर में बनने लगती हैं. कोहरे के बनने के अन्य कारक भी होते हैं, मसलन इस स्थान का तापमान, उच्च वायुमंडलीय दाब, आसमान का साफ़ होना, वायु का कम प्रवाह. वायु प्रवाह के कारण कोहरा कम लगता है. इसी प्रकार से आसमान में बादल होने या स्थान विशेष पर विक्षोभ बनने से भी वह नहीं लगता है.

कोहरा भले ही जिन कारणों से लगता हो, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उत्तर भारत में बड़ी संख्या में बनी सिंचाई योजनाएं, भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल होना व तटबंध उत्तर भारत में कोहरा लगने का एक कारण है, जिससे इस क्षेत्र विशेष में सापेक्ष आर्द्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है. शीतकाल में तापमान के नीचे जाने से नमी का स्तर और भी बढ़ जाता है. इसके अलावा वायुमंडलीय प्रदूषण व ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन के असर से कुहासे की समस्या पैदा हुई है, लेकिन पहले ऐसा क्यों न था या फिर अचानक नमी व प्रदूषण का स्तर क्या इतना बढ़ गया है? लेकिन मात्र यही कारण हैं, सब सहमत नहीं हैं. तब पर्वतीय क्षेत्रों में इन दिनों इस प्रकार कोहरे के आच्छादन की समस्या क्यों नहीं आती है? जहां पर जाड़े के दिन पहले की बजाय अधिक ख़ुशगवार मौसम मिलता है. हालांकि इसका एक कारण वह हिमालय की ऊंची चोटियों व लघु चोटियों के बीच ग्रीन हाऊस गैसों को बताते हैं, जो अब यहां पर इस असर को पैदा करती हैं, जबकि इसके सापेक्ष मैदान में ऐसा प्रभाव नहीं बन पाता है.

लेकिन कोहरा छाने व भीषण सर्दी के पीछे आख़िर कौन से और कारण हो सकते हैं, वैज्ञानिक अभी भी अनुमान ही लगा पाए हैं. भारत में कोहरे की घटना विश्वव्यापी मौसम परिवर्तन का हिस्सा नहीं है, इसे नकारा नहीं जा सकता है. यदि यह विश्व के मौसम में बदलाव के कारण हो रहा है तो इन सारे कारकों पर प्रकाश डालना ज़रूरी होगा जो, इसके लिए ज़िम्मेदार माने जाते हैं. ये सभी कारण वैज्ञानिक अध्ययनों पर ही आधारित हैं, जिन्हें यदि ये सही नहीं हैं तो इनको ग़लत भी नहीं कहा जा सकता है. मौसम वैज्ञानिक, भूगोलवेत्ता, भूभौतिकविद मौसमी बदलाव को विश्व संदर्भ में अपने-अपने दृष्टिकोण से देखते रहे हैं. पर्यावरण वैज्ञानिक मौसमी बदलाव को ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा मानते हैं और तापमान में वृद्धि के कारण दुनिया में होने वाले अप्रत्याशित बदलावों की भविष्यवाणियां करते रहते हैं, मसलन इनकी एक भविष्यवाणी कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने के प्रभाव से 2050 तक समुद्र के किनारों पर बसे कई शहर जलमग्न हो जाएंगे, सत्य लगती है. आज विश्व के उत्तर व दक्षिण ध्रुव व ऊंचे पहाड़ों पर सुरक्षित बर्फ़ के भंडार बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं, फलस्वरूप सागर के जलस्तर में वृद्धि हो रही है.

भूगोल व मौसमवेत्ता विश्वव्यापी मौसमी बदलाव को कुछ ख़ास प्रभावों की देन मानते हैं. भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के चक्र में परिवर्तन हो या अमेरिका में आए विनाशकारी तूफ़ान या बाढ़ हो, या अफ्रीका में सूखा या ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के लिए अल-निनो प्रभाव को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जो हर 4-5 सालों में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में उभरता है और 12 से 18 माह की अवधि के बाद समाप्त हो जाता है. अल-निनो भूमध्य रेखा के इर्दगिर्द प्रशांत महासागर के जल के इस दौरान 2 से.ग्रे. तक गर्म होने की घटना है. इसे सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में पेरू के मछुआरों ने महसूस किया और इसे अल-निनो नाम दिया गया. प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह गर्म होने के असर के कारण पूरे विश्व की जलवायु पर पड़ता है और आए दिन इसकी चर्चा होती रहती है, लेकिन ठीक इसके उलट दूसरी घटना ला-निना है, जिसके असर के चलते समुद्र की सतह ठंडी हो जाती है और इसके कारण भी मौसम बदलाव की बात होती है. यह प्रभाव भी प्रशांत महासागर में महसूस किया जाता रहा है. भारत, पाकिस्तान व नेपाल में लगने वाले कोहरे को कुछ मौसम वैज्ञानिक इसकी देन बताते हैं, जिस कारण इस क्षेत्र विषेश के ऊपर नम हवाएं बहने लगती हैं और कोहरे को जन्म देती हैं.

विश्वव्यापी मौसमी बदलाव के बारे में कुछ भूगोलविद् टेक्टोनिक प्लेटों का खिसकना भी बताते हैं. इसी तरह कुछ का मानना है कि पृथ्वी के घूमने का अक्ष 41 हज़ार सालों में 21.2 से 24.5 अंश के कोण के मध्य रहता है. इससे सूर्य के प्रकाश की तीव्रता प्रभावित होती है. उधर, अंतरिक्ष व भूभौतिकविद् पृथ्वी पर मौसमी बदलाव को सूर्य पर चक्रीय आधार पर होने वाले सन स्पॉट से जोड़कर देखते हैं, जिससे पृथ्वी की जलवायु प्रभावित होती है. इनके कारण सूर्य की सतह पर तापक्रम बदलता रहता है. समय-समय पर इसकी सतह पर परिवर्तन होता रहता है. इसी प्रकार सौर सक्रियता को भी पृथ्वी में मौसमी परिवर्तन से जोड़कर देखा जाने लगा है. 8 से 11 साल बाद प्रकट होने वाली सौर सक्रियता के दौरान सूर्य में बढ़ी हलचल से सूर्य से उत्पन्न होने वाले विकीरणों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पृथ्वी के मैग्नेटोस्फेयर प्रभावित होता है जो अंतरिक्ष से आने वाले विकिरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है. भारत में कोहरे पर मौसम वैज्ञानिक इस बात का पता लगा रहे हैं कि कहीं यह वायुमंडल में मात्र प्रदूषणकारी मुख्य गैसों यथा सल्फर डाईऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाईऑक्साइड व अन्य ग्रीन हाऊस गैसों के कारण तो नहीं होता है और कोहरे के घनेपन का इसका क्या संबंध है.

भू-गर्भवेत्ताओं की नज़र में हिमयुग वापस लौटने को है, जो एक समयबद्ध घटना है. यद्यपि इसके आने में अभी 1500 साल हैं, लेकिन कुछ इसके समय को लेकर असहमत हैं. अमेरिका व यूरोप में इस साल की सर्दी हिमयुग की विचारधारा पर सोचने को मजबूर करती है, किंतु इसका अध्ययन किए बग़ैर ऐसा यक़ीनन नहीं कहा जा सकता है कि विश्व हिमयुग की दहलीज़ पर है.

कोहरे व ठंड की मार आज एक तरह की आपदा का रूप ले चुकी है. कोहरे की मार से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भारी जन-धन का नुक़सान होता है. इसलिए सूखे, समुद्री तूफ़ान, भूकंप, भू-स्खलन या बाढ़ की तरह ही कोहरे से जन-धन के नुक़सान के आकलन की आवश्यकता महसूस होने लगी है. लोगों को यह याद होगा कि दिसंबर 02 व जनवरी 03 की कोहरे भरी सर्दी से उत्तर भारत के राज्यों में 1500 लोगों की मौत हुई थी. 2004-05 में यह आंकड़ा लगभग 800 रहा था. 2008 में दिसंबर से जनवरी में यह आंकड़ा लगभग 600 के आसपास रहा. 2008 से जनवरी के बीच में हालांकि यह संख्या अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन 2011 के साल में अब तक उत्तर प्रदेश में 150 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि कोहरे, कोहरा जन्य दुर्घटनाओं को मिलाकर देश में यह संख्या 250 तक रही. अब 2011 की सर्दियां दर पर हैं और फिर से उत्तर भारत में कोहरा असर दिखाने लगा है.

बहरहाल, पृथ्वी का मौसम एक बेहद जटिल प्रणाली है. जिस प्रकार से भारत में मानूसन को समझा गया है, उसी तरह के प्रयास कोहरे की घटना को समझने के लिए करने होंगे. हालांकि इसके अध्ययन से तात्कालिक कोई समाधान तो नहीं निकल सकता है, लेकिन इससे कम से कम इन कारणों का तो ख़ुलासा हो सकता है जो आम आदमी के मन पर पिछले कई सालों से छाए हैं कि 15 साल पहले उत्तर भारत में कोहरा वास्तव में क्यों नहीं बनता था. यदि यह मानवजन्य है तो कालांतर में हमें इससे बचने के उपाय करने ही होंगे.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... चोरी की गंभीरता!

वन पर निर्भर समुदायों के सशक्तीकरण के कारण न केवल ऐतिहासिक अन्याय को ख़त्म किया जा सकेगा और उनकी आजीविका में वृद्धि होगी, बल्कि हमारी प्राकृतिक वन संपदा और धरोहर का संरक्षण भी हो सकेगा.

वनों में प्रकाश की किरण

भारत में वनों पर निर्भर 250 मिलियन लोग दमनकारी साम्राज्यवादी वन संबंधी क़ानूनों के जारी रहने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से भारी अन्याय के शिकार होते रहे हैं और ये लोग देश में सबसे अधिक ग़रीब भी हैं. वन्य समुदायों के सशक्तीकरण के लिए पिछले 15 वर्षों में भारत में दो ऐतिहासिक क़ानून पारित किए गए हैं. लेकिन ज़मीनी सच्चाई तो यह है कि इनका प्रभाव भी काफ़ी निराशाजनक रहा है. हालांकि ये सभी क़ानून आधे मन से ही पारित किए थे, लेकिन हाल में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं, जिनका उपयोग यदि उचित रूप में किया जाए तो इन समुदायों के जीवन स्तर को काफ़ी बेहतर बनाया जा सकता है.

पृष्ठभूमि

जब गडचिरौली के आदिवासी ज़िले में मेंधा लेखा गांव के सामुदायिक नेता देवाजी तोफ़ा को 2011 में अपनी ग्राम सभा से ट्रांजिट पास मिला तो उनके समुदाय को खेती करने और अपने बांस बेचने की अनुमति मिल गई. यह सुविधा केवल प्रतीकात्मक ही नहीं थी, बल्कि उससे कहीं अधिक थी. इससे वन पर निर्भर लोगों के बेहतर भविष्य की संभावनाएं बढ़ी हैं. जहां एक ओर अधिकांश लोगों को भारत के जंगलों में शेरों और वनस्पतियों के चित्र ही दिखाई पड़ते हैं, वहीं एक और दुनिया है, जहां मेहनतकश लोग ग़रीबी रेखा के अंतिम छोर पर रहते हैं, लेकिन किसी का ध्यान उन पर नहीं जाता. एक अनुमान के अनुसार वनजीवी के रूप में पहचाने जाने वाले पचास मिलियन से अधिक लोग ग़रीबी रेखा के अंतिम छोर पर रहते हैं, लेकिन किसी का ध्यान उन पर नहीं जाता. एक अनुमान के अनुसार वनजीवी के रूप में पहचाने जाने वाले पचास मिलियन से अधिक लोग भारत के वन-प्रांतरों में रहते हैं और वनों पर निर्भर रहने वाले 275 मिलियन लोग अपनी आजीविका के कम से कम एक भाग के लिए तो वनों पर भी निर्भर करते हैं. दोनों प्रकार के लोग, वनों पर निर्भर रहने वाले लोग और विशेषकर वनजीवी लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े और सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर हैं. ये लोग साम्राज्यवादी वन संबंधी क़ानूनों के जारी रहने के ऐतिहासिक दृष्टि में अन्याय के शिकार होते रहे हैं. इन क़ानूनों के कारण न तो इन्हें ज़मीन और संसाधनों के अधिकार मिले और न ही वन संरक्षण में भागीदारी मिली. शताब्दियों से वहां रहने पर भी 2006 तक न तो उन्हें मिल्कियत की सुरक्षा मिली और न ही संपत्ति के अधिकार मिले.

परिवर्तन की पहली लहर

पंद्रह वर्ष पूर्व भारत ने यथास्थिति को बदलने के लिए पहला क़दम उठाया था. अनुसूचित क्षेत्र के 1996 के पंचायत विस्तार अधिनियम ने ग्राम सभा को संसाधन प्रबंधन के केंद्र में लाकर और भूमि, जल और वन जैसे सामुदायिक संसाधनों पर आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता देते हुए अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के शासन को विकेंद्रित कर दिया. दस साल के बाद 2006 में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) ने एक क़दम और आगे बढ़कर वनजीवी समुदायों के सशक्तीकरण का काम शुरू किया और वनजीवियों को उस ज़मीन की मिल्कियत दे दी, जिस पर वे रहते थे और वन्य उत्पादों (एमएफपी) के लिए उसका थोड़ा बहुत उपयोग भी करते थे.

यद्यपि ये दोनों ही क़ानून ऐतिहासिक महत्व के थे, लेकिन ज़मीनी सच्चाई तो यही थी कि उनका कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा. राज्य के क़ानून भी इस अधिनियम की भावना के अनुरूप नहीं थे और कई मामलों में तो सबसे अधिक मूल्यवान वनोत्पादों के सामुदायिक मिल्कियत से भी उन्हें वंचित कर दिया गया. परंतु सामुदायिक वन अधिकार देने की प्रगति बहुत धीमी रही. आरोपित शासन प्रणाली, स्थानीय नौकरशाहों के विरोध और वनोत्पादों से राजस्व जुटाने के लिए वन विभाग की निर्भरता के कारण वन्य समुदायों के वास्तविक सशक्तीकरण पर रोक लग गई.

वन्य समुदायों के जीवन में चार परिवर्तन

यद्यपि ये बातें भारत के वनों पर निर्भर रहने वाले समुदायों के हालात तो बयान करती हैं, लेकिन हाल ही की कम से कम चार प्रवृत्तियों के कारण लगता है कि सशक्त नागरिक समुदायों और हाल ही की सरकारी कार्रवाई के कारण अंततः उनके जीवन में प्रकाश की किरणें फूटने लगी हैं. पहला प्रमुख परिवर्तन 2006 में क़ानूनी हक़ों के कार्यान्वयन के कारण हुआ था. इसके कार्यान्वयन के बाद से लेकर अब तक पहली बार एफआरए के कार्यान्वयन को गंभीरता से लिया जा रहा है. पर्यावरण व वन मंत्रालय ने यह शर्त लगा दी कि जब एक एफआरए का कार्यान्वयन हीं हो जाता, तब तक अगस्त 2009 तक की नई परियोजनाओं को वानिकी के संबंध में स्वीकृति नहीं दी जाएगी. उच्च प्रोफाइल की परियोजनाओं के मामले में भी सरकार इस कार्रवाई को लेकर काफ़ी गंभीर लगती है. उदाहरण के लिए, उड़ीसा में वेदांत ग्रुप की बॉक्साइट खनन परियोजना को रोककर सरकार ने स्पष्ट शब्दों में यह संदेश दे दिया है कि वनजीवियों को दिए गए क़ानूनी अधिकार अपरिवर्तनीय हैं और उन्हें किसी भी क़ीमत पर कार्यान्वित किया जाएगा.

इसके अलावा ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों को ख़त्म करने के लिए और क़ानूनी उपाय भी किए जा रहे हैं. भारतीय वन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन लाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह भी अनुमोदित कर दिया है कि स्थानीय लोगों पर छोटे-मोटे अपराधों के लिए समझौता जुर्माना लगाने के लिए वन अधिकारियों को संबंधित ग्राम सभा से सलाह करनी होगी. वनजीवी समुदायों को वन अधिकारियों के उत्पीड़न से बचाने के लिए यह एक बड़ा क़दम माना जा रहा है.

दूसरा बड़ा परिवर्तन यह है कि स्थानीय समुदायों को वन प्रबंधन और संरक्षण में भागीदार बनाना. परंपरागत रूप में स्थानीय समुदायों को मोटे तौर पर वन संरक्षण और प्रबंधन से दूर रखा जाता रहा है और लंबे समय से यह क्षेत्र वन विभाग का ही माना जाता रहा है. वनजीवियों को सामुदायिक वन रक्षकों के रूप में रखने से दोनों ही लाभ में रहेंगे. अंततः अब इस बात को स्वीकार भी किया जाने लगा है और इसके प्रयोग देश-भर में किए जा रहे हैं.

स्थानीय आदिवासी युवाओं को वन प्रबंधन में प्रशिक्षित और नियोजित किया जा रहा है. पिछले दो वर्षों में इस दिशा में किए गए नए और महत्वपूर्ण प्रयासों के कारण ही प्रति वर्ष लगभग 2.5 मिलियन मानव दिवस इन स्थानीय समुदायों के लिए नियोजित किए गए. उदाहरण के लिए कार्बेट में वन गुर्जर, वन्य पशुओं के अवैध शिकार को रोकने के लिए आगे रहने वाले पैदल सिपाही के रूप में काफ़ी प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं.

स्थानीय समुदायों के उपयोग के इसी प्रयोग के आधार पर सरकार ने हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन नाम से दस वर्षीय दस बिलियन डॉलर की एक परियोजना अभी हाल में शुरू की है, जिसके मूल में लोक-केंद्रित वन संरक्षण की भावना ही है. ज़मीनी स्तर पर मिशन के कार्यान्वयन के साथ पुनर्गठित संयुक्त वन प्रबंधन समितियां (जेएफएमसी) का गठन ग्राम सभाओं द्वारा ही किया जाएगा और वे ही इसके लिए ज़िम्मेदार भी होंगी. इससे रूपावली में एक नया परिवर्तन सामने आएगा, जिसमें निवेश और प्रबंधन के संदर्भ में लोक केंद्रिक निर्णयों की प्रमुख भूमिका होगी.

समुदायों को यह लाभ होगा कि वे स्थानीय जैव विविधता के अपने परंपरागत ज्ञान का लाभ भी उठा सकेंगे. भारत जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र की कन्वेंशन, जिस पर अक्टूबर, 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे, के अंतर्गत एक्सेस और बेनेफिट शेयरिंग प्रोटोकॉल (एबीएस) का प्रमुख प्रस्तावक रहा है. यह प्रोटोकॉल, देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि आनुवांशिक संसाधनों से संपन्न स्थानीय समुदायों के ऐसे परंपरागत ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभ का उचित और समान वितरण किया जाए. घरेलू क़ानून (एफआरए और जैव विविधता अधिनियम) के साथ समर्थित एबीएस प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करने की दिशा में पहला क़दम है कि वन्य समुदायों को उचित रूप में क्षतिपूर्ति का लाभ मिल सके.

तीसरा परिवर्तन शायद जीविका की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और वह बांसों से संबंधित है. कई लोगों का मानना है कि आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक मूल्यवान फ़सल बांसों तक पहुंच होने के कारण वन पर निर्भर समुदायों की जीविका के अवसरों में बेशुमार वृद्धि होगी. मोटे अनुमानों से पता चलता है कि यदि इन समुदायों को बांसों की फ़सल उगाने की अनुमति मिल जाती है तो इससे उनकी आमदनी में प्रतिवर्ष 20,000-40,000 करोड़ रुपये का इज़ाफ़ा हो सकता है और पंद्रह मिलियन से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सकता है. बहस इस बात पर है कि बांस घास है या लकड़ी. यदि यह घास है तो एमएफपी (वे वन समुदाय, जिनकी वह मिल्कियत है) मूल्य संवर्धन और बिक्री के लिए उसकी फ़सल उगा सकेंगे और उसका उपयोग भी कर सकेंगे और अगर यह लकड़ी है तो इसे वन विभाग ही उगा सकेगा और इसकी बिक्री कर सकेगा. यह बहस उस समय तक चलती रही, जब तक पर्यावरण मंत्रालय ने हाल में मार्च, 2011 में यह स्पष्ट नहीं कर दिया कि बांस वास्तव एमएफपी है. इसका अर्थ यह होगा कि ये समुदाय अब ग्राम सभा की अनुमति से बांसों की खेती कर सकेंगे. ग्राम सभाओं को इसके परिवहन और बिक्री के लिए अनुमति देने के लिए कमाने का अवसर मिलने से काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि बाज़ार में बांस की अच्छी क़ीमत मिल जाती है और कई देसी शिल्पों और कुटीर उद्योगों में इसका इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाता है. मेंधा लेखा गांव में इसका प्रतीकात्मक अनुष्ठान इस दिशा में पहला क़दम है. मेंधा लेखा से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी से यह पता चला है कि इससे गांवों की आमदनी में काफ़ी इज़ाफ़ा होने की संभावना है.

चौथे परिवर्तन के कारण वन समुदायों को यह लाभ होगा कि वे स्थानीय जैव विविधता के अपने परंपरागत ज्ञान का लाभ भी उठा सकेंगे. भारत जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र की कन्वेंशन, जिस पर अक्टूबर, 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे, के अंतर्गत एक्सेस और बेनेफिट शेयरिंग प्रोटोकॉल (एबीएस) का प्रमुख प्रस्तावक रहा है. यह प्रोटोकॉल, देशों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि आनुवांशिक संसाधनों से संपन्न स्थानीय समुदायों के ऐसे परंपरागत ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभ का उचित और समान वितरण किया जाए. घरेलू क़ानून (एफआरए और जैव विविधता अधिनियम) के साथ समर्थित एबीएस प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करने की दिशा में पहला क़दम है कि वन्य समुदायों को उचित रूप में क्षतिपूर्ति का लाभ मिल सके.

इसी प्रकार भारत निर्वनीकरण व वन क्षरण (आरईडीडी) पहले के माध्यम से उत्सर्जन करने के लिए उन तमाम अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं की वकालत करने में सक्रिय रहा है, जिनमें वनों के धारणीय प्रबंधन के लिए उत्सर्जन कम करने वाले देश प्रोत्साहन के रूप में संसाधन प्राप्त करने का हक़ हासिल कर सकेंगे. यद्यपि यह अभी आरंभिक अवस्था में ही है. कुछ अध्ययनों में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में आरईडीडी+पहल होने से कार्बन सेवा प्रोत्साहन के रूप में इसे तीन बिलियन डॉलर से अधिक राशि प्रदान की जा सकती है. सरकार ने यह प्रतिबद्धता जताई है कि आरईडीडी+पहल से मिलने वाले मौद्रिक लाभ को स्थानीय, वनजीवी और आदिवासी समुदायों में वितरित कर दिया जाएगा.

इस प्रकार चौथा परिवर्तन वन आधारित संसाधनों से होने वाले लाभ को स्थानीय समुदायों में वितरित करते हुए उसे संरक्षित, मोनेटाइज़ और प्रोत्साहित करना है.

कार्यान्वयन की चुनौतियां

आगे और भी चुनौतियां हैं. इन परिवर्तनों के लिए शासन तंत्र प्रणाली को विकसित करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है. हम सीखने के एक लंबे मोड़ पर हैं, जिसकी शुरुआत अस्सी के उत्तरार्ध में जेएफएमसी के दर्शन 1.0 से हुई थी और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका विकास होता जा रहा है. इस अंतराल को पाटने के लिए शीर्ष स्तर के नेताओं का नेतृत्व और नगारिक समाज की निगरानी की निरंतर ज़रूरत पड़ेगी.

उचित प्रतिनिधित्व वाली और अच्छी तरह चलने वाली ग्राम सभा में सर्वानुमति से निर्णय लेने की बातें सैद्धांतिक रूप में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्हें व्यावहारिक रूप प्रदान करना बहुत कठिन होता है. यदि हम यह मान भी लें कि ग्राम सभाएं आम सहमति से निर्णय ले सकती हैं, लेकिन भद्रलोक की पकड़ (या किसी हितधारक समूह द्वारा उन्हें हथिया लेने) से उन्हें बचाए रखना आसान नहीं है. सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण क्षमता का निर्माण करना होगा.

इसके अलावा वनजीवियों और वन पर निर्भर रहने वाले समुदायों के प्रति वन विभाग और अन्य स्थानीय सरकारी कर्मचारियों के रवैये, प्रशिक्षण और व्यवहार में अर्थात सभी स्तरों पर बदलाव की ज़रूरत है. यह इतना सीधा रास्ता नहीं होगा. वन विभाग अपनी नई भूमिका को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर पाएगा. वे लोग दानवीर के समान स्थानीय समुदायों को एमएफपी ख़ास तौर पर बांस पर इतनी आसानी से अपनी पकड़ नहीं बनाने देंगे, क्योंकि बांस और अन्य एमएफपी राजस्व के मूल स्रोत रहे हैं और साथ ही उनके लिए ये शक्ति और नियंत्रण के स्रोत भी हैं.

एमएफपी के लिए बढ़िया प्रतियोगी मंडियां भी विकसित करनी होंगी, ताकि वनजीवियों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके. इसके लिए नवोन्मेषकारी तंत्र की आवश्यकता होगी, जो मात्र न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने से ही नहीं बन जाएगा. उदाहरण के लिए, वनजीवियों को प्रभावी पूर्तिकर्ता समूहों के रूप में संगठित करने के लिए संस्थागत सपोर्ट की आवश्यकता होगी और अतीत में सहकारी आंदोलनों के हमारे अनुभवों को देखते हुए यह कोई छोटी चुनौती नहीं होगी.

निष्कर्ष

वन पर निर्भर समुदायों के सशक्तीकरण के कारण न केवल ऐतिहासिक अन्याय को ख़त्म किया जा सकेगा और उनकी आजीविका में वृद्धि होगी, बल्कि हमारी प्राकृतिक वन संपदा और धरोहर का संरक्षण भी हो सकेगा. इसका अतिरिक्त लाभ यह होगा कि इन समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण के कारण नक्सलवाद (जिसे स्थानीय वन गांवों से ही शक्ति मिलती है और जिनको धन भी वनज उत्पादों से ही मिलता है) से लड़ने में यह एक प्रभावी उपाय सिद्ध होगा.
आशा है कि इन परिवर्तनों और अधिकारों के कारण जो गति आई है, उसकी मेंधा गांव से निकली मौन यात्रा हमारे वन्य समुदायों के जीवन को आलोकित करती रहेगी.

वरद पांडे/प्रांजुल भंडारी
feedback@chauthiduniya.com

(वरद पांडे भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय में विशेषकार्य अधिकारी हैं और प्रांजुल भंडारी भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष कार्यालय में अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत हैं.)

राष्ट्र को तो उत्पादन ख़र्च पर या कहीं-कहीं उससे भी सस्ती दरों में बिजली देनी ही चाहिए या उस श्रेणी के समस्त उद्योग का यानी सारी बिजली कंपनियों का राष्ट्रीकरण हो जाना चाहिए.

दो वर्षों की जद्दोजहद के बाद आइसलैंड अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आया. इसके बाद के मुख्य क़र्ज़दाता ब्रिटेन और नीदरलैंड ने इस देश के क़र्ज़ की पुनर्व्यवस्था की बात स्वीकार कर ली.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

राष्ट्र और पूंजी

ध्यान देने की बात यह है कि ये पूंजीवादी धनिक उन्हीं चीज़ों में अपने रुपये लगाते हैं या दूसरों से लेकर लगाते हैं, जहां इनको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा नज़र आता है. देश के लिए क्या काम करना अच्छा है, इसमें इनकी तनिक भी आस्था नहीं.

मान लीजिए, समुद्रों में जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाऊस की सख्त ज़रूरत है. आयात-निर्यात करने के लिए बंदरगाहों की अत्यंत आवश्यकता है. इसी तरह देश की उन्नति के लिए सैकड़ों ऐसी आवश्यक चीज़ें हैं. इन्हें बनाने में या तो जोखिम ज़्यादा है या इनसे उतनी आमदनी नहीं हो पाती, जितनी दूसरे ढंग के कारख़ानों से होती है, तो ये पूंजीवादी लोग कभी भी इन चीज़ों को बनाने में रुपये ख़र्च नहीं करेंगे. ये सब आवश्यक काम राष्ट्र को, सरकार को ही करने पड़ते हैं. हां, यदि सिगरेट का एक कारख़ाना लगाना हो तो फ़ौरन पूंजीवादी लोग तैयार होते हैं. वे ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेटें बनाकर बड़े-बड़े इश्तिहारों या विज्ञापनों से घोषणा करेंगे कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है और उनके कारख़ाने में बनी हुई स्पेशल क़िस्म की सिगरेट पीना तो एक प्रकार से धार्मिक पुण्य कार्य ही है. हालांकि यह सरासर झूठ है, पर ऐसी अनेक कंपनियां या फैक्ट्रियां खड़ी करने में, बनाने में इनको ज़रा भी संकोच नहीं होता.

दूसरी प्रधान बात यह है कि पूंजीवादी जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने की कोशिश करता है. मान लीजिए राष्ट्र के डाकतार विभाग से आप तार भेजते हैं. 10 नए पैसे प्रति शब्द की दर से आपको चार्ज देना होता है. अगर इसे घटाकर 2 नए पैसे प्रति शब्द कर दिए जाएं तो देश को आर्थिक हानि होगी या नहीं? अगर तार की दरें इतनी सस्ती हो जाएं तो स्वाभाविक है, तार भेजने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. मान लें, चार्ज 1 रुपया प्रति शब्द कर दिया जाए तो संख्या उसी अनुपात से घट जाएगी, तो भी तार विभाग को उतना ही नफ़ा होने वाला है. क्योंकि चार्ज घटने-बढ़ने से तार भेजने वालों की संख्या अपने आप ज़्यादा या कम हो जाएगी.

किसी भी वस्तु या सेवा की क़ीमत कम या ज़्यादा कर लीजिए, उससे नफ़े पर फ़र्क़ कदाचित ही पड़ता है. वहीं तार विभाग यदि पूंजीवादियों की निजी संपत्ति होता तो यक़ीनन वे प्रति शब्द 1 रुपया ही चार्ज करते और जो उससे मुनाफ़ा होता,

अगर तार की दरें इतनी सस्ती हो जाएं तो स्वाभाविक है, तार भेजने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. मान लें, चार्ज 1 रुपया प्रति शब्द कर दिया जाए तो संख्या उसी अनुपात से घट जाएगी, तो भी तार विभाग को उतना ही नफ़ा होने वाला है. क्योंकि चार्ज घटने-बढ़ने से तार भेजने वालों की संख्या अपने आप ज़्यादा या कम हो जाएगी. किसी भी वस्तु या सेवा की क़ीमत कम या ज़्यादा कर लीजिए, उससे नफ़े पर फ़र्क़ कदाचित ही पड़ता है.

वह उन लोगों की जेबों में ही जाता. राष्ट्र जिन-जिन उद्योगों को चलाता है उसके चार्ज स्वाभाविक तौर पर नीचे या सस्ते होते ही हैं, क्योंकि उनमें नफ़ा करने की मंशा नहीं रहती. अगर नफ़ा होता भी है तो वह फिर राष्ट्र के हर व्यक्ति के उपयोग के लिए ख़र्च होता है.भारत में अभी तक जिन-जिन संस्थाओं का राष्ट्रीकरण हुआ है, वहां भी मनोवृत्ति अभी तक पूंजीवादी ही रही है. इसीलिए जनता को उसका पूरा लाभ हो नहीं पाया है. ऐसा हर जगह, जहां परिवर्तन होता है, वहां होता ही है. लोग काम करने की जिस परिपाटी के अभ्यस्त हो जाते हैं उनकी आदतें बदलते-बदलते ही बदलती हैं. आज का राष्ट्रीकरण दुर्भाग्य से सिर्फ़ पूंजीवादी सम्राट का बदलना मात्र हुआ है. जहां वे धनिक लोग, जिनकी निजी संपत्ति थी, मनमानी करते थे, उसके बदले में नए बने हुए ओहदेदार सरकारी नौकर या ऑफिसर उतनी ही, बल्कि उससे भी ज़्यादा मनमानी या अत्याचार कर रहे हैं. संतोष इतना ही है कि जहां वे अपने बल पर सतारूढ़ रह सकते हैं. प्रजामत ख़िलाफ़ होते ही बड़े से बड़े ओहदे का ऑफिसर भी कुछ ही क्षणों में या दिनों में धराशायी होता दिखाई देता है.

उदाहरण के रूप में बड़ी-बड़ी बिजली की कंपनियों की योजनाएं हैं, जो पूंजीवादी उद्योगपतियों के अधीन हैं, वहां मान लीजिए 10 नए पैसे की यूनिट चार्ज लगता है. बहुत सी जगह राष्ट्रीय बिजली कंपनियां भी हैं या राज्य विद्युत बोर्ड हैं, जहां बिजली पैदा करने का कुल ख़र्च मुश्किल से 2 या 3 नए पैसे प्रति यूनिट आता है तो भी वे ऑफिसर या ओहरेदार अपनी शान समझते हैं कि हम भी 10 नए पैसे या 12 नए पैसे की दर से बिजली बेचकर ज़्यादा मुनाफ़ा कमाकर दिखाएं कि निजी उद्योगपतियों की तरह हम भी व्यापार करना जानते हैं.

दुख है, वे राष्ट्रीकरण के मूल पहलू को जानते ही नहीं. जहां उन पुराने उद्योगपतियों के बिजली के कारख़ाने 1 करोड़ की लागत में बने थे, आज उसी प्रकार या साइज का नया कारख़ाना लगाने में सरकार को 10 गुना से भी अधिक ख़र्च करना पड़ता है, तो फिर आप उनसे प्रतियोगिता कैसे और क्यों करें? इसका प्रयत्न भी नहीं होना चाहिए. राष्ट्र को तो उत्पादन ख़र्च पर या कहीं-कहीं उससे भी सस्ती दरों में बिजली देनी ही चाहिए या उस श्रेणी के समस्त उद्योग का यानी सारी बिजली कंपनियों का राष्ट्रीकरण हो जाना चाहिए. भारत सरकार की आज की नीति जो करना भी चाहती है और नहीं भी करना चाहती, राष्ट्र को किंकर्तव्यविमूढ़ बना देती है और यह निश्चय ही अवांछनीय है.

जिन-जिन संस्थाओं का राष्ट्रीकरण हुआ है, उसकी व्यवस्था में जो पूंजीवादी मुनाफ़ा वृत्ति घुसी हुई है, उसका आमूल खंडन होना ही चाहिए. राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र के हित के लिए, सर्वसाधारण की चीज़ है, उसे कोई भी ऑफिसर या ओहदेदार अपनी बपौती क्यों समझे? सरकारी अफ़सरों के भी आदर्श पूंजीवादी ढंग के ही हैं. उन्होंने भी अपने कारनामों द्वारा देश का शोषण करके करोड़ों रुपये इकट्ठे कर लिए हैं. आज वे भी यही समझते हैं कि मौक़ा हाथ आ गया, क्यों न हम भी करोड़पति बन जाएं? निश्चित ही है कि अवैध मार्गों का अनुसरण किए बिना नौकरशाही के लोग कभी करोड़पति बन नहीं सकते. परिणामस्वरूप भयंकर भ्रष्टाचार फैलता है. पूंजीवादियों या धनिकों की तरह पांचों अंगुली घी में वाली कहावत यहां भी चरितार्थ होती है.

feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

हमारी सहिष्णुता कम हो रही है

प्रेसीडेंट बुश के ऊपर जूता क्या चला, सारी दुनिया में जूतों की बहार आ गई. हमारे देश में भी यह दूसरा या तीसरा वाक़िया है, जब राजनेताओं के ऊपर हमले हुए. जनार्दन द्विवेदी पर जूता फेंका गया और अब शरद पवार को एक शख़्स ने थप्पड़ मारा. ये घटनाएं दो तरह के संकेत देती हैं. पहला संकेत यह है कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों से नौजवानों का भरोसा उठ रहा है. उन्हें यह लगता है कि धरना-प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सिविल नाफ़रमानी, ये शब्द बेमानी हो गए हैं और इनके ऊपर अमल करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है. ख़ासकर, सरकारें इन तरीक़ों से कही हुई बात नहीं सुनतीं. किसी भी प्रदेश की राजधानी चले जाएं तो वहां आपको दो साल से, कहीं तीन साल से, कहीं पांच साल से तंबू लगाए अपनी मांगों की फ़रियाद सरकार के कानों तक पहुंचाने के लिए अनशन करते लोग मिल जाएंगे. लेकिन बड़े पैमाने के आंदोलन नहीं हो रहे हैं. बड़े पैमाने के आंदोलन से मतलब, किसी भी एक मुद्दे को लेकर राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन या जनता का कोई एक वर्ग संगठित होकर अपनी बात कहे, ऐसा दिखाई नहीं देता. जो चीज़ें दिखाई देती हैं वे हैं, जाति के समर्थन में उठी हुई आवाज़ें. चाहे वह जाटों की आवाज़ हो या गूजरों की आवाज़. इस तरह के जातिगत समूहों की आवाज़ें जब उठती हैं तो लोग इकट्ठे होते हैं, सड़कें भी जाम होती हैं और रेलें भी रोकी जाती हैं. कुछ लोग घायल होते हैं, कुछ मरते हैं. सरकार आश्वासन दे देती है और मांगें वहीं की वहीं अपना दम तोड़ देती हैं. दक्षिण में जनांदोलन अवश्य दिखाई दे रहा है और वह है तेलंगाना का आंदोलन, जहां पर छात्र बड़े पैमाने पर चाहे वे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हों या आंध्र प्रदेश की किसी अन्य यूनिवर्सिटी के हों, वे तेलंगाना के समर्थन या विरोध में सड़कों पर हैं. अभी तक लोगों के बीच आपस में लड़ाई नहीं हुई है. पर सरकार के मुक़ाबले तेलंगाना के विरुद्ध और तेलंगाना के समर्थन में आंदोलन ज़रूर हो रहा है.

इससे यह भी साफ़ पता चलता है कि राजनीतिक दल अब कोई मांग नहीं कर रहे हैं तो लोगों को स्वयं अपनी मांगों के लिए खड़ा होना पड़ रहा है और वे संगठित रूप से नहीं, क्योंकि संगठन का आज के दौर में कोई मतलब रह नहीं गया है. अब तो चुनावों में भी कार्यकर्ता नहीं मिलते, बल्कि पैसे देकर लाए हुए एजेंट मिलते हैं. या पैसे देकर ख़रीदे हुए कार्यकर्ता चुनाव में काम करते हैं. राजनीति में कार्यकर्ता शब्द का मतलब धीरे-धीरे बदल रहा है. इसलिए कुछ अपनी मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल कर रहे हैं, कुछ धरने पर बैठे हुए हैं और जो यह सब नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, वे आत्महत्या कर लेते हैं. कुछ बंदूक़ भी उठा लेते हैं. और बंदूक़ उठाने वाले लोगों को हम नक्सलाइट के नाम से जानते हैं.

शरद पवार को लगे थप्पड़ का दूसरा संकेत भी है. संकेत है कि यह सरकार ऐसी स्थिति पैदा कर रही है, जिससे लोग उत्तेजित हों और इतने उत्तेजित हों कि देश एक गहरी अशांति में डूब जाए. ये बातें मैं बहुत ख़ुशी से नहीं कह रहा हूं. इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दस साल नहीं, बल्कि पिछले बीस साल को देखें तो सरकार ने लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना तो बंद ही कर दिया है, साथ ही स्वयं ही समस्याएं पैदा कर रही है. खाद, बीज, पानी, बिजली, जो किसान के लिए सबसे आवश्यक तत्व हैं, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके परिवार के लिए, इस देश की ग्रामीण संरचना के लिए, उन्हीं सारी चीज़ों को सरकार दिनोदिन महंगा करती चली जा रही है. योजना आयोग यह कहता है कि हम इस पर से सब्सिडी हटाएंगे, क्योंकि ऐसा विश्व बैंक या अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष का रोड प्लान है. सब्सिडी अगर आप हटाते हैं, हम आपको मना नहीं करते, सब्सिडी आप क्यों देते हैं. लेकिन लागत मूल्य में जो बढ़ोत्तरी आप करवा रहे हैं, वह तो आप कम करवा सकते हैं. पर हो यह गया है कि उत्पादन करने वाले लोगों को मिलने वाले कच्चे माल को सस्ता करने या उन्हें वह माल सही क़ीमत पर उपलब्ध हो, इन सब बातों पर सरकार का न तो कोई नियंत्रण है और न ही इससे संबंधित कोई योजना है. परिणाम स्वरूप इस देश का उत्पादक वर्ग, जिसमें किसान और मज़दूर दोनों आते हैं, आज सर्वाधिक निराश है. ऐसे में जनता क्या करे? सरकार नए-नए फ़ैसले ले रही है. नया फ़ैसला वॉलमार्ट का है. पहले आपने सब्ज़ी के क्षेत्र में बड़ी कंपनियों के लिए रास्ता खोला. अब उनसे भी बड़ी कंपनी के लिए, जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां है, जैसे वॉलमार्ट, आपने हिंदुस्तान के दरवाज़े खोल दिए हैं. जब से ये बड़ी दुकानें सब्ज़ी के क्षेत्र में आईं, तब से सब्ज़ी में ज़्यादा ज़हर मिलना शुरू हो गया है और ये

शरद पवार को लगे थप्पड़ का दूसरा संकेत भी है. संकेत है कि यह सरकार ऐसी स्थिति पैदा कर रही है, जिससे लोग उत्तेजित हों और इतने उत्तेजित हों कि देश एक गहरी अशांति में डूब जाए. ये बातें मैं बहुत ख़ुशी से नहीं कह रहा हूं. इसलिए कह रहा हूं कि पिछले दस साल नहीं, बल्कि पिछले बीस साल को देखें तो सरकार ने लोगों की समस्याओं पर ध्यान देना तो बंद ही कर दिया है, साथ ही स्वयं ही समस्याएं पैदा कर रही है. खाद, बीज, पानी, बिजली, जो किसान के लिए सबसे आवश्यक तत्व हैं, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके परिवार के लिए, इस देश की ग्रामीण संरचना के लिए, उन्हीं सारी चीज़ों को सरकार दिनोदिन महंगा करती चली जा रही है.

बड़ी खुदरा दुकानों की चेन जब मल्टीनेशनल यहां लेकर आएंगे तो हमारे सामने और क्या मुसीबतें आएंगी, कहा नहीं जा सकता. लेकिन एक मुसीबत तो सामने दिखाई दे रही है. फ्रेश सब्ज़ी के नाम की चेन से जिस तरह बेरोज़गारी बढ़ी, उससे ज़्यादा बेकारी हिंदुस्तान के खुदरा क्षेत्र में विदेशी पूंजी की अनुमति के बाद अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोगों के लिए बढ़ेगी. वॉलमार्ट एक कंपनी है. वॉलमार्ट जैसी कम से कम डेढ़ सौ कंपनियां हैं, जो हिंदुस्तान में भूखे भेड़िए की तरह कूदने वाली हैं. यह वॉलमार्ट कल्चर देश की आठ से दस प्रतिशत जनता के लिए है. अभी जितने भी फ़ैसले हो रहे हैं, वे केवल आठ से दस प्रतिशत जनता के लिए हैं. कुछ लोगों का कहना है कि यह फ़ैसला पांच प्रतिशत के लिए है. अगर थोड़ी ढील देकर देखें तो यह कहीं आठ या दस प्रतिशत के पास पहुंचता है. हिंदुस्तान के 90 प्रतिशत लोग लाभान्वित नहीं होते और वे देश के आठ से दस प्रतिशत लोगों के लिए बने इन भव्य बाज़ारों, भव्य दुकानों, भव्य कारों और भव्य भवनों को टुकुर-टुकुर देखते हैं, तो हमें डर नहीं लगना चाहिए कि कल इनके ऊपर पत्थर पड़ सकते हैं. कल इनमें लूट हो सकती है. कल इनमें घुसपैठ हो सकती है. यह डर हमें क्यों नहीं लगता? शायद इसलिए नहीं लगता, क्योंकि जो लोग ये फ़ैसले लेते हैं, वे पुलिस के पहरे में रहते हैं. उनके घर के आसपास बिजली के तारों की बाड़े हैं, वे पब्लिक के बीच अब जाते ही नहीं हैं कि उन्हें विरोध का डर हो. अब वे उन्हीं जगहों पर जाते हैं, जहां जनता न हो. लेकिन इसके बावजूद कहीं तो जाना पड़ता है. आप शादी में जाएंगे, किसी राजनीतिक समारोह में जाएंगे. अगर आप नहीं संभलेंगे तो शरद पवार जी के साथ जो हुआ, वह कई और लोगों के साथ भी हो सकता है. कुछ लोग कह सकते हैं कि यह राजनीतिक मसला है. कुछ लोग कह सकते हैं, यह एक निराश व्यक्ति की हताशा है. लेकिन व्यक्ति निराश क्यों होता है, हताश क्यों होता है? इस पर राजनीतिक तंत्र में शामिल सभी लोगों को सोचना चाहिए.

इस देश की जनता 120 करोड़ के आसपास है. हम अगर इन 120 करोड़ में से 100 करोड़ लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे और सिर्फ़ 10 या 12 करोड़ लोगों का ध्यान रखेंगे और उन्हीं के लिए सारी नीतियां बनाएंगे तो परेशानी तो होगी ही. इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरद पवार जी के साथ हुआ व्यवहार या जनार्दन द्विवेदी के साथ हुआ व्यवहार अत्यंत निंदनीय है. यह बताता है कि हमारी सहिष्णुता कम हो रही है, पर आदमी सहिष्णु रहे तो आख़िर कब तक? यह संकेत है, जिसे अगर हमारे राजनीतिज्ञ समझ लें तो हम यह मानेंगे कि उनमें थोड़ी बुद्धि बची हुई है. वरना इस देश को चलाने वाले अर्थशास्त्री, इस देश के विपक्ष में बैठे जनता से कटे नेता और वे सरकारी अधिकारी, जो इन दिनों काम ही नहीं कर रहे हैं और जो राजनेताओं को भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं. ये सब मिलकर इस देश में इतना तनाव बढ़ाएंगे कि देश गृहयुद्ध की तरफ़ चला जाएगा. आज, विद्रोह या गृहयुद्ध की बात करना सपने जैसा लगता है. लेकिन कोई शरद पवार को थप्पड़ मारे. इसके बारे में भी आज से पांच या दस दिन पहले कोई नहीं सोच सकता था कि शरद पवार जैसा क़द्दावर नेता बात करके उतर रहा है और उन्हीं की सभा में बैठा कोई व्यक्ति उनको तमाचा मार देता है. ऐसी घटनाएं बढ़नी नहीं चाहिए. लेकिन ये घटनाएं न बढ़ें, इसके लिए राजनीतिज्ञों को भी पहल करनी चाहिए. अगर पहल नहीं करेंगे तो मेरा यह मानना है कि कहीं कोई सुरक्षित नहीं है और गोली की जगह आज लोग हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि गोली लेकर तो कोई जा नहीं सकता. पर हाथ में ब्लेड लेकर तो आदमी जा सकता है. क्या होता, अगर ब्लेड की खरोंच शरद पवार के ऊपर लग जाती?

यहां एक दुखद पहलू है, अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया. अन्ना हजारे को लोग बहुत इज्ज़त और आदर के साथ देखते हैं. अन्ना हजारे के कहे हुए एक-एक वाक्य का लोग समर्थन करते हैं. अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति, जो देश में नई आशाओं को पैदा करने में महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया बहुत लोगों को पसंद आई और बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आई. पर अन्ना हजारे की प्रतिक्रिया के जवाब में शरद पवार की यह प्रतिक्रिया कि मैंने नए गांधीवादी की बात सुनी और समझा और उन्होंने अन्ना हजारे का नाम लेकर कोई हमला नहीं किया. इस मसले में शरद पवार की तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए. लेकिन शरद पवार की ज़िम्मेदारी बनती है, वह सरकार के एक ज़िम्मेदार मंत्री हैं, उनकी सरकार ऐसे फ़ैसले न ले, जिससे लोग निराश होकर क़ानून अपने हाथ में ले लें और शरद पवार की बिरादरी के लोगों को जहां भी देखें वहां उन पर कटाक्ष करें. इसकी ज़िम्मेदारी शरद पवार जी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, लालकृष्ण आडवाणी और फिर मुलायम सिंह, लालू यादव जैसे लोगों की है. अगर ये नहीं चेतेंगे तो इन्हें ऐसी घटनाओं का सामना कहीं भी करना पड़ सकता है, जो देश के लिए दुखद भी है और शायद शर्मनाक भी.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

कमल मोरारका का ब्लॉग

www.kamalmorarka.com

प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

प्रेस काउंसिल के नए चेयरमैन ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, जिसकी वजह से मीडिया में अफ़रा-तफ़री का माहौल बन गया. इसके पीछे प्रेस काउंसिल का मक़सद सिर्फ़ इतना था कि वह प्रेस के क्रिया- कलापों व मानकों पर नज़र रख सके और अपने सीमित अधिकारों के सहारे शिकायतों को देख सके. आशा के अनुरूप ही यह संस्था भी दंतविहीन साबित हुई. कोई व्यक्ति अगर अपने ख़िलाफ़ छपी आपत्तिजनक या ग़लत ख़बर से नाख़ुश है, तो उसे ख़ुद को पाक-साफ़ साबित करने के लिए अदालत की शरण में जाना पड़ता है. जिस प्रकार की क़ानूनी प्रक्रिया हमारे देश में है, उसमें तो उस व्यक्ति को न्याय मिलने में ही 10 से 15 साल लग जाएंगे. प्रेस काउंसिल के नए चेयरमैन ने दो नई बातें कही हैं. एक तो प्रेस काउंसिल को और अधिकार देने की, जिससे वह कड़ी कार्रवाई कर सके और दूसरी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी प्रेस काउंसिल के दायरे में लाने की. प्रेस काउंसिल द्वारा उठाए गए ये मुद्दे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस पर बहस की गुंजाइश भी है, ताकि सर्वसम्मति बनाई जा सके. क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है? क्या स्वीकार्य है, क्या स्वीकार्य नहीं है? क्या उचित है, क्या अनुचित है? ये सारी बातें समय और समाज के अनुसार बदलती रहती हैं. भारत में कई ऐसे लोग हैं, जो यह मानते हैं कि फिल्म सेंसरशिप को ख़त्म कर देना चाहिए और लोगों को जो वे चाहे देखने और दिखाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए. लेकिन साथ ही इस देश में मोरल पुलिस का रोल निभा रहे ऐसे लोग भी हैं, जो एमएफ हुसैन की पेंटिंग प्रदर्शनी का विरोध करते हैं, क्योंकि हुसैन ने एक हिंदू देवी की नग्न तस्वीर बनाई थी. जबकि विरोध कर रहे लोग यह भूल जाते हैं कि खजुराहो और

प्रेस काउंसिल के नए चेयरमैन ने दो नई बातें कही हैं. एक तो प्रेस काउंसिल को और अधिकार देने की, जिससे वह कड़ी कार्रवाई कर सके और दूसरी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी प्रेस काउंसिल के दायरे में लाने की. प्रेस काउंसिल द्वारा उठाए गए ये मुद्दे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इस पर बहस की गुंजाइश भी है, ताकि सर्वसम्मति बनाई जा सके. क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है? क्या स्वीकार्य है, क्या स्वीकार्य नहीं है? क्या उचित है, क्या अनुचित है? ये सारी बातें समय और समाज के अनुसार बदलती रहती हैं.

कोणार्क में ऐसे चित्रण बख़ूबी हुए हैं. अन्ना हजारे के गांव में एक व्यक्ति को शराब पीने के कारण लोग मंदिर के सामने पोल से बांधकर पीटते हैं. क्या हम यही चाहते हैं? निश्चित तौर पर प्रेस पर सेंसरशिप नहीं लगनी चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति, यदि उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है, की शिकायत सुनने और उसके निवारण के लिए एक सशक्त संस्था का होना ज़रूरी है. हमारे देश में अमेरिका की तरह संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं है. भारतीय संविधान में अनुच्छेद-19 है, जो एक आम आदमी को अभिव्यक्ति व भाषण की स्वतंत्रता देता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को विस्तार देते हुए प्रेस को भी इसमें शामिल कर दिया. एक व्यक्ति के लिए यह अधिकार अलग बात है, जबकि प्रेस के लिए अलग. लेकिन इसे स्वीकार कर लिया गया है. क्या हम यह कहते हैं कि प्रेस काउंसिल को भंग कर देना चाहिए? क्या हम यह कहते हैं कि इसे और शक्तिशाली व अधिकार संपन्न बनाना चाहिए? या हम यह कहते हैं कि प्रेस कांउसिल को ऐसे ही एक अप्रभावी संस्था के रूप में चलते रहने देना चाहिए?

feedback@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

यूरोप का लोकतंत्र ख़तरे में

लोकतंत्र की जन्मभूमि ग्रीस में पिछले दिनों इसके साथ मज़ाक़ हुआ. लोकतांत्रिक तरीक़े से चुने गए प्रधानमंत्री जॉर्ज पापेंद्रु को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया गया. पापेंद्रु ग्रीस की समाजवादी पार्टी पासोक के नेता हैं तथा उनके पिता और दादा ग्रीस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं. ग्रीस के प्रधानमंत्री की ग़लती यही थी कि उन्होंने आर्थिक संकट से जूझ रहे ग्रीस के क़र्ज़ की वापसी के लिए जनमत संग्रह कराकर जनता को इसमें सहभागी बनाने का प्रयास किया था. यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था. अगर ग्रीस आर्थिक संकट से जूझ रहा था तो फिर उसे यह अधिकार है कि किस तरह से वह इससे बाहर निकले या वह दिवालिया हो जाए. ऐसा ही आइसलैंड के साथ हुआ था. यह देश बैंकों के दुर्व्यवहार के कारण क़र्ज़ में डूब गया था. इसने अपने नागरिकों से संपर्क किया, जिन्होंने अपने क़र्ज़ वापस करने से मना कर दिया. जनमत संग्रह में विजयी होने के बाद आइसलैंड को बाज़ार द्वारा दंडित किया गया. दो वर्षों की जद्दोजहद के बाद आइसलैंड अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आया. इसके बाद के मुख्य क़र्ज़दाता ब्रिटेन और नीदरलैंड ने इस देश के क़र्ज़ की पुनर्व्यवस्था की बात स्वीकार कर ली. अब ग्रीस को देखें तो वह यूरोपीय संघ तथा यूरोजोन दोनों का सदस्य है. यूरोप के कई देशों में आए आर्थिक संकट के कारण इस संघ पर दो देशों जर्मनी और फ्रांस की दादागिरी चल पड़ी है. इसका मुख्य कारण यही है कि जर्मनी और फ्रांस की अर्थव्यवस्था पटरी पर है और उसके बैंकों ने ग्रीस को क़र्ज़ दे रखा है. इन दोनों देशों ने सभी नियम-क़ायदों को मानने से इंकार कर दिया, जिसके कारण ग्रीस में जनमत संग्रह नहीं हो सका. यही स्थिति अगर आइसलैंड के साथ होती और ब्रिटेन तथा नीदरलैंड ने इसकी सरकार को बर्ख़ास्त कर दिया होता तो विश्व स्तर पर कैसी प्रतिक्रिया हो सकती थी.

ग्रीस और इटली दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं हैं. यहां तक कि वे संसद के सदस्य तक नहीं हैं, केवल उस देश के नागरिक हैं. दोनों ही अर्थशास्त्री हैं, जिनके ऊपर अपने देश को आर्थिक संकट से उबारने की ज़िम्मेदारी है. यूरोपीय संघ में लोकतंत्र मात्र कुछ देशों की मर्ज़ी पर रह गया है. न तो यहां इस बात का डर है कि जनता सरकार के विरुद्ध उठेगी और न ही इस बात का कि वहां सेना लोकतंत्र के विरुद्ध कोई क़दम उठाएगी. वहां के देशों को संघ के कुछ देशों से डर है.

इसी तरह की घटना इटली में भी घटी. इटली के प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी को इस कारण जाना पड़ा, क्योंकि इटली के बॉन्ड की साख समाप्त होती जा रही थी. ग्रीस और इटली दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं हैं. यहां तक कि वे संसद के सदस्य तक नहीं हैं, केवल उस देश के नागरिक हैं. दोनों ही अर्थशास्त्री हैं, जिनके ऊपर अपने देश को आर्थिक संकट से उबारने की ज़िम्मेदारी है. यूरोपीय संघ में लोकतंत्र मात्र कुछ देशों की मर्ज़ी पर रह गया है. न तो यहां इस बात का डर है कि जनता सरकार के विरुद्ध उठेगी और न ही इस बात का कि वहां सेना लोकतंत्र के विरुद्ध कोई क़दम उठाएगी. वहां के देशों को संघ के कुछ देशों से डर है. यूरोपीय संघ असमान देशों का संगठन बनकर रह गया है. अमीर देशों के इस संघ में अधिक अमीर देश यह तय करने लगे हैं कि किस देश पर कौन शासन करेगा. सोचने वाली बात यह है कि आख़िर ऐसा क्यों हो रहा है.देखा जाए तो इसका प्रमुख कारण वैश्वीकरण है. कुछ लोगों का कहना है कि वैश्वीकरण के इस दौर में कोई भी देश आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है. पहले के समय में देश क़र्ज़ लेते थे, लेकिन जब वे इस क़र्ज़ को चुकाने की स्थिति में नहीं होते तो मुद्रा छाप लेते थे और क़र्ज़दाता देशों को धोखा देते थे. लेकिन आजकल ऐसा करना संभव नहीं है, क़र्ज़ प्रायः नागरिकों का पेंशन होता है. वे लोग देशी या विदेशी क़र्ज़दाताओं से क़र्ज़ लेते हैं. यह आधुनिक समय की आवश्यकता है. सरकार आजकल एक बड़ी कंपनी से अधिक कुछ नहीं है तथा इसकी विश्वसनीयता हर दिन बाज़ार तय करती है. कोई भी देश अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ क़र्ज़ ले सकता है, लेकिन इसके बाद उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है. पिछले पंद्रह वर्षों से हम वैश्वीकरण का लाभ उठा रहे हैं. आसनी से क़र्ज़ लेकर ख़र्च कर रहे हैं. घर बैठे हमें क़र्ज़ मिल जाता है. लेकिन इसका परिणाम क्या होता है. भारत के संदर्भ में देखें तो 1991 के बाद इसकी विकास दर काफ़ी आश्चर्यजनक रही है. यह वैश्वीकरण के बिना संभव नहीं था. लेकिन देखा जाए तो विकास के साथ-साथ इस पर क़र्ज़ का बोझ भी बढ़ा है. हमारे ऊपर इतना क़र्ज़ है कि हमारे कर राजस्व का एक तिहाई भाग लिए गए क़र्ज़ का ब्याज़ चुकाने में चला जाता है, जो कि ग्रीस से अधिक है. पिछले तीन सालों से भारत में मुद्रास्फीति की दर जीडीपी वृद्धि दर से अधिक रही है. हर दिन इसे कम करने के वायदे किए जाते हैं. अगर भारत का ग्रोथ रेट पांच फ़ीसदी या उससे कम हो गया तो इसे बजट संबंधित संकट का सामना करना पड़ सकता है. अतः भारत को भी सावधान रहना चाहिए तथा ग्रीस आदि देशों से सबक़ लेकर सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

मनरेगा भ्रष्टाचार की गिरफ्त में

चौथी दुनिया में मनरेगा पर सियासत, पढ़ा. यह बेहद अफ़सोस की बात है कि जनहित में शुरू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना भी अन्य सरकारी योजनाओं की तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है. अगर जनता के हिस्से की धनराशि हड़पने वाले राजनेताओं, अफ़सरों और ठेकेदारों के ख़िलाफ़ सख्ती बरतने की ज़रूरत है, वरना इन योजनाओं का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा.

दानिश, *उन्नाव, उत्तर प्रदेश*

मीडिया का गिरता स्तर

टीवी चैनलों का स्तर दिनोदिन गिरता जा रहा है. हालत यह हो गई है कि अब तो परिवार के साथ टीवी देखना भी मुश्किल हो गया है. एक टीवी चैनल पर प्रसारित बिग बॉस के घर में अब तो पोर्न स्टार तक पहुंच चुकी है. हालांकि शो के पिछले सीजन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शो के कंटेंट पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि यह बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है. उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों को शाम पांच से 11 बजे तक न दिखाने की सलाह दी थी. आज जब समाज में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस तरह के कार्यक्रमों ने उन्हें बढ़ाने का ही काम किया है. सरकार को ऐसे टीवी चैनलों के प्रति सख्ती बरतनी चाहिए.

हिमांशु, *दिल्ली*

क़ानून पर सियासत

चौथी दुनिया में कश्मीर : सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, देश सर्वोपरि है राजनीति नहीं, पढ़ा. पता चला कि किसी भी क़ानून को लेकर किस तरह से सियासी पार्टियां राजनीति करती हैं. किसी को भी देश की सुरक्षा का ख्याल नहीं है. होना तो यह चाहिए कि इस बात पर चर्चा हो कि इस क़ानून का दुरुपयोग कैसे रोका जाए, न कि इस पर सियासत होनी चाहिए. हालांकि क़ानून के दुरुपयोग को लेकर देश में कई संगठन आवाज़ उठाते रहे हैं, इसलिए यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए. आज देश की जो स्थिति है, उसे देखते हुए कई इलाक़ों में ऐसे क़ानूनों की बेहद ज़रूरत है.

ज्योति, *सागरपुर, दिल्ली*

मुसलमान जागरूक हों

भारत विभाजन की सर्वाधिक हानि यदि किसी समुदाय को हुई है, तो वह समुदाय भारतीय मुसलमानों का है. इससे उनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन प्रभावित हुआ है. राजनीतिक पार्टियों ने मुसलमानों को ख़ूब ठगा. इसकी शुरुआत सबसे पहले अगस्त 1950 में राष्ट्रपति आदेश लागू कर धारा 341 के अनुसार धर्म के आधार पर दलित मुसलमानों पर सरकारी नौकरियों में प्रतिबंध लगाने से हुई. वे सरकारी नौकरियों में अपना प्रतिनिधित्व गवाते रहे, लोकसभा एवं विधानसभाओं में उनका प्रतिशत कम होता रहा. मुसलमानों की कुल अर्थव्यवस्था, मुर्ग़ी पालन, बकरी पालन, सुरमा उद्योग, अंडों का व्यापार सहित कुछ लघु एवं कुटीर उद्योगों तक सीमित रह गई. कम्युनिस्ट पार्टियां भारत में मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी होने का दावा करती रहीं, लेकिन बंगाल में उनके 34 वर्षों के शासनकाल में मुसलमान सबसे ज़्यादा ग़रीब हो गए. ऐसा ही हाल लालू के शासन में बिहार के मुसलमानों का हुआ. उत्तर प्रदेश में मुलायम एवं मायावती के शासनकाल में भी सरकारी सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिशत घटा है. ऐसी हालत में मुसलमानों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर सियासी दलों पर दबाव बनाना होगा.

शहरयार जलालपुरी, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश*

शोषित नारी

महिलाओं पर हर प्रकार के अन्याय और अत्याचार के प्रति समाज में सहनशीलता का वातावरण है. विकास और समानता के नाम पर उसे उपभोग-सामग्री बना दिया गया है. आज महिला घर से बाहर तक, कहीं सुरक्षित नहीं. पत्नी के रूप में घरेलू हिंसा का शिकार है, बेटी के रूप में पिता की जायदाद से वंचित की जाती है. स्कूल-कॉलेज हो या कार्यस्थल, हर जगह शोषण का शिकार बनती है. हालत यह है कि जन्म से पूर्व ही कन्या-भ्रूण के रूप में उसकी हत्या सभ्य समाज में हत्या नहीं समझी जाती.

मो. रफ़ीक चौहान, *ईमेल से*

श्रीलाल शुक्ल का जाना

कम पाठकों के लिए श्रीलाल शुक्ल जी के जाने का मतलब हिंदी व्यंग्य विधा के शीर्षस्थ व्यक्तित्व की अनुपस्थिति से है. यद्यपि मृत्यु अवश्यंभावी है, तथापि दुख इसलिए होता है कि शुक्ल जी जैसे लोगों की समसामयिक उपस्थिति, उनके चित्र, वक्तव्य पाठकां को मानसिक रूप से ऊर्जस्वित करते हैं, जो अब नहीं हैं. राग दरबारी उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें उन्होंने व्यंग्य के माध्यम से गंभीर साहित्य का सृजन किया है.

विनय कुमार सिंह, *गांव मोहबत छपरा, ज़िला पूर्वी चंपारण, बिहार*

राजकमल प्रकाशन समूह

राजकमल प्रकाशन राधाकृष्ण लोकभारती प्रकाशन

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय समिति के ताज़ातरीन अनुमानों सहित ज़्यादातर मॉडलों में हाल के दिनों में बर्फ़ के सिकुड़ने के हिसाब से इसके समाप्त होने की गणना की गई है.

दिल्ली, 05 दिसंबर-11 दिसंबर 2011 चौथी दुनिया

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

आपका हथियार सूचना का अधिकार

इस क़ानून से जुड़ी सूचनाएं हम आपको लगातार देते रहते हैं. इस अंक में हम चर्चा कर रहे हैं इस क़ानून के उस पक्ष की, जिससे आमतौर पर ज़्यादातर आवेदकों का वास्ता पड़ता है. ऐसी ख़बरें भी आई हैं कि किसी आवेदक को सूचना क़ानून का इस्तेमाल करने पर धमकी मिली या जेल में ठूंस दिया गया या फ़र्ज़ी केस में फंसा दिया गया. ऐसे कुछ उदाहरण हैं, जिनमें लोगों को शारीरिक हानि पहुंचाई गई, जब उन्होंने भ्रष्टाचार का बड़े पैमाने पर पर्दाफ़ाश किया. लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रार्थी को हमेशा ऐसा भय झेलना होगा. अपनी शिकायत की स्थिति या मामलों की जानकारी लेने के लिए अर्ज़ी लगाने का अर्थ आ बैल मुझे मार नहीं है. ऐसा तब होता है, जब कोई सूचना नौकरशाह– ठेकेदार की मिलीभगत या किसी माफ़िया का पर्दाफ़ाश करती हो. ज़ाहिर है, सालों से ज़ंग लगी व्यवस्था और सामंती मानसिकता वाली नौकरशाही इस बात को हज़म नहीं कर पाती कि कोई आम आदमी उनसे सवाल पूछे. आम आदमी उनकी सत्ता को चुनौती न दे सके या सवाल न पूछ सके, इसलिए सत्ता और प्रशासन में बैठे लोग अपने अधिकार का बेजा इस्तेमाल करके ऐसे आवेदकों को परेशान करते हैं. लेकिन इस सबसे डरने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ी समझदारी से अगर काम लें तो ऐसी धमकियों से भी बचा जा सकता है. यदि आपने आरटीआई से किसी भ्रष्टाचार या ग़लत कार्य का पर्दाफ़ाश किया है तो आप सतर्कता एजेंसियों, सीबीआई को इस बारे में शिकायत कर सकते हैं या एफआईआर भी करा सकते हैं. लेकिन देखा गया है कि सरकार दोषी के विरुद्ध लगातार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करती. यद्यपि कोई भी सतर्कता एजेंसियों पर शिकायत की स्थिति आरटीआई के तहत पूछकर दबाव अवश्य बना सकता है. लेकिन ग़लत कार्यों का पर्दाफ़ाश मीडिया के ज़रिये भी किया जा सकता है. एक बात तय है कि इस प्रकार सूचनाएं मांगना और ग़लत कामों का पर्दाफ़ाश होने से अधिकारियों को स्पष्ट संदेश जाता है कि उस क्षेत्र के लोग अधिक सावधान हो गए हैं और भविष्य में इस प्रकार की कोई ग़लती पूर्व की भांति छुपी नहीं रहेगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

मिड डे मील योजना का विवरण

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना केअधिकार अधिनियम, 2005 केतहत आवेदन.

महोदय,
.... के प्राथमिक विद्यालय की मिड डे मील योजना के संबंध में सूचना केअधिकार के तहत निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. उपरोक्त विद्यालय में मिड डे मील योजना का विवरण निम्नलिखित ब्यौरे के साथ दें:
(क) दिनांक...........से.............के दौरान उपरोक्त स्कूल को उपलब्ध कराई गई खाद्य-सामग्री का विवरण (मासिक ब्यौरे केसाथ) उपलब्ध कराएं.
(ख) विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त खाद्य-सामग्री कितने विद्यार्थियों को वितरित की जानी थी?
(ग) यह खाद्य-सामग्री किस राशन दुकानदार/एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई?
(घ) उपरोक्त दुकान/एजेंसी का चुनाव किस प्रकार किया गया? इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नियमों/आदेशों/दिशा-निर्देशों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं.
(ङ) इस दौरान विभाग द्वारा विद्यालय को खाद्य-सामग्री उपलब्ध कराने से संबंधित सभी आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी उपलब्ध कराएं.

2. मिड डे मील योजना को बेहतर ढंग से लागू कराने एवं गुणवत्ता बनाए रखने से संबंधित सरकार व विभाग द्वारा जारी शासनादेशों/दिशा-निर्देशों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं.

3. मिड डे मील योजना में कालाबाज़ारी/भ्रष्टाचार आदि की रोकथाम केलिए विभाग द्वारा की गई व्यवस्था से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों/नियमों/क़ानूनों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं.

4. दिनांक..........से.............के दौरान उपरोक्त विद्यालय से क्या विभाग को मिड डे मील योजना के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो शिकायतकर्ता का नाम, पता, शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण एवं यदि इस संबंध में कोई जांच की गई है तो जांच रिपोर्ट की प्रति भी उपलब्ध कराएं.

5. मिड डे मील योजना के अंतर्गत स्वीकृत खाद्य-सामग्री यदि किसी कारणवश किसी विद्यालय द्वारा उपयोग नहीं की जाती है तो उस खाद्य-सामग्री के निष्पादन की विभाग ने क्या व्यवस्था की है? इससे संबंधित नीतियों/दिशा-निर्देशों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं.

6. मिड डे मील योजना से संबंधित विभिन्न नियमों, निर्देशों, आदेशों एंव सर्कुलर की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं.

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बी.पी.एल. कार्डधारी हूं इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं.............है.

यदि मांगी गई सूचना आपकेविभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि केअंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम केप्रावधानों केतहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो तो)

ज़रा हट के

मेढक ज़हरीला रसायन उगलते हैं

एक नए अध्ययन के मुताबिक़ समुद्री मेंढक अपना वजूद बचाने के लिए अपनी बिरादरी के अन्य मेंढकों के ख़िलाफ़ एक ख़ास तरह का ज़हरीला रसायन उगलते हैं, क्योंकि उनके बीच भी अस्तित्व की लड़ाई होती है. अपना वजूद बचाने के लिए मेंढक एक-दूसरे की जान ले लेते हैं. सिडनी विश्वविद्यालय के जीव वैज्ञानियों ने पाया कि ये समुद्री मेंढक जल में एक ख़ास तरह का रसायन उगलकर एक-दूसरे से संपर्क साधते हैं और अपना वजूद बचाने के लिए एक-दूसरे की जान ले लेते हैं. इस तथ्य से शहरी इलाक़ों में उनकी संख्या को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी. अध्ययन दल के प्रमुख जीव वैज्ञानी रिक शाइन ने बताया कि समुद्री मेंढक रसायन उगलते हैं, जो जल के ज़रिये अन्य मेंढकों तक पहुंचता है और इस आधार पर वे निर्णय करते हैं. प्रो. शाइन ने बताया कि मेंढक अपने विकास के चरण में यदि बार-बार इन रसायनों को ग्रहण करते हैं तो संभवत: तनाव से उनकी मौत हो जाती है. इसके अलावा उनके ताज़ा अंडों से एक ख़ास तरह का रसायन निकलता है, जो दूसरे मेंढकों को बीमार कर देता है और उनके अंडों को नष्ट कर देता है. इस आकर्षणकारी रसायन का बड़ा फ़ायदा यह है कि भविष्य के प्रतिद्वंद्वियों का सफ़ाया कर देता है, क्योंकि एक समुद्री मेंढक ही दूसरे मेंढक का कट्टर दुश्मन होता है. उन्होंने बताया कि हम इन रसायनों को प्राप्त कर सकते हैं और मेंढकों को फंसाने के लिए जाल बुन सकते हैं.

बर्फ़ ख़ात्मे की कगार पर

आर्कटिक सागर पर सफ़ेद बर्फ़ की मोटी चादर जल्द ही अतीत का हिस्सा बन सकती है. ब्रिटेन के एक शीर्ष महासागर विशेषज्ञ ने दावा किया है कि 2015 के ग्रीष्म तक वहां से बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी. बर्फ़ कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रो. पीटर वधाम्स के मुताबिक़, आर्कटिक सागर की बर्फ़ इतनी तेज़ी से सिकुड़ रही है कि अगले चार साल में ही यह समाप्त हो सकती है. इससे ध्रुवीय भालू जैसे जानवरों केलिए प्राकृतिक आवास की समस्या खड़ी हो जाएगी. उत्तरी रूस, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में पसरी यह बर्फ़ मौसम के साथ घटती-बढ़ती रहती है. फ़िलहाल यह 40 लाख वर्ग किलोमीटर के आकार में सिमट गई है. जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय समिति के ताज़ातरीन अनुमानों सहित ज़्यादातर मॉडलों में हाल के दिनों में बर्फ़ के सिकुड़ने के हिसाब से इसके समाप्त होने की गणना की गई है. हालांकि वधाम्स का कहना है कि ऐसे अनुमान जलवायु परिवर्तन के तेज़ी से पड़ने वाले असर के सटीक आकलन में नाकाम रहते हैं. उनका कहना है कि उनका मॉडल सर्वश्रेष्ठ है. यह दिखाता है कि बर्फ़ के घनत्व में गिरावट इतनी तेज़ी से हो रही है कि बहुत जल्द ही यह शून्य केस्तर पर पहुंच जाएगा. 2015 का अनुमान बेहद गंभीर अनुमान है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह के आरंभ में विशेष प्रयासों के बावजूद भी लाभ मार्ग अवरुद्ध रहेगा. स्वभाव में भी मायूसी प्रकट होगी. यह सप्ताह कई रंग बदलेगा. पहले नए काम में कुछ रुकावट महसूस करेंगे, लेकिन समय बीतने के साथ-साथ काम बनते नज़र आएंगे.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह के आरंभ में यदि आप साहस और धैर्य पूर्वक कार्य करें तो सफलता मिलने की पूरी संभावना है. आपके प्रॉपर्टी के मामले हल हो सकते हैं. कमाई में बढ़ोत्तरी होगी, लेकिन साथ ही ख़र्च के बहाने भी मिल जाएंगे. आपका अच्छा मूड ख़राब माहौल में भी ताज़गी भर देगा.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
इस सप्ताह के आरंभ में उत्साहजनक समाचार मिलते रहेंगे. आपके सहयोगी कुछ रिलैक्स मूड में रहेंगे और पहले से ज़्यादा काम करने की इच्छा जताएंगे. बदलाव के तौर पर आप अपने अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और कामयाब भी होंगे.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
इस सप्ताह के आरंभ में मामूली प्रयासों के बावजूद लाभ मार्ग प्रशस्त रहेगा. सहसा ही ख़ुशी का समाचार मिलेगा. सप्ताह की शुरुआत थोड़ी बेचैनी से होगी. जो काम आप करेंगे, वह इसी बेचैनी के चलते होगा. ऐसे में महसूस होगा कि आपने एक ही दिन में ढेर सारे लटके हुए काम निपटा लिए हैं.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
इस सप्ताह के आरंभ में घर के सदस्यों के साथ वैर-विरोध अथवा उच्चाधिकारियों से तनावपूर्ण संबंध समय-समय पर बनते ही रहेंगे. ऑफिस में साथियों का और घर में अपने से छोटे सदस्यों का सहयोग मिलेगा. सप्ताहांत में खान-पान में सावधानी बरतना ज़रूरी है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
इस सप्ताह के आरंभ में कुछ चिंताओं को छोड़कर समय अच्छा व्यतीत होगा. छिटपुट लाभ से ही संतोष कर लेना चाहिए. आपको कुछ समय पहले खोई हुई कोई ख़ास चीज़ मिल सकती है. किसी को बहुत पहले दिया गया उधार इस सप्ताह के मध्य तक वापस मिल जाएगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह के आरंभ में कार्य सिद्धि के प्रसंग प्रबल होंगे. अच्छे-अच्छे समाचार मिलेंगे. इस सप्ताह के मध्य तक किसी सौदे या लेन-देन के दौरान टेंशन न लें. बढ़ते ख़र्च को क़ाबू में करना काफ़ी कठिन लगेगा, लेकिन थोड़ी-सी इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस सप्ताह के आरंभ में व्यापार में प्रयासों से स्त्री वर्ग का सहयोग मिलेगा. रुका हुआ धन भी मिलेगा. सभी कार्य समय पर हो जाएंगे. इस सप्ताह का मध्य आपके लिए परीक्षा जैसा है. मेहनत से जो कुछ भी करेंगे, वह काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
इस सप्ताह के आरंभ में जिस तरह सुर और ताल के बिना संगीत मधुर नहीं होता है, वैसे ही परिश्रम और युक्ति के बिना सफलता भी संतोष नहीं देती है. ऑफिस में हर तरह की रुकावटों और अड़चनों को आप अपने सीनियर्स की मदद से हटाते रहेंगे. माहौल संतोषजनक रहेगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
इस सप्ताह के आरंभ में धर्म कर्म में अभिरूचि रहेगी. वरिष्ठ सदस्यों की आज्ञा का अनुपालन करना ज़रूरी होगा. आप सोशल वर्क के ज़रिए कुछ उद्देश्य हासिल करेंगे. ऑफिस का माहौल काम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा. जीवनसाथी से सपोर्ट मिलता रहेगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
इस सप्ताह के आरंभ में ख़रीद-फ़रोख्त अथवा लेन-देन के मामलों में उलझे रहेंगे. राजकीय संदर्भ भी गतिविधियों को प्रभावित करेंगे. इस सप्ताह के मध्य में सोसायटी में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. इसके लिए कोई आयोजन हो सकता है.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
इस सप्ताह के आरंभ में आर्थिक तंगी का दबाव रहेगा या फिर अकारण भय और बेचैनी महसूस होगी. ज़रा सी भूल या ग़लतियों की भारी क़ीमत चुकानी पड़ेगी. सप्ताह मध्य में ऑफिस के वर्तमान माहौल में आपके लिए मन लगाना कुछ मुश्किल हो सकता है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

मिस्र के सबसे संगठित राजनीतिक गुट मुस्लिम ब्रदरहुड ने भी तहरीर चौक पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. हालांकि इसके विभिन्न संगठनों ने अपने मंच अलग-अलग लगाए हैं, लेकिन उनकी मांग एक ही है.

पाकिस्तानी लोकतंत्र ख़तरे में

राजीव कुमार

पाकिस्तान की लोकतांत्रिक तरीक़े से चुनी गई सरकार कमज़ोर पड़ गई है. वह चाहकर भी आतंकवादियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में रह रहे चरमपंथियों को सेना का समर्थन प्राप्त है. सेना के कुछ अधिकारी उनके प्रति नरम हैं और कठोर कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं हैं. दूसरी तरफ़ सरकार को इस बात का भरोसा नहीं है कि अगर उसने आतंकवादियों को शह देने वाले सैन्य अधिकारियों ख़ासकर सेनाध्यक्ष के कियानी के ख़िलाफ़ कोई क़दम उठाया तो उनका अस्तित्व बना रहेगा. इस बात की जानकारी एक गुप्त ज्ञापन से होती है, जिसे अमेरिका के तत्कालीन सेना प्रमुख माइकल मुलेन को सौंपा गया था. इसमें इस बात का ज़िक्र किया गया है कि ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी ने सेना की कमान बदलने और चरमपंथी संगठनों से नाता तोड़ने की बात कही थी. वह पाकिस्तान के ख़ुफ़िया तंत्र में मौजूद उस धड़े को हटाना चाहते थे, जिस पर चरमपंथियों को शह देने तथा उसके प्रति नरम रुख़ अपनाने का आरोप है. लेकिन ज़रदारी को इसके लिए अमेरिकी ताक़त की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि सेना की कमान बदलने के चक्कर में कहीं उनकी गद्दी ही ख़तरे में न पड़ जाए, यानी सैन्य विद्रोह न हो जाए. हालांकि अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत हुसैन हक्कानी ने ऐसा कोई ज्ञापन सौंपे जाने की बात से इंकार किया है. मगर पूर्व अमेरिकी सैन्य प्रमुख माइक मुलेन ने कहा है कि उन्हें एक ज्ञापन तो सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. माइक मुलेन ने ध्यान दिया या नहीं, यह तो वही बता सकते हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई पर यह आरोप लगाया था कि अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी दूतावास तथा सैनिकों पर जिस हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादियों का हमला हो रहा है, उसे आईएसआई का सहयोग प्राप्त है. हो सकता है कि मुलेन ने पाकिस्तानी राजदूत के इस गुप्त ज्ञापन के बाद यह समझ लिया हो कि इस आरोप से आईएसआई के कुछ अधिकारियों को हटाने में पाकिस्तानी सरकार को मदद मिलेगी. लेकिन उनका दांव सही नहीं पड़ा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम अमेरिका के इस हस्तक्षेप का विरोध करने लगी, जिसके बाद सरकार के सामने कोई विकल्प ही नहीं था कि वह कोई कार्रवाई कर सके.

गुप्त ज्ञापन संबंधी विवाद की शुरुआत उस समय हुई, जब पाकिस्तानी मूल के एक अमेरिकी व्यापारी मंसूर एयाज़ का एक लेख ब्रिटिश समाचार-पत्र फिनांशियल टाइम्स में छपा, जिसमें इस बात का ज़िक्र किया गया था कि पाकिस्तान सरकार के मुखिया सेना की कमान एवं आईएसआई के कुछ लोगों को जिनका आतंकवादियों के प्रति नरम रुख़ है, बदलना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें अमेरिकी ताक़त की ज़रूरत है.

गुप्त ज्ञापन संबंधी विवाद की शुरुआत उस समय हुई, जब पाकिस्तानी मूल के एक अमेरिकी व्यापारी मंसूर एयाज़ का एक लेख ब्रिटिश समाचार-पत्र फिनांशियल टाइम्स में छपा, जिसमें इस बात का ज़िक्र किया गया था कि पाकिस्तान सरकार के मुखिया सेना की कमान एवं आईएसआई के कुछ लोगों को जिनका आतंकवादियों के प्रति नरम रुख़ है, बदलना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें अमेरिकी ताक़त की ज़रूरत है. इसके बाद पाकिस्तान की राजनीति गर्म हो गई. विपक्षियों ने सरकार पर हमला शुरू कर दिया तथा संयुक्त अधिवेशन बुलाने की मांग की जाने लगी. चूंकि यह आरोप अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत हुसैन हक्कानी पर लगाया गया था, इसके कारण पाकिस्तानी सरकार ने हक्कानी को तलब किया तथा स्पष्टीकरण मांगा. साथ ही उसने संसद को आश्वासन दिया कि हक्कानी के स्पष्टीकरण के बाद ही मामला साफ़ होगा. मंसूर एयाज़ का कहना है कि उन्होंने हुसैन हक्कानी के कहने पर ही इस ज्ञापन को तैयार किया था. हक्कानी इसे अस्वीकार कर रहे हैं. उन्होंने इस्तीफ़े की पेशकश करते हुए जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है. साथ ही जांच के लिए अपना ब्लैक बेरी मोबाइल भी सौंपने की बात कही है. रहमान मलिक ने भी कहा है कि सरकारी स्तर पर कोई ज्ञापन नहीं दिया गया है, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया है कि हुसैन हक्कानी और मंसूर एयाज़ के बीच संदेश के मार्फ़त बातचीत हुई थी. ज्ञापन सौंपने की बात को एक अन्य अमेरिकी अधिकारी ने भी स्वीकार किया है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेम्स जोंस ने कहा है कि उन्होंने तत्कालीन सैन्य प्रमुख माइक मुलेन को विवादास्पद पत्र सौंपा था. उनका कहना है कि बीते मई माह में उन्होंने यह पत्र माइक मुलेन को सौंपा था, लेकिन उस समय वह अमेरिकी सरकार के अधिकारी पद पर नहीं थे.

अब प्रश्न यह उठता है कि इस रहस्योद्घाटन का निहितार्थ क्या है? इससे यह तो साबित हो गया कि ज़रदारी को इस बात का डर था कि कभी भी अशफ़ाक़ परवेज़ कियानी सत्ता पर क़ाबिज़ हो सकते हैं. पाकिस्तान का लोकतंत्र ख़तरे में हैं और सेना पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. लेकिन अगर यह ज्ञापन सच है तो इसका पर्दाफ़ाश करने के पीछे की मंशा क्या है? मंसूर एयाज़ एक व्यवसायी हैं. उन्होंने कहा है कि उनके पास 9 और 10 मई का फोन रिकॉर्ड मौजूद है, जिससे यह बात साफ़ हो जाएगी कि उसे ज्ञापन तैयार करने और अमेरिकी अधिकारी को सौंपने के लिए कहा गया था. उस ज्ञापन पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं. अगर यह घटना मई की है तो इसे पांच महीने बाद क्यों उठाया गया? कहीं यह अमेरिका के इशारे पर तो नहीं हो रहा है? दो अमेरिकी अधिकारियों ने भी इसे स्वीकार किया है. आख़िर जब यह गुप्त ज्ञापन था तो इसे गुप्त ही रहने देना चाहिए. एक व्यवसायी की बात का उतना असर नहीं होता, जितना दोनों अमेरिकी अधिकारियों का हुआ है. उन्होंने तो साबित कर दिया कि ज्ञापन सौंपा गया था. इससे तो यही साबित होता है कि सब अमेरिका की शह पर किया जा रहा है. कहीं पाकिस्तान में घटती साख से अमेरिका घबरा तो नहीं गया है. वह चाहता है कि इस विवाद से सेना और सरकार में कटुता बढ़ जाए. इस कटुता के कारण कहीं सेना और आईएसआई ने सरकार के ख़िलाफ़ कोई क़दम उठाया तो उसे ज़रदारी के समर्थन से पाकिस्तान में हस्तक्षेप करने का मौक़ा मिल जाएगा. इसी कारण वहां से आधिकारिक तौर पर तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन उसके दो अधिकारियों, जिसमें एक अब अधिकारी हैं भी नहीं, ने इस बात को स्वीकार कर लिया है. अगर ऐसा नहीं है तो अमेरिका को साफ़ तौर पर इंकार कर देना चाहिए था कि ऐसा कोई ज्ञापन पाकिस्तानी सरकार या ज़रदारी की ओर से आया है. हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अमेरिका की नीयत सही नहीं दिखाई दे रही है. अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस विवाद का हल कैसे निकालता है.

feedback@chauthiduniya.com

मिस्र की दूसरी क्रांति

हम लोगों ने इसलिए संघर्ष नहीं किया था कि एक तानाशाह को सत्ता से हटाकर दूसरे तानाशाह के लिए ज़मीन तैयार करें. हमें लोकतंत्र चाहिए, सैनिक हस्तक्षेप से चलने वाला शासन नहीं. ऐसी ही आवाज़ें उठ रही हैं मिस्र की राजधानी क़ाहिरा के उस तहरीर चौक से, जहां हज़ारों लोग एक बार फिर से सेना के सत्ता पर क़ाबिज़ होने की मंशा को चकनाचूर करने के लिए एकत्रित हुए हैं. उन्हें लग रहा है कि सेना नहीं चाहती कि मिस्र की जनता को लोकतांत्रिक सरकार मिले. जो सरकार हो, वह देखने सुनने में तो पूरी तरह लोकतांत्रिक दिखाई पड़े, लेकिन शासन पर अधिकार सेना का हो. लेकिन मिस्र की जनता ने सेना की इस चाल को समझ लिया और निकल पड़ी फिर से क्रांति की राह पर. लोगों से तहरीर चौक पर जमा होने की अपील की गई. राजधानी क़ाहिरा के इस चौक पर जन सैलाब उमड़ पड़ा. सेना और सरकार के विरुद्ध आवाज़ें उठने लगीं. सेना द्वारा की जा रही कार्रवाई के विरुद्ध वहां जमा लोग भी पत्थर और पेट्रोल बम का इस्तेमाल कर रहे हैं. भीड़ को हटाने के लिए सेना द्वारा की गई कार्रवाई में 50 लोगों की मौत हो गई तथा हज़ारों लोग घायल हो गए, लेकिन इससे उनकी हिम्मत नहीं टूटी है. मिस्र के सबसे संगठित राजनीतिक गुट मुस्लिम ब्रदरहुड ने भी तहरीर चौक पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है. हालांकि इसके विभिन्न संगठनों ने अपने मंच अलग-अलग लगाए हैं, लेकिन उनकी मांग एक ही है. उनका कहना है कि सेना को स्थाई राजनीतिक अधिकार देने का प्रस्ताव ख़ारिज किया जाए तथा जल्द ही राष्ट्रपति का चुनाव भी करवाया जाए. ग़ौरतलब है कि संसदीय चुनाव में मुस्लिम ब्रदरहुड को अच्छा समर्थन मिलने की उम्मीद है और वह सत्ता पर क़ाबिज़ होने के अपने सपने को टूटने नहीं देगा. होस्नी मुबारक के विरुद्ध हुए आंदोलन का परिणाम देख चुकी मिस्र की सेना के पास अब कोई विकल्प नहीं था. उसने पहले इस आंदोलन को कुचलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब उसे इस बात का अहसास हो गया कि आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता तो उनकी मांगें स्वीकार करने लगी. सबसे पहले तो सेना की ओर से नियुक्त कैबिनेट ने प्रधानमंत्री एसाम शराफ़ की अगुवाई में इस्तीफ़ा दे दिया. लेकिन सेना की सुप्रीम काउंसिल शुरू में इस इस्तीफ़े को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी. मगर जब आंदोलन की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी तो सैन्य परिषद को उनका इस्तीफ़ा मंज़ूर करना पड़ा. इसके बाद सैन्य परिषद ने राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया तीव्र करने की आंदोलनकारियों की मांग को भी स्वीकार कर लिया. लेकिन मिस्र की जनता अभी भी तहरीर चौक पर जमी हुई है. उसकी मांग है कि सैन्य परिषद के प्रमुख फील्ड मार्शल मोहम्मद हुसैन तंतावी इस्तीफ़ा दें तथा सैन्य परिषद का शासन जल्द से जल्द समाप्त हो. हालांकि सैन्य परिषद के प्रमुख ने इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलाई है, जिसमें सेना के प्रतिनिधियों के अलावा राजनीतिक दल के नेता शामिल हुए. तंतावी ने कहा है कि सेना केवल राष्ट्र की सुरक्षा चाहती है न कि शासन करने की उसकी मंशा है. उन्होंने जुलाई तक राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने की बात कही है. उन्होंने यह भी कहा है कि संसद का चुनाव पूर्व निर्धारित समय पर कराया जाएगा. बहरहाल, यह उम्मीद की जा रही है कि मिस्र की जनता की जीत होगी.

ग़ौरतलब है कि बीती फरवरी में हुई क्रांति के बाद तीस सालों से शासन पर क़ाबिज़ होस्नी मुबारक को सत्ता छोड़नी पड़ी थी. होस्नी मुबारक के बाद मिस्र के शासन की बागडोर सेना के हाथ में सौंप दी गई थी. उस समय आंदोलन करने वाले युवा इससे ख़ुश थे, लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने उस समय भी इसे सही नहीं बताया था. उनका कहना था कि सेना के हाथ में सत्ता देना लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक हो सकता है. उनका अनुमान सही निकला. अंतरिम सरकार संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाई, जिसके मुताबिक़ सेना को संवैधानिक वैधता का रक्षक घोषित करना था. साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि सेना के बजट को सावर्जनिक नहीं किया जाएगा. इसके अलावा राष्ट्रपति पद के चुनाव को 2012 के अंत या 2013 तक के लिए टाल दिया गया. संविधान संशोधन के इस प्रस्ताव से जनता भड़क गई. उन्हें लगने लगा कि सेना किसी तरह सत्ता अपने पास रखना चाहता है. मिस्र के युवा जल्द से जल्द लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं. उन्होंने अपने को ठगा महसूस किया. सेना को क्रांति विरोधी क़रार दिया तथा क़ाहिरा और अलक्जेंड्रिया जैसे शहरों में इकट्ठे होने लगे. पहले सेना ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ने लगी तो उनकी बात मान ली. मिस्र की जनता सोई नहीं है, जागी हुई है. जागृत लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता. मिस्र की सेना को इसका पता लग गया है तथा मिस्र की दूसरी क्रांति लगभग सफल हो गई है.

राजीव कुमार
feedback@chauthiduniya.com

वहां उपस्थित सब लोग इस विवाद का आनंद ले रहे थे. बाबा का स्नेह तो दोनों पर था, इसलिए उन्होंने कुशलतापूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया.

दिल्ली, 05 दिसंबर–11 दिसंबर 2011
चौथी दुनिया

बाबा और सेवा का मूल्य

एक अन्य अवसर पर मौसीबाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर दर्शकगण व्यग्र होकर मौसीबाई से कहने लगे कि मां कृपा कर धीरे-धीरे ही पेट दबाओ. इस प्रकार मसलने से तो बाबा की अंतड़ियां और नाड़ियां ही टूट जाएंगी. वे इतना कह भी न पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और अंगारे के समान लाल आंखें कर क्रोधित हो गए.

दामोदर घनश्याम बाबारे, उपनाम अण्णा चिंचणीकर बाबा के भक्त थे. वह सरल, सुदृढ़ और निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे. वह निडरतापूर्वक स्पष्ट भाषण करते और व्यवहार में सदैव नग़द नारायण–से थे. यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से वह रूखे और असहिष्णु प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से कपटहीन और व्यवहार–कुशल थे. इसी कारण उन्हें बाबा विशेष प्रेम करते थे. सभी भक्त अपनी–अपनी इच्छानुसार बाबा के अंग–अंग को दबा रहे थे. बाबा का हाथ कठड़े पर रखा हुआ था. दूसरी ओर एक वृद्ध विधवा उनकी सेवा कर रही थी, जिनका नाम वेणुबाई कौजलगी था. बाबा उन्हें मां शब्द से संबोधित करते तथा अन्य लोग उन्हें मौसीबाई कहते थे. वह एक शुद्ध हृदय की महिला थी. वह उस समय दोनों हाथों की अंगुलियां मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थी. जब वह बलपूर्वक उनका पेट दबाती तो पेट और पीठ का प्रायः एकीकरण हो जाता था. बाबा भी इस दबाव के कारण यहां–वहां सरक रहे थे. अण्णा दूसरी सेवा में व्यस्त थे. मौसीबाई का सिर हाथों की परिचालन क्रिया के साथ नीचे–ऊपर हो रहा था. जब इस प्रकार दोनों सेवा में जुटे थे तो अनायास ही मौसीबाई विनोदी प्रकृति की होने के कारण ताना देकर बोली कि यह अण्णा बहुत बुरा व्यक्ति है और यह मेरा चुंबन करना चाहता है. इसके केश तो पक गए हैं, परंतु मेरा चुंबन करने में इसे तनिक भी लज्जा नहीं आती है. यह सुनकर अण्णा क्रोधित होकर बोले, तुम कहती हो कि मैं एक वृद्ध और बुरा व्यक्ति हूं. क्या मैं मूर्ख हूं. तुम ख़ुद ही छेड़खानी करके मुझसे झगड़ा कर रही हो. वहां उपस्थित सब लोग इस विवाद का आनंद ले रहे थे. बाबा का स्नेह तो दोनों पर था, इसलिए उन्होंने कुशलतापूर्वक विवाद का निपटारा कर दिया. वह प्रेमपूर्वक बोले, अरे अण्णा, व्यर्थ ही क्यों झगड़ रहे हो. मेरी समझ में नहीं आता कि मां का चुंबन करने में दोष या हानि ही क्या है. बाबा के शब्दों को सुनकर दोनों शांत हो गए और सब उपस्थित लोग जी भरकर ठहाका मारकर बाबा के विनोद का आनंद लेने लगे.

इसी प्रकार बाबा की भक्त–परायणता और शिक्षा का नमूना एक और कथा में मिलता है. बाबा भक्तों को उनकी इच्छानुसार ही सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें सहन न था. एक अन्य अवसर पर मौसीबाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर दर्शकगण व्यग्र होकर मौसीबाई से कहने लगे कि मां कृपा कर धीरे–धीरे ही पेट दबाओ. इस प्रकार मसलने से तो बाबा की अंतड़ियां और नाड़ियां ही टूट जाएंगी. वे इतना कह भी न पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और अंगारे के समान लाल आंखें कर क्रोधित हो गए. साहस किसे था, जो उन्हें रोके. उन्होंने दोनों हाथों से सटके का एक छोर पकड़ नाभि में लगाया और दूसरा छोर ज़मीन पर रख उसे पेट से धक्का देने लगे. सटका (सोटा) लगभग 2 या 3 फुट लंबा था. अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह पेट में छिद्र कर प्रवेश कर जाएगा. लोग शोकित एवं भयभीत हो उठे कि अब पेट फटने ही वाला है. बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो, उसके अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रतिक्षण पेट फटने की आशंका हो रही थी. सभी किंकर्तव्यविमूढ़ हो रहे थे. वे आश्चर्यचकित और भयभीत हो ऐसे खड़े थे, मानो गूंगों का समुदाय हो. यथार्थ में भक्तगण का संकेत मौसीबाई को केवल इतना ही था कि वे सहज रीति से सेवा करें. किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुंचाने की न थी. भक्तों ने तो यह कार्य केवल सद्भावना से प्रेरित होकर ही किया था, परंतु बाबा तो अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप कणमात्र भी न होने देना चाहते थे. भक्तों को तो आश्चर्य हो रहा था कि शुभ भावना से प्रेरित कार्य दुर्गति से परिणत हो गया और वे केवल दर्शक बने रहने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे. भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और सटका छोड़कर वह पुनः आसन पर विराजमान हो गए. इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि अब दूसरों के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप न करेंगे और सबको उनकी इच्छानुसार ही बाबा की सेवा करने देंगे. केवल बाबा ही सेवा का मूल्य आंकने में समर्थ थे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्री सद्गुरु साईं बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

श्री साईनाथ स्तवन मंजरी

जो अज्ञानी जग केवासी. जन्म–मरण कारा–ग्रहवासी.
जन्म–मरण के आप पार है. विभु निरंजन जगदाधार है.

निर्झर से जल जैसा आये. पूर्वकाल से रहा समाये.
स्वयं उमंगित होकर आये. जिसने ख़ुद है स्त्रोत बहायें.

शिला छिद्र से ज्यों बह निकला. निर्झर उसको नाम मिल गया.
झर–झर कर निर्झर बन छाया. मिथ्या स्वत्व छिद्र से पाया.

कभी भरा और कभी सूखता. जल निस्संग इसे नकारता.
छिद्र शून्य को सलिल न माने. छिद्र किन्तु अभिमान बखान.

भ्रमवश छिद्र समझता जीवन. जल न हो तो कहां है जीवन.
दया पात्र है छिद्र विचार. दम्भ व्यर्थ उसने यों धारा.

यह नरदेह छिद्र सम भाई. चेतन सलिल शुद्ध स्थायी.
छिद्र असंख्य हुआ करते हैं. जलकण वही रहा करते हैं.

अतः नाथ हे परम दयाघन. अज्ञान नग का करने वेधन.
वज्र अस्त्र करते कर धारण. लीला सब भक्तों के कारण.

जड़तः छिद्र कितने है सारे. भरे जगत में जैसे तारे.
गत हुये वर्तमान अभी हैं. युग भविष्य के बीज अभी हैं.

भिन्न–भिन्न ये छिद्र सभी है. भिन्न–भिन्न सब नाम गति है.
पृथक–पृथक इनकी पहचान. जग में कोई नहीं अनजान.

चेतन छिद्रों से ऊपर है. मैं तू अन्तर नहीं उचित है.
जहां द्वैत का लेश नहीं है. सत्य चेतना व्याप रही है.

चेतना का व्यापक विस्तार. हुआ असरो पूरित संसार.
तेरा मेरा भेद अविचार. परम त्याज्य है बाह्य विकार.

मेघ गर्भ में निहित सलिल जो. जड़तः निर्मल नहीं भिन्न सो.
धरती तल पर जब वह आता. भेद–विभेद तभी उपजाता.

जो गोद में गिर जाता है. वह गोदावरी बन जाता है.
जो नाले में गिर जाता है. वह अपवित्र कहला जाता है.

सन्त रूप गोदावरी निर्मल. तुम उसके पाव अविरल जल.
हम नाले के सलिल मलिनतम. भेद यही दोनों में केवल.

करने जीवन स्वयं कृतार्थ. शरण तुम्हारी आये नाथ.
कर जोरे हम शीश झुकाते. पावन प्रभु पर बलि–बलि जाते.

पात्र–मात्र से है पावनता. गोदा–जल की अति निर्मलता.
सलिल सर्वत्र तो एक समान. कहीं न दिखता भिन्न प्रणाम.

गोदावरी का जो जलपात्र. कैसे पावन हुआ वह पात्र.
उसके पीछे मर्म एक है. गुणः दोष आधार नेक है.

मेघ–गर्भ से जो जल आता. बदल नहीं वह भू–कण पाता.
वही कहलाता है भू–भाग. गोदावरी जल पुण्य–सुभाग.

वन्य भूमि पर गिरा मेघ जो. यद्यपि गुण में रहे एक जो.
निन्दित बना वही कटुखारा. गया भाग्य से वह धिक्कारा.

सदगुरू प्रिय पावन हैं कितने. षडिरपुओं के जीता जिनने.
अति पुनीत है गुरु की छाया. शिरडी सन्त नाम शुभ पाया.

अतः सन्त गोदावरी ज्यों है. अति प्रिय हित भक्तों के त्यों हैं.
प्राणी मात्र के प्राणाधार. मानव धर्म अवयं साकार.

जग निर्माण हुआ है जब से. पुण्यधार सुरसरिता तब से.
सतत प्रवाहित अविरल जल से. रुद्धित किंचित हुआ न तल है.

सिया लखन संग राम पधारे. गोदावरी के पुण्य किनारे.
युग अतीत वह बीत गया है. सलिल वही क्या शेष रहा है.

जल का पात्र वहीं का वह है. जलधि समाया पूर्व सलिल है.
पावनता तब से है वैसी. पात्र पुरातन युग के जैसी.

पूरव सलिल जाता है ज्यों ही. नूतन जल आता है त्यों ही.
इसी भांति अवतार रीति है. युग–युग में होती प्रतीत है.

बहु शताब्दियां संवत सर यों. उन शतकों में सन्त प्रवर ज्यों.
हो सलिल सरिस सन्त साकार. ऊर्मिविभूतियां अपरंपार.

सुरसरिता ज्यों सन्त सु–धारा. आदि महायुग ले अवतार.
सनक सनन्द न सनत कुमार. सन्त वृन्द ज्यों बाढ़ अपारा.

नारद तुम्बर पुनः पधारे. ध्रुव प्रहलाद बली तन धारे.
शबरी अंगद नल हनुमान. गोप गोपिका बिदुर महाना.

सन्त सुसरिता बढ़ती जाती. शत–शत धारा जलधि समाती.
बाढ़ें बहु यों युग–युग आती वर्णन नहीं वाणी कर पाती.

सन्त रूप गोदावरी तट पर. कलियुग के नव मध्य प्रहर पर.
भक्ति –बाढ़ लेकर तुम आये. 'सांईनाथ सुनाम तुम कहाये.

चरण कमल द्वय दिव्य ललाम. प्रभु स्वीकारों विनत प्रणाम.
अवगुण प्रभु हैं अनगिन मेरे. चित न धरों प्रभु दोष घनेरे.

क्रमशः

चस्का अच्छा नहीं, असल में चरित्र हनन, रिश्वतख़ोरी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाता हास्य से भरपूर नाटक है. इस नाटक में सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को बहुत ही सरल तरीक़े से दर्शाने की कोशिश की गई है.

अनंत विजय

औरत की बोली

पिछले कई सालों से हिंदी में साहित्येतर विधाओं की किताबों के प्रकाशन में काफ़ी तेज़ी आई है. प्रकाशकों के अलावा लेखकों ने भी इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया है. कई लेखकों ने कहानी, कविता, उपन्यास से इतर समाज के उन विषयों को छुआ है, परखा है, जो अब तक हिंदी समाज की नज़रों से ओझल थे. पिछले कुछ वर्षों में लेखकों की जो नई पीढ़ी आई है, उसने उन विषयों पर ध्यान दिया और जीवनानुभव और भोगे गए यथार्थ के नाम पर काल्पनिक कथाओं से ख़ुद को मुक्त करते हुए बिंदास अंदाज़ में अपनी लेखनी से हिंदी की जड़ होती ज़मीन तोड़ी. हिंदी में शोध के आधार पर साहित्येतर लेखन भी कम ही हुआ है और जो भी हुआ है, उसमें डिटेलिंग की ज़रूरत ही महसूस नहीं की गई. हिंदी साहित्य में किसी विषय विशेष पर पूरी डिटेलिंग के साथ लेखन मेरी नज़र से नहीं गुज़रा है. लेकिन जो नई पीढ़ी आई है, उसने इस दिशा में कई काम किए हैं. नई पीढ़ी की उन्हीं चुनिंदा लेखकों में एक अहम नाम है गीताश्री का. कुछ दिन पहले एक के बाद एक बेहतरीन कहानियां लिखकर शोहरत हासिल कर चुकी पत्रकार गीताश्री ने अपने अनुभवों और शोध के आधार पर मानव सभ्यता के सबसे पुराने कारोबारों में से एक– वेश्यावृत्ति पर एक गंभीर किताब लिखी है, नाम है औरत की बोली. गीताश्री ने इस किताब में स्वयं देखी–सुनी एक ऐसी दास्तान पेश की है, जिसे पढ़कर पाठकों के हृदय के तार झंकृत हो उठते हैं. दुनियाभर के देशों में स्त्री देह के कारोबार को लेकर जो रिपोर्ताज इस किताब में संग्रहित हैं, उसमें तथ्यों और अनुभवों को बेहद ही कलात्मक और प्रभावोत्पादक ढंग से प्रस्तुत किया गया है. औरत की बोली में लिखे लेखों को सिर्फ़ रिपोर्ताज या तथ्यों का लेखा–जोखा मात्र नहीं कहा जा सकता है, बल्कि गीताश्री ने स्त्री देह के व्यापार को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक और ऐतिहासिक आधार पर परखने की कोशिश भी की है.

अपनी इस किताब की भूमिका में गीताश्री ने अपने बचपन के अनुभव का ज़िक्र किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह उनके गांव में शादी के दौरान महफ़िल में बाईजी का नाच होता था. उस बाईजी के नाच ने लेखिका के बाल मन पर गहरा प्रभाव डाला था, जिसका असर काफ़ी बाद तक उसके मन पर रहा. उस वक़्त बालमन में कई प्रश्न भी उठ खड़े हुए थे, जिनके जवाब बाद में पत्रकारिता के दौरान उनको मिले. बाल मन में उठ रहे सवालों को लेकर लेखिका जब कॉलेज की पढ़ाई के लिए बिहार के अपने शहर मुज़फ्फ़रपुर आती हैं तो वहां पहली बार कोठे और कोठेवालियों से सामना होता है. हिंदी के वरिष्ठ कवि जानकी वल्लभ शास्त्री मुज़फ्फ़रपुर के उसी बदनाम मोहल्ले चतुर्भुज स्थान की गली के आख़िर में बने एक मकान में रहा करते थे. साहित्य की विद्यार्थी थी, लिहाज़ा जानकी वल्लभ शास्त्री के घर आना जाना शुरू हुआ. साहित्य प्रेम की आड़ में गीताश्री ने मुज़फ्फ़रपुर की उस बदनाम गली चतुर्भुज स्थान के कई चक्कर लगाए. कोठे और कोठेवालियों के तिलिस्म को समझने की लगातार कोशिश में देश–विदेश के रेड लाइट एरिया में चक्कर लगाती रही. किताब की भूमिका में स्वीकार भी किया है कि बचपन में जगी उत्सुकता धीरे–धीरे उनके प्रति सद्भाव में बदलती चली गई. फिर दुनिया देखने का मौक़ा मिला. देश के कुछ चुनिंदा ठिकाने देखने के बाद दुनिया की खिड़की से झांकने का मन था. यह मौक़ा भी ख़ूब मिला. कई विकसित और

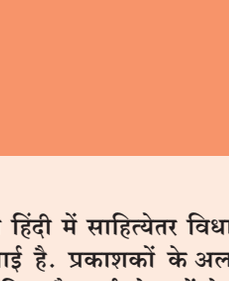

समीक्ष्य कृति- औरत की बोली
लेखिका- गीताश्री
प्रकाशक- सामयिक प्रकाशन, दिल्ली
मूल्य- 250 रुपये

विकासशील देशों की ऐसी लड़कियों की दुनिया को क़रीब से महसूस करने का मौक़ा मिला. लगभग कई रातें गुज़ारी, उन गलियों की तलाश में, अपने लोकल गाइड और दोस्तों की सहायता भी ली. इस तरह बिहार के गांव की महफ़िल से जो उत्सुकता पैदा हुई, वह गीताश्री को जर्मनी, चीन, हंगरी, ईरान से लेकर खाड़ी देशों में वेश्याओं की स्थिति को जानने के लिए खींच ले गई. साथ ही वह अपने देश के मशहूर वेश्यावृत्ति के अड्डों तक भी पहुंचती हैं.

गीताश्री के मुताबिक़, चीन में किसी क्षेत्र का सकल सालाना कारोबार एक अरब का आंकड़ा पार करता है तो उसे उद्योग का दर्जा प्राप्त हो जाता है, लेकिन सेक्स सेवा को अब तक वहां उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया है. हेयर सैलून और मसाज पार्लर की आड़ में हो रहे देह व्यापार के धंधे की समस्याओं की तरफ़ से चीन की सरकार आंख मूंदकर बैठी है.

इस किताब की जो केंद्रीय थीम है, वह यह है कि सारी दुनिया में वेश्यावृत्ति के पीछे के कारण कमोबेश एक ही हैं. गीताश्री जब इसको परखती हैं तो वह उन देशों के उदाहरण और तथ्यों को भी पेश करती चलती हैं, जिस वजह से किताब की उपयोगिता और विश्वसनीयता दोनों बढ़ जाती है. चीन के बारे में लेखिका ने कई चौंकाने वाले तथ्यों का ख़ुलासा किया है. गीताश्री ने बताया है कि चीन में सेक्स सेवाओं का सालाना कारोबार तक़रीबन 3.6 अरब डॉलर को पार कर गया है. गीताश्री के मुताबिक़, चीन में किसी क्षेत्र का सकल सालाना कारोबार एक अरब का आंकड़ा पार करता है तो उसे उद्योग का दर्जा प्राप्त हो जाता है, लेकिन सेक्स सेवा को अब तक वहां उद्योग का दर्जा नहीं मिल पाया है. हेयर सैलून और मसाज पार्लर की आड़ में हो रहे देह व्यापार के धंधे की समस्याओं की तरफ़ से चीन की सरकार आंख मूंदकर बैठी है. लेकिन हेयर सैलून का विस्तृत अध्ययन करने वाले गे जेजू के हवाले से लिखा गया है कि बहुत देर तक इस समस्या को नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन है. चीन पर लिखे लेख में गीताश्री ने वहां चल रहे देह व्यापार को भी डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत के आधार पर परखा है. चीन के अलावा गीताश्री पाठकों को एम्सटर्डम भी ले जाती हैं. चीन के बिल्कुल उलट, वहां वेश्यावृत्ति को क़ानूनी मान्यता प्राप्त है. वहां किस तरह से स्त्रियां अपनी देह की नुमाइश करती हैं, और किस तरह से पूरा कारोबार फैला हुआ है, उसका भी आंखों देखा वर्णन लेखिका ने किया है. एक पत्रकार की आंख में जब साहित्यकार की संवेदना शामिल हो जाती है, तो जो भाषा पैदा होती है उसकी चमक को भी गीताश्री की इस किताब में महसूस किया जा सकता है.

धर्म के नाम पर जिस तरह से सदियों से स्त्रियों के शरीर का उपभोग पुरुष करता है, उसकी पड़ताल भी गीताश्री ने इस किताब में की है. चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें स्त्रियों को दोयम दर्जे का ही अधिकार प्राप्त है. हम चाहे जितना भी नारा लगा लें कि स्त्रियां पूजनीय हैं, लेकिन अंततः वे उपभोग की ही वस्तु रही हैं. स्त्री देह के शोषण और उसके उपयोग को लेकर धर्मों में कमोबेश मतांतर नहीं है. कुल मिलाकर अगर हम देखें तो गीताश्री की यह किताब औरत की बोली वेश्यावृति के इस कारोबार का समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है. इस किताब के कई चैप्टर छोटे हैं, लेकिन उसमें बड़े सवाल उठाकर गीताश्री उससे टकराने की चुनौती भी समाज को देती हैं. गीताश्री अपनी यात्राओं के मध्य समय–समय पर मिलने वाले लोगों के अनुभव से अपने लेखों को समृद्ध करती चलती हैं. गीताश्री की इस किताब की छोटी सी भूमिका राजेंद्र यादव ने लिखी है, आशीर्वाद की शक्ल में.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

भ्रष्टाचार का चस्का और आम आदमी

राजेश एस. कुमार

सही मायनों में अपनी आवाज़ को सीधे संवाद के ज़रिये जन–जन तक पहुंचाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम आज भी नाटक को ही माना जाता है. नाटक मंचन और इसी की एक विधा नुक्कड़ नाटकों के ज़रिये न सिर्फ़ दर्शकों से सीधा संवाद होता है, बल्कि उसी वक़्त नाटक की विषयवस्तु से संबंधित सारी जानकारी भी मिल जाती है. क़रीब दो साल पहले राजेश दुआ का हास्य नाटक दूल्हा बिकता है, देखा था. नाटक में हास्य के साथ–साथ समाज में फैली दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों पर कटाक्ष किया गया था. लगभग दो साल के बाद उनके द्वारा निर्देशित नाटक चस्का अच्छा नहीं, देखने का मौक़ा मिला. यह नाटक भी निर्देशक की छवि के अनुरूप व्यंग्य का पुट लिए सामाजिक सरोकारों की बात कह रहा था. लेकिन इस बार निर्देशक के तेवर और कड़े दिखाई दिए. इस नाटक की थीम सरकारी तंत्र में फैला भ्रष्टाचार थी. यह थीम ख़ुद में कहीं न कहीं अन्ना आंदोलन का कलेवर भी ओढ़े हुई थी. नाटक में चपरासी का किरदार मैं अन्ना हूं, लिखी की गांधीनुमा टोपी पहने दिखाई देता है. हाल में दिल्ली के पीएसके (पूर्व सांस्कृतिक भवन) सभागार में नाट्य कला मंच के तत्वावधान में राजेश दुआ द्वारा निर्देशित एवं लिखित इस हास्य–व्यंग्य नाटक का मंचन किया गया. नाटक में विजय शर्मा, रंजन कुमार, संजय कुमार, जेसी मल्होत्रा, हरीश चौहान, फ़ातिमा, गीतरेखा, रमेश कथूरिया, रजत भटनागर, ओपी शर्मा और अतिथि कलाकार अदीप सेतिया, देवेंद्र अकोत्रा जैसे वरिष्ठ कलाकारों ने भाग लिया. तकनीकी पहलुओं की बात करें तो प्रकाश की व्यवस्था एवं परिकल्पना

बहुत उत्कृष्ट थी. प्रकाश व्यवस्था अजय की थी और परिकल्पना राजेश दुआ की.

चस्का अच्छा नहीं, असल में चरित्र हनन, रिश्वतख़ोरी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाता हास्य से भरपूर नाटक है. इस नाटक में सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को बहुत ही सरल तरीक़े से दर्शाने की कोशिश की गई है. एक अफ़सर किस तरह से हर काम के लिए रिश्वत वसूलने की कोशिश करता है. अनोखे लाल एक भ्रष्ट सरकारी बाबू है, जो अपने ऑफिस की हर फाइल को उसमें रखी नोटों की गड्डी के वज़न के हिसाब से तौलता है, यानी जिस फाइल में जितने ज़्यादा नोट, उस फाइल की उतनी ही तेज़ गति. अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर प्रसिद्ध धारावाहिक (जिस पर चला मुसद्दी ऑफिस–ऑफिस नाम से फिल्म भी बन चुकी है) के किरदार मुसद्दीलाल की तरह आपको भी हर दूसरे हफ्ते आने के लिए कहा जाएगा. इस तरह से अनोखे लाल के साथ–साथ उसका पूरा स्टाफ उसी के नक्शे–क़दम पर चलता है. लेकिन एक दिन जब भ्रष्ट बाबुओं की इस प्रवृत्ति की शिकार जनता एकजुट होकर भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करती है, तब जाकर प्रशासन जागता है और फिर अचानक जांच एजेंसी का बाबू मामलों की जांच करता है. परत–दर–परत मामला खुलता है. तब अनोखे लाल उनकी पकड़ में आता है. जनता की हुंकार के बाद यह सरकारी बाबू किस तरह से भ्रष्टाचार से तौबा करते हैं, इसी को हास्य के पुट के साथ नाटक में दिखाया गया है. दरअसल, भ्रष्टाचार यानी रिश्वतख़ोरी हमारे देश में हर जगह, हर कार्यालय में व्याप्त है. लेखक ने एक काल्पनिक कहानी के ज़रिये भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जनता को जागरूक करने की कोशिश की है. हमारे नेताओं, बिल्डरों एवं नौकरशाह का गठजोड़ इतना गहरा हो चुका है कि जब तक जनता एकजुट होकर विरोध नहीं करेगी, तब तक हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकता है. नाटक के कलाकारों ने अपने सफल अभिनय द्वारा यही सब दिखाने की कोशिश की है. नाटक के अंत में जिस तरह से सभी कलाकर एक साथ मंच पर जनता से भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ने का आह्वान करते हैं, वह एक बार फिर से सोचने पर मजबूर करता है कि जब तक आम आदमी अपनी लड़ाई ख़ुद नहीं लड़ेगा, तब तक देश से भ्रष्टाचार का ख़ात्मा मुमकिन नहीं है. कुल मिलाकर राजेश दुआ एक ज्वलंत विषय उठाकर एक सफल संदेशात्मक नाटक रचते हैं.

rajeshy@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
अयोध्या विवाद
एक पत्रकार की डायरी

लेखक
अरविंद कुमार सिंह

प्रकाशक
शिल्पायन

मूल्य
350 रुपये

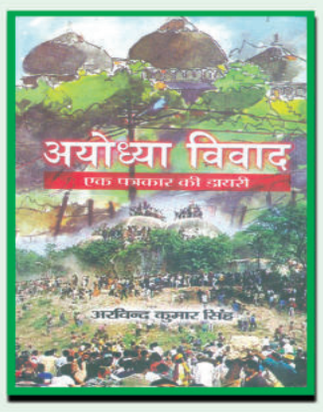

इस किताब में बाबरी मस्जिद ध्वंस के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया | एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

ब्राईट® की सभी के लिए उपयोगी पुस्तकें

★ हिन्दी संस्करण भी उपलब्ध है।

FROM THE HOUSE OF : BRIGHT® Career's® BOOKS | COMPETITION REFRESHER | SCIENCE REFRESHER | G.K. GENERAL KNOWLEDGE REFRESHER

BRIGHT PUBLICATIONS®
Publishers of INDIA'S LARGEST SELLING Competition & School Books
2767, Kucha Chellan, Darya Ganj, New Delhi-110 002 (India) —— (ESTD. 1968)
Ph.: 011-64632226 & 3226, 23282226 & 3226 Fax: 011-23269227 Telefax: 64633226
E-mail: sales@brightpublications.com | Web Site: http://www.brightpublications.com

FOR VPP ORDERS, SEND ₹ 25/- AS ADVANCE & FOR FREE CATALOGUE WRITE TO US

भारतीय बाज़ार में भी ग्रीनबेरी कंपनी ने ग्रीन टी के अलग-अलग वेरिएंटस को पेश किया है, जो अलग-अलग फ्लेवर में बाज़ार में मौजूद हैं.

दिल्ली, 05 दिसंबर-11 दिसंबर 2011

चौथी दुनिया

मज़ेदार हेल्दी ब्रेकफास्ट

सुबह का नाश्ता जितना हल्का और शुद्ध होगा, पूरे दिन तन और मन उतना ही फ्रेश रहेगा. हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए बैगरिज ने कुछ ख़ास कॉर्न फ्लेक्स, मुसली, ओटस को बाज़ार में अलग-अलग स्वाद के साथ पेश किया है. ये नए प्रोडक्ट बाज़ार में अलग-अलग फ्लेवर में उपलब्ध हैं. बैगरिज का नया ब्रान एडेड कॉर्न फ्लेक्स एक स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता है, जो उच्च फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर है. यह मुख्य रूप से उन व्यक्तियों के लिए फ़ायदेमंद है, जो उच्च फाइबर डाइट की तलाश में रहते हैं, ताकि वे अपने वज़न पर नियंत्रण रख सकें. कॉर्न फ्लेक्स नाश्ते के लिए स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है, लेकिन असल में कॉर्न फ्लेक्स बनाते वक़्त इसका प्राकृतिक चोकर नष्ट हो जाता है और वह उच्च स्टार्च, हाई गलिसीमिक इंडेक्स और कम फाइबर वाला रह जाता है. उच्च जीआई स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, जिससे वज़न बढ़ता है. कंपनी ने इस तथ्य का ख्याल रखते हुए अपना नया उत्पाद ब्रान एडेड कॉर्न फ्लेक्स तैयार किया है, जिसमें फाइबर नष्ट नहीं होता है, जिससे पोषण का संतुलन बना रहता है. इसके साथ ही कंपनी ने अलग-अलग फ्लेवर में हेल्दी फूड मुसली भी पेश किया है. यह मिक्सचर की तरह यूं ही दिन में किसी भी वक़्त भूख लगने पर फांका जा सकता है. इसके अलावा आइसक्रीम, पुडिंग, केक पर छिड़क कर या फ्रूट जूस या दूध में मिलाकर लिया जा सकता है. आमंड, चोको आमंड, बनाना, पाइन एप्पल, मिक्सड फ्रूट और स्ट्राबेरी के कुछ वेरिएंटस भी प्रस्तुत किए गए हैं. कंपनी ने एक स्वस्थ आहार वीट ब्रैन भी पेश किया है. इसे घर में रोटी बनाने वाले आटे में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा दही, दूध, शेक या किसी भी चीज़ में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है. वीट ब्रैन में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है. इससे वज़न भी नियंत्रण में रहता है.

स्पाई गैजेट से कार पर नज़र रखें

आजकल की व्यस्त लाइफ में इतना वक़्त कहां है कि आप अपनी कार और ड्राइवर पर लगातार नज़र बनाए रख सकें. ख़ासकर कंपनियों के लिए तैयार की गई फारआई निजी इस्तेमाल में भी लाई जा सकती है. दरअसल, जीपीआरएस पर काम करने वाली इस डिवाइस को कार में रखे जाने पर कार और ड्राइवर दोनों पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है. कंपनी की वेबसाइट पर एक यूजरनेम के साथ ही आपको कार के ट्रैवलिंग रूट की जानकारी मिल जाती है. इस सर्विस की कई विशेषताएं हैं. आवश्यकता के अनुसार अपने वाहन की गति, ठहराव, निष्क्रियता और दूरी का विवरण प्राप्त कर सकते हैं, मैप पर वाहन की स्थिति की ताज़ा जानकारी, पूरे इंडिया की कवरेज, कार पार्क करने पर एसएमएस के ज़रिये सूचना पा सकते हैं. इसमें जियो-फेंसिंग की फैसीलिटी भी है, यानी मैप पर अपने वाहन के लिए एक सीमा-क्षेत्र निर्धारित करने की सुविधा और निर्धारित सीमा के बाहर जाने पर या अंदर आने पर एसएमएस के ज़रिये सूचना. किसी भी हालत में वेबसाइट से ही एसएमस के माध्यम से अपने वाहन को रोकने की सुविधा. इसके अलावा ईंधन की सूचना, घटनाओं का विवरण ई-मेल द्वारा अधिक गति होने पर एसएमएस अलर्ट, एक से ज़्यादा वाहन की ट्रैकिंग सुविधा, 365 दिनों की यात्रा संबंधी सूचना का संग्रह और दैनिक यात्रा का विवरण भी मिल सकता है. इसके अलावा वाहन के भीतर के वार्तालाप सुनने के लिए गुप्त माइक्रो फोन, चोरी की आशंका को कम करने में सहायक, ईंधन चोरी पर सतर्क सूचना और वाहन के अंदर की स्थिति को कैमरे से देखने की सुविधा है. इसकी क़ीमत मध्यम वर्गीय लोगों की जेब के हिसाब से रखी गई है. इस स्पाई डिवाइस की क़ीमत शुरुआत होती है सात हज़ार रुपये से.

सीगेट डेस्कटॉप ड्राइव

सीगेट हार्ड डिस्क ड्राइव और स्टोरेज समाधान बनाने वाली दुनिया की अग्रणी कंपनी है. सीगेट ने नया डेस्कटॉप ड्राइव बनाया है जो प्रदर्शन और क्षमता के लिहाज़ से दुनिया भर में व्यवसायिक व निजी स्तर पर कंटेंट के लगातार बढ़ते निर्माण व उपयोग के मद्देनज़र कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरे. नई बाराकुडा फैमिली ग्राहकों के लिए उनकी ज़रूरत के उत्पाद की खोज एकदम आसान बनाती है और सीगेट के मूल उपकरण निर्माताओं व वितरक चैनलों के लिए ख़र्च कम कर देती है. यह उन्हें भारी मात्रा में डिजिटल कंटेंट मैनेज और स्टोर करने में मदद करते हैं. इसके अलावा ओईएम और चैनल ग्राहक चाहते हैं कि कम प्रॉडक्ट लाइन क्वालीफाई करने और इनवेंटरी प्रबंधन का उनका ख़र्च भी कम हो जाए. डेस्कटॉप पीसी का प्रदर्शन काफ़ी अहमियत रखता है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इस्तेमाल करते हैं. उससे भी ज़्यादा मल्टी मीडिया टेक्स्ट, ऑडियो, तस्वीरें, एनीमेशन, वीडियो और अन्य कंटेंट-कारोबार, विज्ञापन, कला, एजुकेशन, मनोरंजन, इंजीनियर दवा, गणित व विज्ञान आदि से जुड़े, इस्तेमाल करते हैं. हार्ड ड्राइव का बेहतर प्रदर्शन का मतलब है तेज़ी से चलने वाला कंप्यूटर, ताकि इससे कंटेंट तक आसानी से पहुंच बन सके. नई बाराकुडा हार्ड ड्राइव नवंबर से नियमित सीगेट चैनल के ज़रिये आ गई है. यह डेस्कटॉप, टॉवर या ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, वर्क घर या छोटे कारोबारी सर्वर, नेटवर्क से जुड़े स्टोरेज उपकरणों, सीधे जुड़े स्टोरेज विस्तार, घर या छोटे कारोबार के लिए आरएआईडी समाधान के लिए डिज़ाइन की गई है. फैमिली की क्षमता 250 जीबी से लेकर 3 टीबी तक के रेंज में है. सीगेट ने एक टीबी-पर-डिस्क बाराकुडा हार्ड ड्राइव की वॉल्यूम शिपमेंट शुरू कर बाराकुडा फैमिली को सुलभ बनाया है. इसकी तकनीकी विशिष्टता भी कम नहीं है. नई बाराकुडा हार्ड ड्राइव एसएटीए 6 जीबी/सेकंड इंटरफेस,7200 आरपीएम स्पिन स्पीड और 64 एमबी कैचे से लैस है, जिसके चलते यह हर कैपीसिटी में बेहतरीन प्रदर्शन देती है. सीगेट की स्मार्ट लाइन तकनीक, सीगेट बाराकुडा ग्रीन ड्राइव की एक ख़ूबी, फ्लैगशिप बाराकुडा ड्राइव के साथ भेजी जाती रहेगी. नया 4 के स्टैंडर्ड ग़लतियां सुधारने की बेहतर प्रणाली बनाता है. सीगेट उच्च गुणवत्ता वाली, पर्यावरण के मानकों पर खरा उतरने वाली हार्ड ड्राइव बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. स्टोरेज उत्पाद में इस्तेमाल 70 प्रतिशत से ज़्यादा मैटेरियल रीसाइकिल करने लायक़ होता है. इसके सारे उत्पाद हैलोजन से मुक्त होते हैं और कठिन आरईएसीएच मानक पर खरे उतरते हैं. सीगेट ड्राइव में हानिकारक हैलोजन तत्व क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं होते. हैलोजन की ग़ैर मौजूदगी कई कंप्यूटर निर्माताओं और पर्यावरण समूहों के कड़े क़ानूनी नियमों के मानदंड पर खरा उतरती है.

घरेलू इस्तेमाल की आटा चक्की

वुड और फाइबर कवरिंग के साथ यह चक्की काफ़ी मज़बूत और स्टाइलिश है. चक्की में पीसे जाने वाले दानों की पौष्टिकता बरक़रार रहे, इसका भी ख़ास ध्यान रखा गया है.

आजकल मिलावटी चीज़ों से बाज़ार भरा पड़ा है. आटे में मिलावट रहती है. रोटी में किरकिरी खाने का स्वाद बिगाड़ देती है और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है वह अलग. कितना अच्छा हो यदि गेहूं धोकर, साफ़ करके ख़ुद ही घर में इसकी पिसाई भी कर सकें. दरअसल, मीलसेंट कंपनी ने ऐसी ही घरेलू इस्तेमाल में आने वाली आटा चक्की को बाज़ार में पेश किया है. देखने में बेहद ख़ूबसूरत यह आटा चक्की पौष्टिक भोजन की ओर ले जाने वाला एक ज़रिया है. इस घरेलू आटा चक्की में अनाज पीसने के लिए पत्थर की जगह मेटल ब्लेड और ग्राइंडर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यह ज़्यादा टिकाऊ है. इस चक्की में अलग-अलग तरह के दानों के लिए अलग-अलग ब्लेड दिए गए हैं, जिन्हें आसानी से फिट किया जा सकता है. कई तरह के ब्लेड होने की वजह से इसमें अपने हिसाब से अनाज के दानों को मोटा या महीन पीसा जा सकता है. वुड और फाइबर कवरिंग के साथ यह चक्की काफ़ी मज़बूत और स्टाइलिश है. चक्की में पीसे जाने वाले दानों की पौष्टिकता बरक़रार रहे, इसका भी ख़ास ध्यान रखा गया है. इस चक्की में पीसते वक़्त अनाज के दानों से फाइबर नहीं निकलता है और गेहूं, मक्का या किसी भी चीज़ के आटे में पूरी तरह से पौष्टिकता बरक़रार रहती है. इसे साफ़ करने में भी कोई झंझट नहीं है. यह मशीन ऑटोक्लीन हो जाती है, एक बार पूरी तरह से आटा पिस जाने के बाद इसे फुल स्पीड चला दें तो क्लीन हो जाने पर इसमें ऑटोमेटिक बीप होता है. बाक़ी किनारों में फंसा आटा ब्रश की मदद से बाहर आ जाता है. कंपनी ने इस चक्की के कई मॉडल बाज़ार में उतारे हैं. इनमें से ख़ास है टॉकी चक्की, जिसमें चलती चक्की में यदि मशीन का दरवाज़ा खुल जाए तो मशीन ऑटोमैटिक बंद हो जाती है और वॉइस मैसेज अलर्ट सुनाई देता है. यदि इस चक्की में पांच किलो आटा प्रतिदिन पीसा जाए तब भी चक्की बिना किसी समस्या के तीस साल तक कारगर रहेगी. इसकी क़ीमत सात हजार रुपये से शुरू होती है.

स्वास्थ्यवर्धक चाय का मज़ा लें

स्वाद में टेस्टी और स्वास्थ्यवर्धक ग्रीन टी के मिलियासिनेनसिस के ताज़े पत्तों से तैयार की जाती है. भारत, चीन, जापान और थाईलैंड में वर्षों से ग्रीन टी का सेवन किया जाता रहा है. परंपरागत चीन और भारतीय दवाओं में चिकित्सकों द्वारा ग्रीन टी को शक्ति बढ़ाने वाली दवा के रूप में देखा गया है. इसी को देखते हुए भारतीय बाज़ार में भी ग्रीनबेरी कंपनी ने ग्रीन टी के अलग-अलग वेरिएंटस को पेश किया है, जो अलग-अलग फ्लेवर में बाज़ार में मौजूद हैं. ये ग्रीन टी वेरिएंटस टी बैग, पैकेज्ड टी और आइस टी में भी उपलब्ध हैं. ग्रीन टी स्वादिष्ट होती है. इसमें थीयेनाइन-एक अमीनो एसिड होता है, जिससे दिमाग़ पर शांत प्रभाव पड़ता है. यही नहीं ग्रीन टी बढ़िया अस्ट्रिंजंट है, जो रक्त स्राव को नियंत्रित करती है और शरीर में कहीं भी लगे घाव को भरने में मदद करती है. ग्रीन टी को दिल की सेहत को सुधारने वाली औषधि के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है. इसके अलावा ग्रीन टी का उपयोग गैस भगाने, शरीर के तापमान को बनाए रखने, शुगर कंट्रोल करने, पाचन शक्ति को बढ़ाने में और मानसिक विकास को बेहतर करने के लिए किया जाता है. इसके सेवन से कोरोनरी धमनी नामक बीमारी से सुरक्षा होती है. यह उच्च रक्तचाप को कम करता है. अथरोसकलेरोसीस के कैंसर के विकास को रोकती है. गुर्दे की बीमारी से बचाती है. लू से लड़ने में मदद करती है. गठिया रोग को नियंत्रित करती है. ज़ुकाम को रोकती है और इंफ्लुएंजा से रक्षा करती है. मधुमेह, जिगर की बीमारी से बचाती है और वज़न घटाने में भी मदद करती है. तो आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए परिपूर्ण चाय का एक प्याला है ग्रीन टी. चाय का असली व पूरा आनंद उठाने के लिए इसके बनाने की विधि पर भी ध्यान देना चाहिए. यह देखना रोचक है कि अलग-अलग क़िस्म की चाय के लिए अलग-अलग ज़रूरतें होती हैं, जैसे पानी का तापमान और पत्ती को भिगोने का समय.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

अब सुधरेंगे हालात

ओलंपिक क्वालीफायर से पहले विश्व सीरीज़ हॉकी के आयोजन को लेकर आलोचना झेल रहे निम्बस स्पोर्ट्स और भारतीय हॉकी महासंघ ने 2012 लंदन ओलंपिक के लिए स्ट्राइव फोर गोल्ड मुहिम की घोषणा की है, जिसके तहत ओलंपिक पदक जीतने पर भारतीय टीम में शामिल सीरीज के खिलाड़ियों को दो करोड़ रुपये नक़द पुरस्कार दिया जाएगा. भारतीय टीम को 15 से 26 फ़रवरी तक दिल्ली में ओलंपिक क्वालीफायर खेलने हैं, जबकि विश्व सीरीज हॉकी 17 दिसंबर से 22 जनवरी तक खेली जानी है. आयोजकों ने घोषणा की है कि ओलंपिक क्वालीफायर के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने वाले सीरीज के सभी खिलाड़ियों को पांच-पांच लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा यदि टीम ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर लेती है तो इन खिलाड़ियों को पांच लाख रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे. भारतीय टीम यदि लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतती है तो उसमें शामिल सीरीज के खिलाड़ियों में दो करोड़ रुपये के पुरस्कार को बराबर बांटा जाएगा. रजत पदक जीतने पर एक करोड़ और कांस्य जीतने पर 50 लाख रुपये दिए जाएंगे.

निम्बस स्पोर्ट्स के सीओओ यानिक कोलासो ने कहा कि हमारा लक्ष्य हॉकी खिलाड़ियों की स्थिति में सुधार करके उच्चतम स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है. इसी वजह से हमने स्ट्राइव फोर गोल्ड कार्यक्रम की घोषणा की है. भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष आरके शेट्टी ने कहा कि लीग के ज़रिये भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक जैसे आयोजनों के लिए बेहतर तैयारी कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि ओलंपिक खेलों में सफलता राष्ट्रीय गौरव का विषय है. विश्व सीरीज हॉकी के ज़रिये खिलाड़ी इसकी बेहतर तैयारी कर सकेंगे. इससे पहले हॉकी इंडिया ने अपने सभी खिलाड़ियों को सीरीज से दूर रहने के लिए कहा है. भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच माइकल नोब्स पहले ही कह चुके हैं कि ओलंपिक क्वालीफायर की तैयारी के लिए शिविर को छोड़कर लीग में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए उनकी टीम में कोई जगह नहीं होगी.

नए कोच का सहारा

मिकी आर्थर को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है. इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार विदेशी कोच की नियुक्ति की है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व दक्षिण अफ्रीकी और वर्तमान में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कोच मिकी आर्थर को ऑस्ट्रेलिया का मुख्य कोच नियुक्त किया है. वह चयनकर्ता की भूमिका भी निभाएंगे. तैंतालीस वर्षीय आर्थर 2005 से 2010 तक दक्षिण अफ्रीकी टीम के मुख्य कोच थे. वह 2010 से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन रेट्राविजन वॉरियर्स के मुख्य कोच थे. वह टिम नील्सन की जगह लेंगे. आर्थर दक्षिण अफ्रीका में 15 साल तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने के बाद कोचिंग में आए. उन्होंने प्रथम श्रेणी मैचों में 13 शतक की मदद से 6657 रन, जबकि एक दिवसीय मैचों में 3774 रन बनाए. उन्हें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2015 में होने वाले विश्वकप तक कोच बनाया गया है. आर्थर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय टीम का कोच बनने का फिर से मौक़ा मिलने पर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं. ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट प्रतिभा की भरमार है और मुझे विश्वास है कि यह प्रतिभा ऑस्ट्रेलिया की सफलता सुनिश्चित करेगी. सीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेम्स सदरलैंड ने कहा कि आर्थर की ऑस्ट्रेलियाई कोच के रूप में शुरुआत न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ एक दिसंबर से ब्रिस्बेन में शुरू होने वाले टेस्ट मैच से होगी.

मुनाफ़े की लड़ाई

अमेरिका की बास्केटबॉल लीग मुसीबत में फंस गई है. खिलाड़ियों ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ख़िलाफ़ विद्रोह कर दिया है. लीग के मालिकों की खिलाड़ियों को मनाने की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं. खिलाड़ी हड़ताल पर जा रहे हैं. दरअसल, बास्केटबॉल अमेरिका का कमाऊ खेल है. वहां होने वाले लीग मुक़ाबलों के ज़रिये खिलाड़ी और टीम मालिक अरबों रुपये कमाते हैं. इस कमाई में सबका हिस्सा है. खिलाड़ियों को पहले 57 फ़ीसदी मिलता था. जून में वह समझौता ख़त्म हो गया. उसके बाद नए समझौते में खिलाड़ियों की हिस्सेदारी कम करने को लेकर विवाद हो गया. खिलाड़ी 52.5 फ़ीसदी तक लेने को तैयार हैं, लेकिन टीमों के मालिकों का प्रस्ताव 50-50 बांटने का है. इस पर खिलाड़ी राज़ी नहीं हो रहे हैं. इस मुद्दे पर कई हफ्तों से दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है. अब तक खिलाड़ियों की यूनियन ही मालिकों के साथ बातचीत कर रही थी. लेकिन बैठक के बाद यूनियन में भी विवाद खड़ा हो गया है. इसलिए यूनियन को ही भंग करने की बात उठ रही है. यूनियन के अध्यक्ष डेरेक फिशर ने भी हंटर की इस बात से सहमति जताई है कि मालिकों के साथ लेनदेन करने में यूनियन नाकाम रही है. फिशर ने कहा, यह वह मौक़ा है जहां से हम एक यूनियन के तौर पर आगे नहीं बढ़ सकते. हमने दो साल तक पूरी ईमानदारी से एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश की. लेकिन हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह प्रक्रिया काम नहीं कर रही है. लेकिन एनबीए भी झुकने को तैयार नहीं है. टीमों के मालिक कमाई को आधा-आधा बांटने पर तो राज़ी हो गए हैं. लेकिन एनबीए के कमिश्नर डेविड स्टर्न ने कहा है कि अगर समझौता नहीं होता है तो यह हिस्सेदारी मालिकों के पक्ष में 47-51 तक जा सकती है. अगर दोनों पक्ष राज़ी हो जाते हैं तो 2011-12 के सीजन के कुछ मुक़ाबले हो सकते हैं. स्टर्न ने 15 दिसंबर से 72 मुक़ाबलों के एक शेड्यूल का प्रस्ताव रखा है. लेकिन हंटर ने इसका जवाब साफ़ शब्दों में दिया है. उन्होंने कहा, खिलाड़ी किसी तरह की चेतावनी स्वीकार नहीं करेंगे. उनका मानना है कि इस तरह समझौता स्वीकार करने की चेतावनी देना एकदम नाजायज़ है.

हरभजन की नई पारी

हरभजन सिंह जल्द ही अपनी निजी ज़िंदगी की नई पारी शुरू करने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं. हाल में आई ख़बरों के मुताबिक़, भज्जी अपनी प्रेमिका गीता बासरा के साथ बहुत जल्द घर बसाने जा रहे हैं. दोनों की सगाई और रोका का कार्यक्रम तय हो गया है. उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में भज्जी और गीता का रोका हो जाएगा. ख़बर यह भी है कि ये सारे कार्यक्रम लंदन में होंगे, क्योंकि गीता की आधी फैमिली लंदन में रहती है. आजकल मैदान की जगह रियलिटी शो में नज़र आने वाले भज्जी के क़रीबी लोगों का कहना है कि वह रोका के 6 महीने के बाद सात फेरे ले लेंगे. भज्जी का तो पूरा परिवार पंजाब में रहता है, लेकिन भज्जी के रोके के लिए उनका परिवार भी लंदन जाएगा, क्योंकि रस्म के मुताबिक़ लड़के के पक्ष के लोग ही रोका के लिए लड़की के यहां जाते हैं. शादी पंजाब में होगी. फ़िलहाल यह क़रीबी सूत्रों के हिसाब से ख़बर है. भज्जी या गीता किसी ने भी इस बात की औपचारिक घोषणा नहीं की है. वैसे भी भज्जी का यह फ़ैसला ठीक समय लिया लगता है, क्योंकि टीम इंडिया ने तो इस समय उनका साथ छोड़ दिया, कहीं गीता भी उन्हें छोड़कर आगे न बढ़ जाए. शायद इसलिए भज्जी ने रोका करने की सोची. उम्मीद करते हैं कि हरभजन इतना ही ध्यान अपने खेल पर भी देंगे.

जीत कर भी हार गए

भारत ने कबड्डी में एक बार वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया. लेकिन जीतने के बाद जो बर्ताव खिलाड़ियों के साथ हुआ, उसने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया है कि देश में सिर्फ़ क्रिकेट की ही पूजा होती है. ग़ौरतलब है कि पंजाब के लुधियाना शहर में कबड्डी की पुरुष टीम ने फाइनल में कनाडा को हराया, जबकि भारतीय महिला टीम ने भी फाइनल में जीत हासिल की. कबड्डी में पारंपरिक तौर से भारत का दबदबा रहा है और भारत ने जीत के इस क्रम को टूटने नहीं दिया. पिछली बार भी भारत ने ही विश्व कप जीता था. भारत इटली को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल तक पहुंचा था, जबकि कनाडा ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल मुक़ाबले में हराया था. पाकिस्तान पिछली बार उपविजेता था. भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को मात दी. पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सभी महिला खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया है. महिलाओं को विश्व कप में पहली बार शामिल किया गया है.

कुछ दिन पहले ही महिला टीम की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें कई खिलाड़ियों को चोट भी आई थी. विश्व कप के उद्घाटन समारोह में जहां शाहरुख़ ख़ान को बुलाया गया था, वहीं समापन समारोह में अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण पहुंचे हुए थे. हालांकि इस बार का कबड्डी विश्व कप डोपिंग के मामलों को लेकर विवाद के घेरे में रहा. ऑस्ट्रेलिया की टीम को डोपिंग मामलों के कारण बाहर कर दिया गया था, लेकिन इस जीत को कई मायनों में अधूरा ही कहा जाएगा.

बेसिल डी ओलिवारा नहीं रहे

इंग्लैंड के पुराने हरफ़नमौला क्रिकेटर बेसिल डी ओलिवारा का निधन हो गया है. ओलिवारा वही क्रिकेटर हैं, जिन्हें 70 केदशक में साउथ अफ्रीका में व्याप्त रंगभेद नीति के कारण अपने देश के लिए खेलने का मौक़ा नहीं मिला था. अश्वेत खिलाड़ी ओलिवारा का जन्म 1931 में साउथ अफ्रीका के कैपटाउन शहर में हुआ था. 60-70 के दशक में साउथ अफ्रीका में रंगभेद नीति चरम पर थी. इस कारण गोरों की टीम में उन्हें स्थान नहीं मिला. आख़िर उन्होंने दूसरे देश इंग्लैंड के लिए खेलने का निर्णय लिया. वर्ष 1966 में उन्हें इंग्लैंड की टीम में जगह मिल गई. जल्द ही बतौर ऑल राउंडर उन्होंने टीम में जगह बना ली. इसके बाद 1968-69 में साउथ अफ्रीका दौरे के लिए जो इंग्लैंड की टीम चुनी गई, उसमें ओलिवारा का नाम भी शामिल था. यह बात साउथ अफ्रीका के क्रिकेट मठाधीशों को रास नहीं आई. उन्होंने इंग्लैंड से ओलिवारा को टीम से हटाने को कहा. इस घटना से विश्व क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की बड़ी बदनामी हुई. इंग्लैंड ने ओलिवारा को टीम से नहीं हटाया और यह सीरीज रद्द हो गई. इस घटना के बाद विश्व क्रिकेट से साउथ अफ्रीका का बहिष्कार किया गया. साउथ अफ्रीका पर 1970 से 1991 तक टेस्ट क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लग गया. इसका साउथ अफ्रीका को काफ़ी नुक़सान हुआ. साउथ अफ्रीका के कई क्रिकेटर्स का करियर बर्बाद हुआ. ओलिवारा ने इंग्लैंड के लिए 1966 से 1972 तक 44 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 40.06 की औसत से 2484 रन बनाए. इसके अलावा 47 विकेट भी झटके. क्रिकेट इतिहास का जो पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया, उस इंग्लैंड की टीम में भी ओलिवारा शामिल थे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिग बॉस में पॉर्न स्टार लाकर भी यह शो लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित तो नहीं कर पाया, लेकिन बॉलीवुड के निर्माता-निर्देशक और कलाकार उनकी तरफ़ तेज़ी से आकर्षित हुए.

ट्विंकल ने जलवे बिखेरे

सुपर स्टार की पत्नी होना कोई मामूली बात नहीं है. बात चाहे शाहरुख़ ख़ान की पत्नी गौरी ख़ान की हो या अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना की. वैसे गौरी ख़ान तो अपने पति की कामयाबी के साथ ग्लैमर का तड़का लगाने में कभी पीछे नहीं रहतीं, लेकिन अब ट्विंकल खन्ना ने भी ग्लैम फेसेस में अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है. मैगजीन कवर फेस बनाना बॉलीवुड का और ग्लैम वर्ल्ड का हॉट ट्रेंड बन गया है और ग्लैमर्स तड़का देने के विचार से ट्विंकल ने इसी ट्रेंड का इस्तेमाल किया है. अपनी बेहतरीन शेप्ड बॉडी और शाइनी एटीट्यूट को उन्होंने लोगों के बीच एक बार फिर से चर्चा का विषय बनाया है. दरअसल, ट्विंकल भी उन अभिनेत्रियों की कतार में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने एक मैगजीन कवर पर अपने जलवे बिखेर कर लोगों के बीच खलबली मचा दी है. ट्विंकल खन्ना देश की मोस्ट गॉर्जियस फेस और बेस्ट ड्रेस्ड वुमेन हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब तक इसे ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया गया था. लेकिन अब मशहूर मैगजीन वर्व ने इस बात को ऑथेंटिक बना दिया है. ट्विंकल खन्ना वर्व मैगजीन की तरफ़ से बेस्ट ड्रेस्ड वुमेन का टैग जीत चुकी हैं और इसी वजह से उन्हें मैगजीन के कवर पेज पर जगह दी गई है. कवर पेज पर उनके हुस्न का जादू बिखेरने के लिए मदद ली गई है फोटोग्राफर डब्बू रतनानी की और उन्हें स्टाइलिश बनाया है निशा जंगियानी ने. इस फोटो में उन्होंने पहना है तदाशी शोजी का वन शोल्डर ड्रेस, जिस पर सिल्वर सिक्यवेंस लगे हैं. इस ड्रेस को एक्सेसराइज किया गया है रोज गोल्ड फिनिश मेटल कफ और बड़े हुप इयरिंग्स के साथ. इसमें उन्होंने कोई ख़ास फैशन ट्रेंड को फॉलो नहीं किया है, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से ड्रेस पहनी है.

अनुष्का सही फ़ैसलों से सफल

बॉलीवुड में नई-नई एंट्री करने वाली कुछ ही ऐक्ट्रेसेस हैं, जो बॉलीवुड में अपने सही फ़ैसलों की वजह से अपनी पहचान बना पाई हैं. कुछ ख़ास ही फिल्मों में करने वाली अनुष्का शर्मा ने अपनी कामयाबी की दास्तां ख़ुद ही लिखी है. अभी हाल में अनुष्का शर्मा को बॉलीवुड सर्कल में अपने जीरो साइज़ फिगर के लिए जाना जा रहा था. लेकिन इसके साथ ही वह मशहूर हो रही हैं अपनी आने वाली फिल्म लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल के लिए भी. हॉट दिखने वाली अनुष्का जल्द ही कॉमेडी गर्ल बनने जा रही हैं. जी हां, वह विशाल भारद्वाज की अगली फिल्म मतरू की बिजली का मन डोला, में कॉमेडी करती हुई दिखाई देंगी. इस नए रोल के लिए अनुष्का बेहद एक्साइटेड हैं. उनका कहना है कि यह रोल मेरी सारी फिल्मों से अलग है, मुझे इस बात की ख़ुशी है कि निर्देशक ने इस फिल्म के लिए मुझे चुना. मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी है और पढ़ते समय हंस-हंस कर पेट में दर्द होने लगा. मुझे यक़ीन है कि दर्शक मेरे इस किरदार को भी काफ़ी पसंद करेंगे. इस फिल्म में अनुष्का के साथ इमरान ख़ान हैं. वैसे दर्शकों को उनकी ज़्यादातर फिल्में पसंद आई हैं. अब तक हर रोल में चाहे वह एक आदर्श पत्नी का रोल हो या एक एस्पायरिंग करियर ओरिएंटेड वुमेन का, चाहे वह एक बदमाश गर्ल का हो या मोटिवेट करने वाली गर्ल फ्रेंड का, सभी रोल्स में वह फिट बैठी हैं और लोगों को अपनी अभिनय प्रतिभा का क़ायल बनाया है. देखते हैं कि अब उनके कॉमेडी रोल को लोग पसंद करेंगे या नहीं.

फिल्म प्रीव्यू

लेडीज वर्सेस रिकी बहल

साल 2010 की सफलतम फिल्म बैंड बाजा बारात की टीम फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल के साथ एक बार फिर धमाका करने के लिए तैयार है. मनीष शर्मा निर्देशित और अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह अभिनीत इस फिल्म का लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है. फिल्म बैंड बाजा बारात और अब लेडीज वर्सेस रिकी बहल में रोमांस करने वाली यह जोड़ी वास्तविकता में भी अपने रिश्ते के कारण ख़बरों में रहता है. हालांकि रणवीर और अनुष्का अपने रिश्ते को सिर्फ़ दोस्ती बताते हैं. पहली फिल्म में दोनों की जोड़ी को सराहा गया था. शाहरुख़ ख़ान के साथ यशराज की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से बॉलीवुड में क़दम रखने वाली अनुष्का इस फिल्म में नए अवतार में नज़र आएंगी. फिल्म में अनुष्का का बिकनी अवतार नज़र आएगा, जिसकी गवाह बनेगी गोवा की ख़ूबसूरत लोकेशन. अपनी पहली ही फिल्म बैंड बाजा बारात से लोकप्रिय हुए अभिनेता रणवीर सिंह की यह दूसरी फिल्म है. फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल में रणवीर सिंह कई रूपों में नज़र आएंगे. दरअसल, फिल्म में रणवीर ने एक कॉन-मैन का किरदार निभाया है, जो अलग-अलग जगहों की लड़कियों के साथ धोखेबाज़ी करता है. महज़ चार फिल्मों से ही अनुष्का बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं. अभिनय और नृत्य कौशल के कारण अनुष्का बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्री होने की क़ाबिलियत रखती हैं. अपनी इस नई फिल्म में अनुष्का एक दिलचस्प भूमिका निभा रही हैं, जिसमें वह धोखेबाज़ी करने में भी बाज़ नहीं आती हैं. लेडीज वर्सेस रिकी बहल में रणवीर ने रिकी बहल का किरदार निभाया है, जो हमेशा ही लड़कियों को धोखा देता रहता है. आख़िरकार उसे भी एक धोखेबाज़ मिल ही जाती है, जो अनुष्का शर्मा हैं. फिल्म में जहां अनुष्का का बिकनी अवतार नज़र आएगा, वहीं रणवीर सात अवतारों में नज़र आएंगे. मनीष शर्मा के निर्देशन में बनी लेडीज वर्सेस रिकी बहल एक कॉमेडी फिल्म है, जो दर्शकों को गुदगुदाएगी. फिल्म का निर्माण आदित्य चोपड़ा के बैनर तले हुआ है. फिल्म में रणवीर, अनुष्का के अलावा परिणीती चोपड़ा और दिपन्निता शर्मा ने भी अभिनय किया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

शर्लिन नए रोल में

काफ़ी वक़्त से शर्लिन चोपड़ा की कोई खोज ख़बर नहीं मिल पा रही थी. दरअसल, वह अपने फैंस के सामने सरप्राइजिंग गुड न्यूज़ के साथ आना चाहती थीं. उनके चाहने वालों के लिए ख़ुशख़बरी है कि जल्द ही शर्लिन लोगों के बीच नज़र आएंगी. बॉलीवुड में सैक्स सिंबल के रूप में अपनी पहचान बना चुकी आइटम गर्ल शर्लिन चोपड़ा अब प्रॉस्टिट्यूट बनेंगी. अरे रियल लाइफ में नहीं रील लाइफ में शर्लिन को उनके एक्पोज के चलते फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर मिल ही गया. काफ़ी दिन से शर्लिन ख़बरों से ग़ायब रहीं, लेकिन एक बार फिर वह सुर्ख़ियों में आ चुकी हैं. वह हमेशा ही ख़बरों में बने रहने के लिए एक नई कंट्रोवर्सी पैदा करती रहती हैं. लेकिन इस बार वह अपनी आने वाली नई फिल्म को लेकर ख़बरों में आ गई हैं. शर्लिन को स्वप्ना जोशी वाघमारे ने अपनी फिल्म के लिए चुना है, जिसमें शर्लिन एक प्रॉस्टिट्यूट का रोल करने वाली हैं. इस फिल्म में इस हॉट एक्ट्रेस के साथ एक नए चेहरे को कास्ट किया जाएगा. वैसे स्वप्ना नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान शाह को इस रोल के लिए साइन करना चाहतीं थीं, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया. आपको बता दें कि फिल्म में शर्लिन के अपॉजिट कैरेक्टर के लिए स्वप्ना विवान को लेना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने रेडलाइट एरिया पर बन रही इस फिल्म में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई. इसके बाद स्वप्ना ने एक नए एक्टर को इस कैरेक्टर के लिए कास्ट करने का फ़ैसला किया है. अभी एक्टर की तलाश चल रही है. वैसे तो शर्लिन बिना किसी फिल्म के ही एक्सपोज़ करती हैं, लेकिन अब वह फिल्म में सैक्स वर्कर का काम करने जा रही हैं, ऐसे में क्या रंग दिखाती हैं, यह तो आने वाली फिल्म में उनका रोल ही बताएगा.

हॉलीवुड से...

रास न आई लियोन

साल 2010 में मैक्सिम पत्रिका द्वारा टॉप 12 पॉर्न स्टार में शामिल की गई इंडो केनेडियन स्टार और अडल्ट फिल्म ऐक्ट्रेस सन्नी लियोन को कई मैगजीन जैसे डेबॉनेयर, पेंटहाउस, हस्लर, हाई सोसायटी और स्वैंक में देखा जा चुका है. उनके माता-पिता मूल रूप से भारत से हैं, उनकी मां हिमाचल से तो पिता दिल्ली के हैं. इसी वजह से सनी को लोग कैरन मल्होत्रा के नाम से भी जानते हैं. सन्नी केवल पॉर्न फिल्मों और मैगजीनों के लिए मॉडलिंग नहीं करतीं, बल्कि कई बिजनेस भी चलाती हैं. बिग बॉस के घर वालों की ही तरह सन्नी को कोई नहीं पहचानता था, जब तक उन्होंने देश के रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में हिस्सा नहीं लिया था. लेकिन बिग बॉस में आने के साथ ही उनकी चर्चा देश के गांव-गांव तक पहुंच गई. अचानक ही बिग बॉस में नया मेहमान देखकर एक बार को तो दर्शकों में भी उत्साह देखा गया, मगर पॉर्न स्टार का नाम सुनते ही लोगों की दिलचस्पी इसमें कम ही हो गई. हालांकि सनी ने अपनी तरफ़ से यह दलील भी रख दी कि भारत में एडल्ट इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री न होने की वजह से यहां पॉर्न स्टार को कलाकार नहीं माना जाता, लेकिन उनकी इस बात से शायद ही आम लोगों की पसंद-नापसंद पर कोई फ़र्क़ पड़ता है. बिग बॉस में पॉर्न स्टार लाकर भी यह शो लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित तो नहीं कर पाया, लेकिन बॉलीवुड के निर्माता व निर्देशक और कलाकार उनकी तरफ़ तेज़ी से आकर्षित हुए. जहां कमाल ख़ान ने उनसे शादी करने की इच्छा रख दी, वहीं महेश भट्ट ने अपनी अगली फिल्म जो फिल्म मर्डर का सिक्वल है, उसमें सनी को कास्ट करने की बात कह दी है. एक के बाद एक आती विदेशी एक्ट्रेसेस और उन्हें भारत की फिल्म इंडस्ट्री से धड़ल्ले से मिलते ऑफर का यह ट्रेंड देखकर लगता है कि जल्द ही भारतीय सिनेमा में उनकी अच्छी पैठ होने वाली है, और दर्शकों को पर्दे पर देशी ब्यॉज के साथ विदेशी बालाओं के रोमांस के क़िस्से देखने को मिलेंगे. बॉलीवुड को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने वाली अभिनेत्रियों जैसे हेमा मालिनी, वैजयंती माला और दूसरी अभिनेत्रियों की ख्याति को क़ायम रखने का सिलसला विदेशी अभिनेत्रियों की पैठ से ख़त्म हो सकता है, ऐसा अंदेशा है. लेकिन इस बात की ज़िम्मेदारी बॉलीवुड के बड़े नामों पर है कि वे भारतीय कला और कलाकारों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाते रहें. बहरहाल, विदेशी बालाओं ने देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

8 दिसंबर, (जन्मदिन पर विशेष)

हिंदी सिनेमा के इतिहास का उज्जवल अध्याय

धर्मेंद्र फिल्म जगत में सपने लेकर आए थे. उनका कोई गॉड फादर नहीं था. उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा. 1960 के दशक में विभिन्न किरदारों से सजीं धर्मेंद्र की 52 फिल्में रिलीज़ हुईं, जिनमें अधितकतर समाज की समस्याओं और रोमांस पर आधारित थीं. यह वह ज़माना था जब फिल्में बनाने का मक़सद केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी देना होता था. 1970 के दशक में फूल और पत्थर की सफलता ने धर्मेंद्र ही मैन के रूप में स्थापित किया. इसी दशक में धर्मेंद्र के हिस्से में इसी इमेज को ध्यान में रखकर फिल्में बनीं. इसी दशक में धर्मेंद्र ने 63 सफल फिल्मों में काम किया. फिल्म शोले ने हिंदी फिल्मों के इतिहास में सफलता के एक नए अध्याय की शुरुआत की. 36 वर्ष गुज़र जाने के बाद भी शोले के वीरू का किरदार लोगों की जुबां पर आम है.1980 के दशक में उन्होंने 75 फिल्मों में काम किया. उस समय धर्मेंद्र की इमेज बॉक्स आफिस पर ऐसी बन चुकी थी, जो पर्दे पर एक साथ 10-20 लोगों से लोहा लेता हुआ नज़र आता था. अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी ग़ुलामी ने धर्मेंद्र को एक अमिट किरदार दिया. ढलती उम्र के बावजूद अपने फिल्मी करियर के चौथे दशक में भी धर्मेंद्र के जोश में कोई कमी नहीं आई. उन्होंने 44 फिल्मों में काम किया. आज वह उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जहां संघर्ष, जुस्तजू, इच्छाओं, शोहरत और कामयाबी कोई मायने नहीं रखती. इन सबके बावजूद धर्मेंद्र फिल्मी पर्दे से अपना रिश्ता ख़त्म करने को तैयार नहीं हैं. इस साल वह टीवी चैनल पर बतौर जज अपनी नई पारी का आगाज़ कर चुके हैं. वह अपनी जीवनी उर्दू में लिख रहे हैं. धर्मेंद्र को फिल्मों मे लाने वाले अर्जुन हिंगुरानी उनकी सादगी के दीवाने हैं.

कमल देवबंदी
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 05 दिसंबर-11 दिसंबर 2011

www.chauthiduniya.com

किसान आत्महत्या कब रुकेगी

प्रवीण महाजन

विदर्भ के किसान बदहाल है और यहां के राजनेता बदमाश हैं. वे नहीं चाहते कि किसान खुशहाल हों, उनकी समस्याओं का समाधान हो, वे प्रगति करें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों. इसलिए कृषि-कृषक से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान करना नहीं चाहते है. यदि किसानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर दिया गया तो राजनीति करने के लिए मिलने वाला एक भावनात्मक मुद्दा भी उनके हाथ से निकल जाएगा. यही यह वजह है कि सत्ता के राजनीतिक दांवपेंच में आज किसान-कृषि मात्र एक मुद्दा बनकर रह गया हैं. जब भी महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र नागपुर में होता है या चुनाव का मौसम आता है तो नेताओं को विदर्भ के किसानों की दुर्दशा की चिंता सताने लगती है. आंदोलन की घोषणाएं होती हैं. कभी-कभार आर्थिक पैकेज की घोषणा करके तात्कालिक लाभ पहुंचाने की घोषणा ज़रूर की जाती है पर उसका लाभ किसानों को आज तक कितना मिला है? यह शोध का विषय है, लेकिन सतापक्ष व विपक्ष में बैठने वाले नेताओं ने आज तक समस्या के स्थायी समाधान करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. इसलिए विदर्भ में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रूक रहा है. यह कहना है गाड़ेघाट (भिवापुर तहसील) निवासी कृषक भास्कर रेहपाड़े और मोरेश्वर शिंदे का.

किसानों की आर्थिक बदहाली का पता इससे ही चल जाता है कि चालू वर्ष 2011 में ही अब तक 674 किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन सरकार ने उनकी अब तक कोई सुध नहीं ली है. किसानों को कभी अतिवृष्टि डूबा देती है तो कभी सूखा, अकाल उसे सूखा देता है. कभी घटिया बीज उसका आर्थिक शोषण कर संकट में डाल देता हैं. यदि कभी-कभार फसल अच्छी हो गई उसकी सही क़ीमत नहीं मिलती है. उनके कृषि उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने में सरकार हमेशा पीछे ही रहती है. उपज की लागत से कम बाज़ार भाव मिलने से किसान बैंकों का कर्ज़ समय पर नहीं लौटा पाते हैं. घर-परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पाते हैं जिससे वे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से टूट जाते हैं. जब कहीं से कोई सहायता मिलने की आस नहीं बचती है तो वे निराशा में आत्महत्या करने जैसा क़दम उठाते हैं. रोज हो रही आत्महत्याओं के कारण विदर्भ में निरंतर कलावतियों(किसान की विधवाओं) की संख्या में बढोत्तरी होती जा रही है. सरकार हमेशा किसानों की आत्महत्याओं की घटनाओं के आंकड़ों को कम कर आंकने का प्रयास करती है, लेकिन अब उसकी आंख खुल जानी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय अपराध सर्वे ब्यूरो की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक किसान आत्महत्याएं हो रही हैं.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने दावा किया था कि वर्ष 2010 में 365 किसानों ने आत्महत्या की थी और उसमें से मात्र 65 ने कर्ज़बाज़ारी के कारण आत्महत्या की थी. इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय अपराध सर्वे आयोग की जारी रिपोर्ट से उनके दावे की पोल खुल जाती है. रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 16 वर्षों में पूरे देश में 2 लाख 52 हज़ार किसानों ने आत्महत्या की. वर्ष 2010 में पूरे भारत में 15 हज़ार 964 किसानों ने आत्महत्या की है, जिनमें सबसे अधिक महाराष्ट्र में 3 हज़ार 141 कृषकों ने आत्महत्या की है. आयोग की रिपोर्ट शरद पवार के दावे को पूरी तरह झुठला देता है. इसके बाद भी राज्य के सत्ताधीश बेशर्मी की चादर ओढ़कर अपने दावे को सही साबित करने के लिए जब तब तर्क देते रहते हैं. विदर्भ में आत्महत्याएं हो रही हैं उसके लिए राज्य व केंद्र सरकार की कृषि नीति ज़िम्मेदार है. किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए उपाय योजनाओं की घोषणा की जाती है पर उसके क्रियान्वयन की ख़ामियों की ओर ध्यान नहीं देती हैं. ये उपाय योजनाएं भी तात्कालिक होती हैं. लिहाज़ा समस्याएं जस की तस हर वर्ष बनी रहती हैं. सवाल यह उठता है कि जब सरकार कपास की लागत के अनुसार क़ीमत नहीं दे सकती है तो उसके निर्यात पर पाबंदी क्यों लगाती है? सरकार की कृषि नीति की पोल इसी से खुल जाती है कि संकट में पड़ी किंगफिशर विमान सेवा के मालिक को आर्थिक मदद करने की जल्दी रहती है फिर चाहे मदद मांगी गई हो या नहीं पर बदहाल किसानों द्वारा आर्थिक मदद मांगने पर भी सरकार मदद को आगे नहीं आती है. इसे देश की कृषि-किसान की उपेक्षा करना नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? ऐसा लगता है कि किसान मरता है तो मरने दो का सिद्धांत अघोषित रूप से सरकार अपना चुकी है.

सच्चाई यही है कि रोज़ मरने वाले के लिए कौन रोता है. किसान आत्महत्या

के लिए कुख्यात यवतमाल ज़िले के गांवों का दौरा कर नेता अपनी राजनीति चमकाते हैं. विधानसभा व संसद के सदन में कलावती जैसी किसान विधवाओं का ज़िक्र कर लच्छेदार भाषण देकर अपनी बिरादरी व मीडिया में वाहवाही लूटते हैं. राहुल गांधी हों या नितिन गडकरी (जिन्होंने हाल ही में राहुल की कलावती को एक लाख की मदद की और किसान आत्महत्याग्रस्त गांवों को गोद लेने की घोषणा की है.) या अन्य कोई नेता हो, वे वहां जाकर आश्वासनों-वादों की ख़ैरात बांटकर वापस चले जाते हैं. उसके बाद उस गांव की क्या दशा है, जिनकी मदद की उनकी हालत में सुधार हुआ है कि नहीं, इन बातों पर विचार करने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं रहता है. न ही इतना समय रहता है कि वे जाकर उस गांव का जायजा लें. इसका मतलब यह है कि वे राजनीतिक सोच के साथ वहां जाते हैं पर समस्या का जड़मूल से समाधान करने की दृष्टि का अभाव इन नेताओं मे साफ झलकता है. इसलिए अब तक राज्य व केंद्र सरकार किसान आत्महत्या का तोड़ निकालने में असफल रही हैं. उनको सिर्फ करोड़ों के कागज़ी पैकेज बनाकर घोषित करने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है. अब तक किसानों की मदद के लिए सारे आर्थिक पैकेज नाकाफ़ी ही साबित हुए हैं. पैकेजों के साथ जो शर्तें सरकार लगाती है उससे उसके क्रियान्वयन में दिक्कत होती है और जिन किसानों को सबसे अधिक आर्थिक मदद की ज़रूरत रहती है, वे ही उसके लाभ से वंचित कर दिए जाते हैं.

पिछले सात साल में हुई किसान आत्महत्या की घटनाओं पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि सरकार की उपाय योजनाओं का इन पर कोई असर नहीं हुआ है. विदर्भ के किसानों का सुसाइड जोन अब भी बना हुआ है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004 में 456, 2005 में 668, 2006 में 1586, 2007 में 1556, 2008 में 1680, 2009 में 1054, 2010 में 826 किसानों ने आर्थिक बदहाली, कर्ज़ के बोझ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण खेती को हुए नुक़सान के चलते आत्महत्या को गले लगाया है और इतने ही किसानों की विधवाओं की संख्या में इजाफ़ा हुआ है. इसका तो यही मतलब निकलता है कि राज्य व केंद्र सरकार ने किसान आत्महत्या के लिए कुख्यात ज़िले और गांवों की तस्वीर बदलने के लिए कोई ठोस क़दम नहीं उठाया है सिवाय पैकेज घोषित करने के. चालू वर्ष 2011 में ही अब तक (15 नवंबर तक) 674 किसानों ने आत्महत्या की है और उक्त आंकड़े में और इजाफ़ा हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी. महिला किसानों द्वारा आत्महत्या करने की नई बात भी सामने आयी है. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में साफ-साफ कहा गया है कि महिला किसानों की हालत अधिक गंभीर है. पिछले वर्ष 2010 में देश में 2372 महिला किसानों ने आत्महत्या की है. इनमें सबसे अधिक कर्नाटक में 457, आंध्रप्रदेश में 395, छत्तीसगढ़ में 348, मध्यप्रदेश में 264 और महाराष्ट्र में 149 महिला कृषकों ने आत्महत्या किया है. जिस गति से किसानों की आत्महत्या विदर्भ में जारी है यदि उसे रोकने के उपाय नहीं किए गए तो महिला कृषकों के आंकड़े में महाराष्ट्र भविष्य में आगे निकल सकता है. इसकी वजह यह है कि विदर्भ में किसानों की आत्महत्याओं के साथ ही किसान विधवाओं की संख्या तेज़ी से बढ़ रही हैं. इन विधवाओं के कंधों पर ही घर के भरण-पोषण करने की ज़िम्मेदारी आ जाती है. साथ ही इन किसान विधवाओं को शासन-प्रशासन के साथ ही पारिवारिक व सामाजिक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है. इससे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती है. इस सब के बीच बस एक ही सवाल गूंजता है कि आख़िर विदर्भ में कब रुकेगी किसान आत्महत्याएं?

हर साल की भांति इस बार भी दिसंबर माह में उप राजधानी नागपुर में पिकनिक (शीतकालीन) सत्र का आयोजन 12 दिसंबर से किया जा रहा है. राज्य के देव (मंत्री-विधायक-अफसर) देवनगरी (मुंबई) छोड़ नागपुर पधार रहे हैं. चारों ओर किसान आंदोलन हो रहे हैं. किसान आत्महत्या के नाम पर राजनीति तेज़ हो गई है. पूरा प्रशासन उनकी आवभगत में जुटा हुआ है. पुलिस बंदोबस्त के नाम पर जनता की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, लेकिन जनता की मुश्किलों से सरकार को कोई फर्क़ नहीं पड़ता है. फिर यह सवाल किया जा रहा है कि इस साल के नागपुर अधिवेशन से विदर्भ के किसानों को क्या मिलने वाला है? विदर्भ के लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है? सबसे अहम सवाल यही है कि विदर्भ में हताशा-निराशा से ग्रस्त किसानों का जीवन खुशहाल कब होगा? उनकी आत्महत्याओं की घटनाओं पर सरकार कब रोक लगा पाएगी? कृषक आत्महत्याग्रस्त परिवारों का पुनर्वास कब होगा? आदि सवालों का जवाब राज्य का कोई मंत्री-अफसर व नेता देने को तैयार नहीं है. इसकी वजह यह है कि ये लोग समस्या का पूरी तरह समाधान करने के विषय पर कभी सोचने की जहमत ही नहीं उठायी है. बस समस्या को टालने के लिए तात्कालिक क़दम उठा कर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली है. जिसे राज्य की जनता और किसानों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

सहकारी बैंकों में चल रहे इस गड़बड़झाले का तब पता चला जब सहकार पीड़ित गुंतवणूकदार संघर्ष समिति नागपुर के अध्यक्ष व वरिष्ठ समाजसेवक उमेश चौबे ने सूचना के अधिकार के मार्फ़त बैंकों संबंधी जानकारी मांगी.

मनपा में सत्ता चाहे कांग्रेस-राकांपा की हो या फिर भाजपा-शिवसेना की सफाई कर्मचारियों की स्थिति नहीं बदली है.

महाराष्ट्र हलचल

मुंबई स्थित राजभवन में विदेशी वाणिज्य दूतों के सम्मान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करते राज्यपाल के. शंकरनारायणन. उनके साथ सौ. शंकरनारायणन, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, लोक निर्माण व पर्यटन मंत्री छगन भुजबल, राज शिष्टाचार मंत्री सुरेश शेट्टी और वाणिज्य दूत संघ की मुखिया एटोनिओ बुलॉन .

भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर आदरांजलि अर्पित करने के पश्चात मंत्रालय के कर्मचारियों व पुलिस जवानों को राष्ट्रीय एकात्मता की शपथ दिलाते प्रदेश के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण.

चर्चगेट स्थित पार्टी कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ कांगेस में शामिल होने पर नांदेड़ के पूर्व महापौर मकबूल सलीम का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण. इस मौके पर उनके साथ हैं राज्यमंत्री डी.पी. सावंत, विधायक ओमप्रकाश पोकर्णा, भीषण कुमार यादव, चंद्रशेखर गावडे, एड. नरेन्द्र सब्बनवार व अन्य गणमान्य लोग.

नरीमन प्वाइंट स्थित भाजपा कार्यालय में बारामती तहसील के वरिष्ठ राकांपा नेता व पूर्व ज़िला परिषद सदस्य ज्ञानेश्वर (बापू) कौल अपने समर्थकों के साथ पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, विधायक विनोद तावड़े, विधायक चंद्रकांत दादा पाटिल, पुणे ज़िलाध्यक्ष नामदेव ताकवड़े, ज़िला महासचिव दिलीप खैरे, शामराव चकोर की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होने की घोषणा करते हुए.

दक्षिण नागपुर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी महासचिव व सांसद विलासराव मुत्तेमवार व उनकी धर्मपत्नी को गांधी प्रतिमा भेंट कर सम्मानित करते प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे. उनके साथ मौजूद हैं पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे, विधायक दीनानाथ पडोले, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध मोहिते, ज़िलाध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता.

सेन्ट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नागपुर की ओर से आयोजित समारोह में केंद्रीय युवा कल्याण व खेल मंत्री अजय माकन, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अनीस अहमद, अतुल कोटेचा सत्कारमूर्ति प्रमिला नारनवरे, मीरा बड़वाइक, सुधा इरस्कर, ज्योत्सना मेरी और नफीसा अंसारी .

नागपुर में शिवसेना के विदर्भस्तरीय पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधि शिविर को संबोधित करते सेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे व मंचासीन अन्य पार्टी पदाधिकारी.

सफाईकर्मियों की सुध कौन लेगा

मयूर रंगारी

राह मौत तो आनी ही है, लेकिन उससे पहले यदि नौकरी में स्थायी हो जाऊं, तो ज़िंदगी भर की मेहनत सफल हो जाएगी. यह कहना है कल्पना कोचे का, जो पिछले 20 वर्षों से नागपुर महानगर पालिका में अस्थायी सफाई कर्मचारी हैं. यह पीड़ा सिर्फ एक कल्पना की नहीं है, बल्कि नागपुर मनपा में ऐसे सैकड़ों अस्थायी सफाई कर्मचारी की है, जो 18-20 वर्षों से स्थायी होने का इंतज़ार कर रहे हैं. इनमें से ज्यादातर की उम्र के 40 पार कर चुकी है. नागपुर मनपा के अस्थायी सफाई कर्मचारियों की पूरी ज़िंदगी नौकरी या फिर मौत में से किसी एक के पहले आने, इसकी राह देखने में बीत जाती है. मनपा के स्थाई-अस्थाई सफाई कर्मचारियों में से लगभग 80 फ़ीसदी ऐसे कर्मचारी हैं, जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं. एक अध्ययन के अनुसार महाराष्ट्र में हर वर्ष 250 सफाई कर्मचारियों की मौत बीमारियों से हो जाती है. दुर्भाग्य यह है कि पूरे शहर की गंदगी उठाकर लोगों को कई बीमारियों से बचाने वाले इन सफाई कर्मचारियों को सरकारी अस्पताल की सुविधा तक नहीं है. मनपा में सत्ता चाहे कांग्रेस-राकांपा की हो या फिर भाजपा-शिवसेना की सफाई कर्मचारियों की स्थिति नहीं बदली है. वसंता चवरे 21 वर्ष, मुकेश पसेरकर 21 वर्ष, मिलिंद नागदेवे 22 वर्ष, मीना चवरे 20 वर्ष और दुर्गाबाई गौते 16 वर्ष नागपुर मनपा में ऐसे कई सफाई कर्मचारी हैं, जो पिछले 15 से 20 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में अस्थायी तौर पर नौकरी कर रहे हैं. कई लोगों की अस्थाई तौर पर काम करते हुए मृत्यु भी हो गई, लेकिन उनके परिवार को कुछ नहीं मिला. जबकि, अनुकंपा के लगभग एक हज़ार मामले लंबित हैं. एक सफाई कर्मचारी ने चुटकी लेते हुए कहा कि मनपा में हम लोग इतने अपनी ज़िंदगी दे चुके हैं कि ये नेता यदि इन्हें ही भी बेच दे तो पूरे साल भर का मनपा का खर्चा निकल जाएगा. इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सफाई कर्मचारियों की हालत कैसी है?

सैकड़ों मरे, हज़ारों बीमार

वीजेंद्र डोंगरे, प्रदीप डोंगरे, राजेश डोंगरे, सुधाकर मेश्राम, संजय कुंभलकर, अशोक चव्हाण, विनोद बुरबुरे ये ऐसे ही अस्थाई सफाई कर्मचारियों के नाम हैं, जिनकी मौत किसी न किसी बीमारी के कारण हुई है. यह नाम केवल नागपुर मनपा के आशीनगर ज़ोन के वार्ड क्र. 8 में सफाई करने वाले कर्मचारियों के हैं. ऐसे में नागपुर शहर के अन्य वार्डों की स्थिति क्या होगी? बावजूद इसके लापरवाही का आलम यह है कि सफाई कर्मचारियों को काम के दौरान न तो रेनकोट दिए जाते हैं और न ही मास्क. ठंड के समय गर्म कपड़े और बारिश के समय रेनकोट तक नहीं दिए जाते हैं. इस वजह से उन्हें कई बीमारियां हो जाती हैं. ये सफाईकर्मचारी दमा और त्वचा रोग के अलावा कैंसर, टी.बी., डायरिया, मलेरिया, पीलिया आदि बीमारियों से भी पीड़ित हैं. राज्य या केंद्र सरकार या फिर निजी संस्थान में काम करने वाले किसी भी साधारण कर्मचारी को ईएसआईसी सरकारी अस्पताल की सुविधा मुहैया कराई जाती है, लेकिन मनपा, नपा में काम करने वाले सफाई कर्मचारी को यह सुविधा नहीं है. इनका आधा वेतन केवल बीमारियों के इलाज में ही खर्च हो जाता है. चौथी दुनिया ने जब शहर में घूमकर स्थिति का जायज़ा लिया तो पाया कि कई सफाई कर्मचारी काम पर अपने साथ दवाइयां भी लाते हैं. उनकी स्थिति एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी हो गई है. उपेक्षित दलितवाद संगठन के संस्थापक लक्ष्मण शुक्ला ने कहा कि संविधान में सभी को समान अधिकार दिया गया है, लेकिन जिन लोगों के हाथों में सत्ता है, उन्होंने कभी यह अधिकार सफाई कर्मचारियों को नहीं दिया. उन्होंने बताया कि बर्डी स्थित हरदेव होटल के सामने पी.डब्ल्यू.डी. की ज़मीन पर स्वीपर को दुकान बनाने के लिए जगह दी गई थी. वहां गैरेज, ममता ऑटो वर्क्स, मधु रेडियो, मकरंद इलेक्ट्रीकल्स, जगदीश मोटर रिवाइंडिंग, नरेंद्र टेलर, खरे वॉच आदि 14 दुकानें थीं. इससे समाज में काफी अच्छा संदेश गया कि वे भी व्यवसाय कर सकते हैं. वर्ष 2003 में लोक कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने सड़क चौड़ी करने का कारण बताकर सभी दुकानों को तोड़ दिया. आज तक उन दुकानदारों को पर्याप्त जगह नहीं दी गई है. शुक्ला का कहना है कि नागपुर के बारासिंगल, पांचपावली, सिरसपेठ आदि क्षेत्रों में जाकर नेताओं और अधिकारियों को देखना चाहिए कि योजना के तहत मिले करोड़ों रुपये से आखिर कितने घरकुल बनाकर दिए गए? आखिर योजना का पैसा गया कहां? ठेकेदारी प्रथा भी बंद करने की मांग उन्होंने की.

कई डिग्रियां फिर भी हाथों में झाड़ू

यदि आपका बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त है तो आप चाहेंगे कि वह नौकरी में अच्छे ओहदे पर काम करे, लेकिन सफाई कामगारों की स्थिति ठीक इसके उलट है. नागपुर महानगर पालिका में ही करीब 247 ऐसे सफाई कर्मचारी हैं, जिन्होंने कम से कम स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की हैं. इसके बावजूद मनपा उनसे सफाई का काम ले रही है. हालांकि इनमें से कुछ को लिपिक का काम दिया गया है, लेकिन उनका ओहदा सफाई कर्मचारी का ही रखा गया है. पिछले कई वर्षों से सफाई कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे लक्ष्मण शुक्ला ने बताया कि नागपुर मनपा में ज्योति वर्से (एम.ए.), माया शुक्ला (एम.ए.), राजेंद्र खोटे (एम.कॉम.), धीरज शुक्ला (एल.एल.बी, एम.एस.डब्ल्यू.), अमित हाडोती (बी.कॉम.,एस.आई.), धर्मेश सीरसवान (डी.फॉम.,एस.आई.), रजनी चव्हाण (एल.एल.बी.), सुधीर डैगोर (बी.कॉम.), मुकेश सिक्कलवार (बी.कॉम.), मनीष शुक्ला (बी.कॉम.) आदि वेतन तो सफाई कर्मचारी का उठा रहे हैं, लेकिन उनसे पिछले 6-7 वर्षों से लिपिक का काम लिया जा रहा है.

बीएससी पास नितिन प्रताप

हर समस्या हल होगी : महापौर

महापौर अर्चना डेहनकर से इस संबंध में जब चर्चा की गई, तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज़ कर दिया. श्रीमती डेहनकर ने कहा कि जो सफाई कर्मचारी नाले और गटर की सफाई का काम करते हैं, उन्हें मनपा की ओर से जूते दिए गए हैं, लेकिन वे पहनते नहीं हैं. महापौर ने कहा कि पहले अस्थाई सफाई कर्मचारियों को महीने में केवल 10-12 दिन काम मिलता था, लेकिन भाजपा-शिवसेना के प्रयास से अब उन्हें महीने में 26 दिन काम मिलता है. सफाई कर्मचारियों की कई समस्याएं हैं और उन्हें धीरे-धीरे हल किया जा रहा है.

मनपा की दोहरी नीति

पागे समिति के अनुसार जो सफाई कर्मचारी उच्च शिक्षित है, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार किसी भी विभाग में प्रमोशन देने की बात कही गई है, लेकिन इन सिफ़ारिशों को लागू करते समय भी मनपा के नेताओं और अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों पर अन्याय किया है. ऐसा ही एक ताज़ा मामला मनपा में सामने आया है. मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक में यह तय किया गया कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का प्रमोशन केवल उसी विभाग में होगा, जबकि अन्य विभागों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का प्रमोशन किसी भी विभाग में किया जा सकेगा. बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग के 58 सफाई कर्मचारियों को मलवाहक जमादार के पद पर प्रमोशन दिया गया. लेकिन ग़ौर करने वाली बात यह है कि इससे किसी भी कर्मचारी का कैडर नहीं बदलता, बल्कि वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही रहता है. वहीं दूसरे विभाग के 6 कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में जूनियर क्लर्क के रूप में पदोन्नत किया गया. शुक्ला ने इसे सरासर बेइमानी बताया है.

माधुरी मलिक

मनोज सांगले, नगर सेवक   लक्ष्मण शुक्ल, दलितवाद संगठन

30 हज़ार सफाईकर्मियों की ज़रूरत

जानकारी के अनुसार एक हज़ार लोगों के पीछे एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की जानी चाहिए. नागपुर शहर की जनसंख्या क़रीब 30 लाख तक पहुंच गई हैं. ऐसे में यहां 30 हज़ार सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है, लेकिन यहां केवल 3890 स्थाई और 4800 अस्थाई सफाई मज़दूर हैं. वार्ड क्र. 8 के नगरसेवक मनोज सांगोले ने कहा कि कई बार इस मुद्दे को मनपा सदन में उठाया गया, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकला. उन्होंने कहा कि पूर्व मनपा आयुक्त टी. चंद्रशेखर ने 300 सफाई कर्मचारियों को स्थाई कर अच्छा निर्णय लिया था. बाद में मनपा आयुक्त असीम गुप्ता ने अस्थाई कर्मचारियों को रोज काम देने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी 220 रुपये रोजी को घटाकर 164 रुपये किया गया, जो ग़लत है. मनपा ने वर्ष 2004 से सफाई कर्मचारियों को स्थायी करना बंद कर दिया है. इस स्थिति में अनुकंपा धारकों को 15 से 20 वर्षों तक राह देखनी पड़ रही है. ऐसे में उन्हें क्या लाभ मिलेगा? अस्थायी सफाई कर्मचारियों को छुट्टियां नहीं मिलती. सातों दिन उन्हें काम करना पड़ता है. सांगोले ने बताया कि अन्य विभागों के अकुशल रोजंदारी कर्मचारियों को 275-220 रुपये, अर्धकुशल कर्मचारियों को 309 रुपये और कुशल कर्मचारी (रंगारी, सूतार, वाहन चालक, लिपिक) को 363 रुपये रोजी दी जाती है. उन्हें छुट्टियां भी लागू हैं, लेकिन अस्थाई सफाई कर्मचारी को केवल 164 रुपये रोजी मिलती है.

केंद्रीय मंत्री वासनिक के क्षेत्र में मैला ढोने की प्रथा

जिस केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक ने मार्च 2010 तक पूरे देश से सिर पर मैला ढोने की प्रथा को ख़त्म करने का आश्वासन दिया था, जबकि उन्हीं के संसदीय क्षेत्र रामटेक में सिर पर मैला ढोने की प्रथा बदस्तूर जारी है. यह कोई और नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य श्यौराज जीवन ने कहा है. इस समय उल्हासनगर, कल्याण, ठाणे, नागपुर के भालदारपपरा, कामठी और रामटेक में सफाई मज़दूरों की हालत बेहद ख़राब है.

नेताओं को ठेकेदारों की फ़िक्र: आर्य

नागपुर मनपा में राकांपा के नेता वेदप्रकाश आर्य का कहना है कि सत्ताधारी भाजपा-शिवसेना को जनता से अधिक ठेकेदारों की चिंता है. उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों की ओर से हर वर्ष मिलने वाली मोटी रक़म के कारण जनता के प्रश्नों को महत्व नहीं दिया जा रहा है. कई सफाई कर्मचारी है जो उच्च शिक्षित हैं और उन्हें जल्द प्रमोशन मिलनी चाहिए. साथ ही अस्थाई सफाई कर्मचारियों का प्रश्न हल करने की दिशा में सामूहिक प्रयास की जरूरत है.

feedback@chauthiduniya.com

300 करोड़ का घोटाला

सहकारी बैंकों का गोरखधंधा

अजंता भौमिक

आम आदमी कड़ी मेहनत कर पैसा कमाता है. अपने सपनों व अकस्मात जरूरतों को पूरा करने के लिए एक-एक पैसा जोड़कर बचत करता है. उस बचत को सुरक्षित रखने के लिए वह सहकारी बैंक या पत संस्थाओं में जाता है. उसे लगता है कि घर की अपेक्षा बैंक या पत संस्था में उसकी रक़म सुरक्षित रहेगी, लेकिन इन संस्थाओं के संचालकों द्वारा जो गोरखधंधा चलाया जा रहा है, उससे लोगों की अमानत में ख़यानत का ख़तरा बढ़ गया है. नागपुर में सहकारी बैंक व पत संस्थाओं में 3 सौ करोड़ का गड़बड़झाला होने का मामला उजागर हुआ है. इससे इन बैंकों और पत संस्थाओं के खाताधारकों को अपनी बचत को बचाने की चिंता सताने लगी है. इसके लिए वे बैंकों के चक्कर लगाकर पूछताछ कर रहे हैं.

सहकारी बैंकों में चल रहे इस गड़बड़झाले का तब पता चला जब सहकार पीड़ित गुंतवणूकदार संघर्ष समिति नागपुर के अध्यक्ष व वरिष्ठ समाजसेवक उमेश चौबे ने सूचना के अधिकार के मार्फ़त बैंकों संबंधी जानकारी मांगी. आरटीआई के आधार पर जो सूचना मिली है उसके अनुसार समता सहकारी बैंक, महिला सहकारी बैंक और परमात्मा एक सेवक सहकारी बैंक और 11 पत संस्थाओं की मिली भगत से 2 लाख 50 हज़ार बचत खाताधारकों के 3 सौ करोड़ डूब चुके हैं. उक्त तीनों सहकारी बैंकों में गैर क़ानूनी व नियमों को ताक पर रख कर 154 पत संस्थाओं ने 32 करोड़ रुपये जमा कराये थे, जबकि नियमानुसार उक्त रक़म राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखी जानी चाहिए थी. चूंकि तीनों बैंकों की आर्थिक हालत खस्ता होने पर उनका डूबना तय है, इसलिए सरकारी नियमों के अनुसार केवल 1-1 लाख रुपये ही पत संस्थाओं को लौटाया जाना है. इसका मतलब है कि अधिकांश खाते धारकों की बचत का पैसा डूब चुका है. इस गडबड़झाले की जानकारी होने के बाद भी शासन-प्रशासन द्वारा लोगों की बचत अमानत बचाने के लिए कोई ठोस क़दम नहीं उठाया गया. राज्य का सहकार विभाग मूकदर्शक बनकर तमाशा देखता रहा. बैंकों में व्याप्त आर्थिक कदाचार के संबंध में समाजसेवक उमेश चौबे ने कहा कि आश्चर्य व दु:ख की बात यह है कि राज्य सरकार द्वारा पश्चिम महाराष्ट्र की डुबित सहकारी बैंकों व पत संस्थाओं के खाताधारकों की मदद के लिए बिना ब्याज़ के 200 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने में ज़रा भी देर नहीं लगाई थी. दूसरी ओर विदर्भ के साथ इस मामले में भी सरकार का सौतेलापन जाहिर हो गया, क्योंकि यहां के सहकारी बैंक व पत संस्थाओं के पीड़ित खाताधारकों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया हालांकि इस संबंध में 6 दिसंबर 2010 को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को लिखित निवेदन देकर समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया था, लेकिन अब तक नागपुर ज़िले के सहकारी बैंक व पतसंस्था के पीड़ित खाताधारकों को न्याय नहीं मिला है. इस संबंध में जब परमात्मा एक सेवक सहकारी बैंक के जनरल मैनेजर एम.आर. श्रावणकर से पूछा गया तो उनका कहना था कि हमने लोगों का पैसा वापस करने के लिए 20 अक्टूबर 2011 को डी.आई.सी.जी.सी. से पैसा मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया है. उन्होंने बताया कि खाताधारकों के खाते में चाहे जितना जमा हो पर एक खाताधारक को मात्र एक लाख रुपये ही मिलेंगे. यह पैसा अगले वर्ष 2012 के जनवरी माह तक मिलने की संभावना है. फ़िलहाल हमारे बैंक का कामकाज रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय लिक्विडेटर कमेटी देख रही है. विशेष बात यह है कि इस गड़बड़झाले में शामिल पत संस्थाओं ने कई सालों से अपना ऑडिट नहीं कराया है और जो कुछ संस्थाओं ने ऑडिट तो कराया पर अपनी सुविधा के अनुसार ग़लत रिपोर्ट तैयार कर दिखाया, जिसमें बैंक का पूरा कारभार दुरुस्त दिखाया गया है. बैंक में हुई गड़बड़ियों को उमेश चौबे ने पुलिस प्रशासन के समक्ष भी रखा है. साथ ही प्रशासन से मांग की है कि सभी अनियमित कारोबार करने वाले बैंकों, पत संस्थाओं का ऑडिट कराया जाए. जिन बैंकों या पत संस्थाओं ने गलत ऑडिट रिपोर्ट बनाकर पेश किया है उनका लाइसेंस खारिज़ किया जाए. जिन बैंक संचालकों व अधिकारियों ने खातेधारों की अमानत में डाका डाला है उनकी संपत्ति जब्त कर पीड़ित बैंक खाताधारकों को रक़म लौटाई जाए. सहकार पीड़ित गुंतवणूकदार संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि जहां अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ मुहिम चला रखी है. जनता में भ्रष्टाचारियों के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है. वहीं स्थानीय सहकारी बैंक और पत संस्थाएं आम लोगों की मेहनत की कमाई में गोलमाल करने में तुली हैं. इन संस्थाओं के संचालक भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूब चुके हैं. इन संस्थाओं में लोगों की अमानत में खयानत करने वाले अधिकारियों, संचालकों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी संपत्ति जब्त कर पीड़ितों का पैसा लौटाया जाना चाहिए. यह हमारी मांग है, लेकिन अब तक किसी बैंक संचालक के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई. इसलिए अब भी कई पत संस्थाएं इस गोरखधंधे को चला रखा है और लोगों को लूट रही हैं. नागमित्र सहकारी पत संस्था में घोटाले का पता चलने पर वहां के अधिकारी को हटाया गया था. नागमित्र सहकारी पत संस्था ने इनकम टैक्स के तौर पर 1 लाख रुपये आयकर विभाग को दिए थे, लेकिन जैसे ही बैंक को मालूम पड़ा कि इनकम टैक्स नहीं भरना था तो उसने आयकर विभाग से एक लाख रुपये वापस मांगे. इस पर आयकर विभाग 1 लाख रुपये वापस करने को तैयार हो गया, पर जब नागमित्र सह. पतसंस्था के अधिकारियों से बैक एकाउंट नंबर मांगा तो उनके हाथ-पांव फूल गए. यहां पर पतसंस्था संचालक ने अपना बैक एकांउट नबंर देने के बजाय अपनी संस्था के ही एक आधिकरी का एकांउट नंबर दे दिया. इस वाकये के बाद संस्था की ऑडिट रिपोर्ट को देखने पर पतसंस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है. इसलिए समाजसेवक चौबे ग़लत ऑडिट रिपोर्ट बनाने वाले ऑडिटरों की मान्यता रद्द करने की मांग भी शासन से की है.

उमेश चौबे, समाज सेवक

feedback@chauthiduniya.com

डुबित तीन सहकारी बैंकों में लोगों की बचत जमा करने वाली संस्थाएं और लाखों में उनकी जमा रक़म

1.	एवरेस्ट सह. पंतसंस्था	13.41
2	बुलढाना अर्बन क्रेडिट	295.78
3.	दीनबंधु अर्बन	24.17
4.	परशुराम अर्बन	81.67
5.	नवीन सुभेदार	224.49
6.	आंनद साई	19.07
7.	धरमपेट माहिला	408.34
8.	निर्मल उज्ज्वल क्रेडिट	295.78
9.	गोपाल कृष्ण	86.21
10.	नागमित्र सह. पंतसंस्था	86.02
11.	पी.एम.जी. ऑफिस स्टॉफ	41.03
12.	उज्ज्वल क्रेडिट	76.70
13.	हिमालय सहकारी	35.43
14.	विघ्नहर्ता सह. पतसंस्था	13.36
15.	पंजाब नागरी	42.47
16.	शुभम नागरी	161.63
17.	मधुबन अर्बन	44.70
18.	ज्योति नागरी	97.40
19.	सम्राट अशोक	23.06
20.	सेन्ट्रल अर्बन क्रेडिट	125.32
21.	नंदनवन नागरिक	11.82
22.	श्रीकृष्ण नागरी	27.63
23.	युनाइटेड अर्बन	38.93
24.	प्रगतिशील सह	50.60
25.	अनंत क्रेडिट	30.58
26.	जनता नागरी	36.01
27.	नवप्रभात अर्बन	11.15
28.	संचिता अर्बन	83.75
29.	मां अंबे	27.28
30.	विशाल नागरी	17.36
31.	महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट एम्पा.	116.09
32.	हनुमान क्रेडिट	30.00
33.	ज्ञानेश्वर नागरी	8.49
34.	हरिओम ग्रामीण बिगर शेती	28.74
35.	नारायण गुरू	14.88
36.	तुमसर नागरी	21.38
37.	जनकल्याण तुमसर	35.97
38.	चक्रधर स्वामी	13.46
39.	श्री गजानन सह. बहु. संस्था	13.41
40.	नरकेसरी सह. गृहनिर्माण संस्था	12.14
41.	एयरपोर्ट अथॉ. एम्पा. को-ऑप. संस्था	12.73
42.	मेट्रोलॉजिकल को-आ. क्रे. संस्था	13.19
43.	विदर्भ प्रीमियर को-ऑप. हाऊ. सो.	11.50
44.	लोकमान्य गृह निर्माण	8.88
45.	वर्षा अर्बन क्रे.	6.84
46.	नरहरी अर्बन क्रे. क्रो.	16.37
47	कलमना अर्बन क्रं.	7.76

ये क्या हो रहा है...

मंत्री और सचिव के बीच लड़ाई

राजकाज में मंत्री बड़ा होता है या सचिव? सवाल कुछ अटपटा ज़रूर है पर महत्वपूर्ण है. जब कोई सचिव ही अपने को सुपर पावर मानने लगे तो मंत्री का दिल दुखना लाज़िमी है. यह अलग बात है कि मंत्रियों की शिकायतों के बाद भी राज्य के मुखिया यानी मुख्यमंत्री इस बात से बेख़बर हैं कि राजकाज में क्या चल रहा है? मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड़ के पावर ऑन से सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजी राव मोघे और रोज़गार गारंटी और सामाजिक वनीकरण मंत्री नितिन राऊत दुखी हैं. शिवाजी राव मोघे तो इतने दुखी हुए कि उन्होंने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से लिखित शिकायत की है, लेकिन लगता है कि अब तक मुख्यमंत्री ने उसे देखी नहीं है या अनदेखी कर रखी है. मोघे साहब को शिकायत है कि मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड़ उनके मंत्रालय से संबंधित आर्थिक व प्रशासकीय निर्णय उनको विश्वास में न लेते हुए स्वयं ले रहे हैं. दरअसल मोघे के गुस्से का कारण पुणे में बनने वाले शासकीय पिछड़ावर्गीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था और छात्रावास के लिए बड़े प्रयासों के बाद ज़मीन का जुगाड़ होने पर उनके मंत्रालय ने उसे मंज़ूरी दी थी, लेकिन मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड़ ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्रस्ताव को रद्द कर दिया. उनके इस निर्णय पर सामाजिक न्याय मंत्री मोघे का नाराज़ होना स्वाभाविक है. मोघे ने आरोप भी लगाया है कि उसी जगह पर आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था की इमारत खड़ी करने की हलचल शुरू है. इस संस्था की मंज़ूरी भी सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दी गई थी. इसके बावजूद इस सामाजिक न्याय मंत्रालय को न सूचित करते हुए डॉ. बाबासाहब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था के नियामक मंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड़ और एक सनद अधिकारी डॉ. संजय चहांदे को आजीवन सदस्य बना दिया है. इस पर मोघे ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से सवाल किया है कि दोनों अधिकारी डॉ. बाबासाहब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था के आजीवन सदस्य कैसे हो सकते हैं? दूसरी ओर रोज़गार गारंटी योजना और सामाजिक वनीकरण मंत्री नितिन राऊत मुख्य सचिव गायकवाड़ से इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि उनके रोज़गार गारंटी योजना के तहत होने वाले कार्य के लिए अब तक मिले 950 करोड़ और राज्य में 100 करोड़ वृक्ष लगाने की योजना का श्रेय मुख्य सचिव ले रहे हैं, लेकिन इन दोनों मंत्रियों की नाराज़गी पर मुख्य सचिव का बोल वचन है कि जो भी निर्णय प्रशासनिक स्तर पर उन्होंने लिया है, वे सभी नियम-क़ायदों के तहत योग्य प्रक्रिया के अनुसार ही लिया है. अब सवाल उठता है कि जब दोनों अपने को सही बता रहे है तो गड़बड़ कहां है? इस मामले से तो यही उजागर होता है कि शीर्षस्तर पर शासन-प्रशासन में कोई समन्वय नहीं है. मुख्यमंत्री महोदय आपके शासनकाल में यह हो क्या रहा है? मंत्रियों को मुख्य सचिव के निर्णय से परेशानी हो रही है तो इसका मतलब होता है कि उनके अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही है. यह तो जगज़ाहिर है कि मंत्री-अफसर मिलकर नोट छापते हैं, लेकिन यहां एक अफसर मंत्री के निर्णय को पलट रहा है और मंत्री महोदय तिलमिला रहे हैं. संस्थाओं की इमारत का निर्माण कार्य हो या उसको शुरू करने का मामला हो, उसमें गड़बड़ी होती ही है. इसी तरह वनीकरण का मामला है जिसमें लाखों पेड़ों का वृक्षारोपण हर साल एक ही जगह पर होता है पर वहां हरियाली नज़र नहीं आती है. चूंकि आप का राज राज्य में है. मंत्रिमंडल भी आपका है. मुख्य सचिव आपके मातहत कार्य करते हैं. अब मुख्यमंत्री जी आपको ही यह पता लगाना होगा कि मंत्री सही है या मुख्य सचिव. राज्य की जनता में मंत्रियों-संतरियों की जो छवि है उसके मद्देनजर आपको शीघ्रातिशीघ्र सच्चाई पर से पर्दा उठाना चाहिए. वरना आपकी सरकार की छवि स्वार्थ की इस लड़ाई से और धूमिल हो जाएगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र हलचल

कपास क़ीमत बढ़ाने की मांग को लेकर अनशनरत बड़नेरा के विधायक रवि राणा को राज्यमंत्री राजेन्द्र मुलक जूस पिलाकर अनशन ख़त्म कराते हुए. इस मौके पर अमरावती ज़िले के पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल भी मौजूद रहे.

रामगोपाल माहेश्वरी सांस्कृतिक सभागृह नागपुर में आयोजित समारोह में दामोदर खड़से व घनश्यामदास मूंदड़ा को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करते हुए केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक.

फेसबुक में राय नामक व्यक्ति द्वारा प्रसिद्ध मंदिर का विवादित फोटो जारी किए जाने पर आक्रोशित जिला वाशिम के कारंजालाड वासी.

कपास व सोयाबीन जलाते हुए स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रवि तुपकर व संगठन के कार्यकर्ता लखन माडेकर, राणा चंद्रशेखर, हरिभाऊ उबरहडे, जगदीश भोवल, विजय, सागर, राजू, बाजीराव उबरहडे व अन्य.

शिवसेना नेता एड. प्रभाकर देसाई द्वारा अपने समर्थकों के साथ राकांपा में शामिल होने के मौके पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते गृहमंत्री आर.आर. पाटिल. इस अवसर पर मंचासीन पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड़, राज्यमंत्री भास्कर जाधव, मुंबई कांग्रेसाध्यक्ष नरेन्द्र वर्मा और विधायक दीपक केसरकर.

उद्योग मंत्री नारायण राणे देवभाग गांव दौरे के दौरान कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ गांव के नदी तट का अवलोकन करते हुए.

नागपुर दौरे के दरम्यान केंद्रीय युवा कल्याण व खेल मंत्री अजय माकन कोराड़ी रोड स्थित क्रीडा संकुल का ज़िले के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए.

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 05 दिसंबर–11 दिसंबर 2011

राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने 13 नवंबर को यवतमाल में घोषणा करते हुए कहा कि वे कपास का उचित दाम किसानों को दिला कर रहेंगे.

उप राजधानी में शीतकालीन सत्र के निहितार्थ

युधिष्ठिर जोशी

महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर और मुख्य राजधानी मुंबई है. विदर्भ के गौरव को बनाए रखने के लिए विधानमंडल का एक शीतकालीन सत्र नागपुर में लिया जाता है. बाकी दो अधिवेशन मुंबई में होते हैं. इस वर्ष का शीतकालीन सत्र 12 दिसंबर से नागपुर में शुरू होगा. द्विभाषिक (मराठी और गुजराती) मुंबई राज्य का बंटवारा कर महाराष्ट्र (मराठी भाषिक) और गुजरात राज्य (गुजराती भाषिक) ऐसे दो राज्यों का निर्माण वर्ष 1960 में किया गया. तभी से विधानमंडल का एक शीतकालीन सत्र नागपुर में शुरू करने की प्रथा आरंभ हुई. इससे पहले सी.पी. एंड बेरार राज्य था. इसे मध्यप्रांत भी कहा जाता था. इस राज्य की राजधानी नागपुर में थी. 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्रता मिलने के पहले भी मध्यप्रांत अस्तित्व में था और इसकी राजधानी नागपुर थी. यानी देखा जाए तो कई वर्ष पहले नागपुर शहर राजधानी हुआ करता था. राजधानी में मुख्यमंत्री, मंत्रियों का निवास स्थान, राज्य का सचिवालय और हाईकोर्ट आदि होते हैं, जो नागपुर में है.

सी.पी. एंड. बेरार राज्य में हिंदी और मराठी भाषिक दोनों बड़ी संख्या में थे. वहीं मुंबई राज्य में गुजराती, तेलगू और मराठी भाषिकों की संख्या अच्छी खासी थी. स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही भाषिक राज्यों की मांग ने जोर पकड़ लिया था. मराठी भाषिकों का अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हर वर्ष होता आ रहा है. इस सम्मलेन में मराठी भाषा बोलने वालों का एक राज्य होना चाहिए इसका प्रस्ताव पहली बार बेलगांव के अधिवेशन में लाया गया. प्रस्ताव उस समय सम्मेलन के अध्यक्ष रहे नागपुर से प्रकाशित होने वाले तरुण भारत (मराठी) अख़बार के संस्थापक संपादक गजानन त्र्यंबक माडखोलकर ने लाया था. पहले से ही शुरू हिंदी–मराठी भाषिकों में विवाद को इस प्रस्ताव से काफ़ी हवा मिली. इससे राजनीतिक आंदोलन को भी बढ़ावा मिला. इसके बाद ही मध्यप्रांत में रहने वाले मराठी भाषिकों ने स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग को आगे बढ़ाना शुरू किया. पुराने मध्यप्रांत में 8 ज़िले शामिल थे. इनमें भंडारा, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, यवतमाल और बुलढाना का समावेश था. जहां मराठी भाषा बोलने वालों की संख्या काफ़ी अधिक थी. इस मांग को लोकनायक बापूजी अणे, ब्रिजलाल बियाणी आदि का समर्थन भी हासिल था. वहीं दूसरी ओर विदर्भ सहित मराठी भाषियों का एक अलग राज्य हो, इसकी मांग भी होने लगी थी. इसमें नागपुर का राजधानी का महत्व बना रहे. यह भी मांग हो रही थी.

इस तरह के कई मुद्दों पर सहमति बने इसके लिए विदर्भ और अन्य मराठी भाषिक नेताओं में अकोला क़रार हुआ. इस क़रार में एक मुद्दे पर सहमति बनी कि नागपुर शहर के वैभव व सम्मान को क़ायम रखने के लिए नए सिरे से गठित होने वाले महाराष्ट्र राज्य में उसे उप राजधानी का दर्जा दिया जाएगा. स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग को आगे बढ़ाने के लिए एक और कारण यहां के नेताओं के पास था. भारत सरकार ने भाषावार राज्य रचना के लिए फ़ाज़ल अली आयोग गठित किया था. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्वतंत्र विदर्भ राज्य के गठन होने की बात कही है, लेकिन आगे अकोला क़रार होने से स्वतंत्र विदर्भ राज्य का निर्माण नहीं हो सका और मराठी भाषिकों के एक राज्य महाराष्ट्र का निर्माण किया गया.

विदर्भ के गौरव को बचाए रखने के लिए वर्ष 1960 से विधानमंडल का एक शीतकालीन सत्र नागपुर में आयोजित हो रहा है. वर्ष 1980 तक विदर्भ वीर जाम्बुवंतराव धोटे और उनके सहयोगी स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग के लिए काफ़ी सक्रिय थे. तब तक इस मांग के समर्थन में कई आंदोलन हुए और मोर्चे निकाले गए. अब वह पीढ़ी थक गई है. कुछ तो इस दुनिया में नहीं रहे. इसके कारण स्वतंत्र विदर्भ राज्य के लिए शुरू हुआ आंदोलन अब शिथिल हो गया है. विदर्भ ने भी विधानमंडल के केवल एक शीतकालीन सत्र की मांग क्यों करनी चाहिए? या फिर महाराष्ट्र सरकार ने भी विधानमंडल के अधिवेशन की औपचारिकता क्यों करनी चाहिए? ये सवाल अब खड़ा हो गया है. केवल आठ–दस दिन के लिए राजधानी का काम मुंबई से नागपुर लाया जाता है. इसके लिए करोड़ों रुपये ख़र्च होते हैं. आख़िर क्यों? इससे आख़िर हासिल क्या होता है? आख़िर यह पैसा जनता की ही जेबों से आता है. ऐसे में सरकारी खजाने को इस तरह उड़ाना कहां तक सही है? इस बारे में विदर्भ सहित सभी को सोचने की ज़रूरत है. वर्ष 1978 तक महाराष्ट्र विधानमंडल का नागपुर में होने वाला शीतसत्र कम से कम छह से आठ सप्ताह का होता था, लेकिन इसके बाद शीतसत्र के दिनों में कमी होती गई. अब शीतसत्र तो केवल दो या तीन सप्ताह तक ही सीमित रह गया है. तीन सप्ताह यानी प्रत्यक्ष रूप से केवल 15 दिन ही काम होता है. इन तीन सप्ताह के लिए सत्र के क़रीब दो–तीन सप्ताह पूर्व ही मुंबई से नागपुर में ट्रक भर–भर कर फाइलों के गठ्ठे लाए जाते हैं. विधानमंडल के सत्र के लिए मंत्रालय का कर्मचारी वर्ग बड़ी संख्या में नागपुर आता है. ऑफिस में कार्यवाही शुरू होने के पूर्व तीन–चार दिन घूमने और आने–जाने में ही ख़र्च हो जाते हैं. विधानमंडल चलता है 15 दिन और उसकी तैयारी के लिए पहले 15 दिन लग जाते हैं. सुरक्षा के लिए पूरे राज्य से पुलिस अधिकारी और कर्मियों को नागपुर लाया जाता है. उनके रहने–खाने की व्यवस्था. सैकड़ों गाड़ियां और उसमें लगने वाला पेट्रोल, डीजल, यानी सरकारी खजाने को बग़ैर किसी काम के ख़र्च किया जाता है. देखा जाए तो विदर्भ वासियों को इससे कुछ नहीं मिलता. केवल सरकारी इमारतें, मुख्यमंत्री, मंत्रियों के निवास स्थान, विधायक निवास, सरकारी विश्रामगृह आदि का रंगरोगन और कुछ रास्तों का निर्माण शीतसत्र के बहाने हो जाता है. सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं की पार्टियां होती हैं. उनसे मिलकर कुछ लोग अपने काम निकाल लेते हैं. इससे कुछ लोगों को रोज़गार ज़रूर मिलता है, लेकिन आम आदमी के हाथों में कुछ नहीं आता. राज्य विधानमंडल के अधिवेशन में केवल विदर्भ की समस्याओं को ही प्राथमिकता दी जाए, यह मांग भी ग़लत है. केवल विदर्भ की प्रतिष्ठा का प्रश्न समझकर करोड़ों रुपये ख़र्च करना, यह भी ग़लत है. शहर में लाल–पीली बत्तियों की गाड़ियों का जमघट, रास्ते–रास्ते पर पुलिस बंदोबस्त इन ग़लत विचारों का सरकार और विदर्भवासियों को समर्थन नहीं करना चाहिए. इसकी बजाय मंत्रिमंडल की लगातार 8 दिन बैठक यहां होनी चाहिए. इन 8 दिनों में विदर्भ की समस्याओं पर चर्चा कर उन्हें सुलझाने की दिशा में कोशिशें होनी चाहिए. इससे न सिर्फ़ विदर्भ के विकास को गति मिलेगी, बल्कि बाकी चीज़ों पर होने वाला करोड़ों रुपये का ख़र्च भी बचेगा.

विदर्भ के नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजधानी की बजाय विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए. साथ ही पार्टियों के बीच होने वाले मतभेदों को भूलकर नेताओं को विदर्भ की समस्याओं पर अध्ययन कर विचार रखने और एकजुट होने की ज़रूरत है. तभी विदर्भ का करोड़ों का बैकलॉग दूर होगा. पुणे, कोल्हापुर, नासिक, जलगांव आदि शहरों में विधान मंडल के अधिवेशन नहीं होते, लेकिन फिर भी उन शहरों और क्षेत्र का विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा. वहां की उद्यमशीलता, दूरदृष्टि और भव्य सपनों को साकार करने की कोशिशों ने उन क्षेत्रों के विकास को गति दी. मंत्री, विधायक, बड़े–बड़े सरकारी अधिकारियों की बैग पकड़ने और उनके आगे–पीछे घूमने से किसी का भला नहीं हो सकता है.

महाराष्ट्र के निर्माण के बाद विदर्भवासियों के मन का गुस्सा, हलचल इतने वर्षों बाद काफ़ी कम हुई होगी. इतने वर्षों तक उप राजधानी का दर्जा लेकर आख़िर क्या मिला? इसका मंथन करने की ज़रूरत आज है. अपने क्षेत्र के विकास की गुरुकिल्ली राजधानी बनाने की मांग से पूरी नहीं होगी यह समझने की ज़रूरत है.

एक तो विदर्भवासियों ने स्वतंत्र राज्य की मांग कर स्वयं राज्य का कामकाज संभालना चाहिए. इसके लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करने चाहिए या फिर स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग को छोड़कर विकास के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

किसान आंदोलन का राजनीतिकरण अनुचित

राजेश नामदेव

जब तक गन्ना उत्पादकों की समस्या को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष सांसद राजू शेट्टी ने आंदोलन नहीं किया था, तब तक किसानों के हित में संघर्ष करने के लिए कोई सड़क पर नहीं उतरा था. सिर्फ उनके भाषणों में ही किसानों की दुर्दशा पर चिंता झलकती थी, लेकिन गन्ना उत्पाद को उचित दाम दिलाने के लिए राजू शेट्टी के नेतृत्व में जो सफल आंदोलन हुआ और गन्ने की क़ीमत में वृद्धि करने के लिए तत्परता से सरकार आगे आयी और नए मूल्यों की घोषणा की. उसके बाद अचानक सभी नेताओं की नींद टूटी. उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अपनी सियासी छवि चमकाने का अच्छा अवसर यही है. ख़ासकर विदर्भ के नेताओं को अब कपास, धान और सोयाबीन के उचित दाम दिलाने की सूझी है, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन किया जा रहा है उससे राज्य की जनता को यह महसूस हो रहा है कि किसानों को हक़ दिलाने के नाम पर राजनीति अधिक हो रही है और किसानों की बदहाली दूर करने पर बात कम हो रही है. कपास, धान व सोयाबीन उत्पादकों को घटिया बीज के कारण जो नुक़सान उठाना पड़ा उसकी परवाह किसी को नहीं है. बस, उक्त उत्पादों की अधिक से अधिक क़ीमत दिलाने की मांग हर नेता कर रहा है ताकि वह किसी से पीछे न रह जाए.

दरअसल किसी को यह अपेक्षा नहीं थी कि बारामती में सांसद शेट्टी के आंदोलन करने की रणनीति को इतनी अधिक सफलता मिलेगी. इसलिए किसी नेता ने किसानों के हक़ के लिए आंदोलन छेड़ने का मन नहीं बनाया था. लेकिन बारामती में राजू शेट्टी ने अनशन तोड़ने के साथ ही आगे कपास, धान और सोयाबीन उत्पादकों के हक़ के लिए संघर्ष करने का ऐलान किया, उसके दूसरे दिन ही कपास को लेकर पूरे विदर्भ में आंदोलन भड़क उठा. सत्ता पर बैठे नेताओं से लेकर तहसील तक के नेताओं को कपास उत्पादकों को न्याय दिलाने की चिंता सताने लगी है. कोई दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलकर न्याय दिलाने की मांग कर रहा है. कुछ सड़कों पर उतर कर सरकार से मांग करने लगे हैं तो कुछ नागपुर में होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में आंदोलन करने की बात कर रहे हैं. ख़ास बात जो सामने आ रही है वह यह है कि सभी कपास की अलग–अलग क़ीमत दिलाने की बात कर रहे है. जो चित्र सामने आया है उसके अनुसार विविध संगठन व नेता कपास को 5000 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक दाम दिए जाने की मांग करने लगे.

राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने 13 नवंबर को यवतमाल में घोषणा करते हुए कहा कि वे कपास का उचित दाम किसानों को दिला कर रहेंगे. उन्होंने कपास के निर्यात पर पाबंदी को हटवाने के लिए राकांपा नेताओं के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलकर इस समस्या को सुलझाने की बात कही. धान व सोयाबीन उत्पादकों की स्थिति पर भी चिंता ज़ाहिर की. इसके बाद कांग्रेस के नेता भी अचानक किसानों की दुर्दशा पर दुबले होने लगे. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे के नेतृत्व में एक पार्टी नेताओं का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से मुलाकात की और उनसे कपास की क़ीमत 6000 रुपये करने की मांग की. मुख्यमंत्री ने उनकी कपास की क़ीमत 6000 रुपये करने की मांग को तत्काल ठुकरा दिया. उन्होंने इस विषय में दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलकर चर्चा करने का आश्वासन दिया. वहीं विविध किसान संगठनों ने विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश में कपास के दाम बढ़ाने को लेकर सड़कों पर उतर आए. सड़कों पर धरना दिया जिससे यातायात जाम हो गया. अमरावती ज़िले के तिवसा में निर्दलीय विधायक रवि राणा ने चक्का जाम कर दिया था जिससे वाहनों का आवागमन पूरी तरह रुक गया था. रवि राणा को उनके समर्थकों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार भी किया. अब हालात यह है कि उनसे जेल में जारी अनशन को तुड़वाने के लिए अस्प–ताल तक दौड़ लगाई गई, लेकिन विधायक राणा ने तब तक अनशन तोड़ने से इंकार कर दिया जब तक सरकार कपास का उचित दाम नहीं घोषित करती है. वहीं नागपुर में 15 नवंबर को ज़िला परिषद के सरपंच भवन में किसान जागृति अभियान के तहत विदर्भ के कपास, धान उत्पादक किसानों की एक बैठक का आयोजन किया गया. बैठक को पूर्व मंत्री रणजीत देशमुख, विधायक आशीष जैस्वाल, विदर्भ जनांदोलन समिति के संयोजक किशोर तिवारी, पूर्व विधायक देवराव भांडेकर व अन्य कई नेताओं ने संबोधित किया. बैठक में रणजीत देशमुख ने कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों का आंदोलन शुरू होते ही राज्य सरकार मूल्यवृद्धि की घोषणा करती है, लेकिन उसी तर्ज पर कपास उत्पादकों के साथ न्याय नहीं किया जाता है. उन्होंने कपास को 7500 रुपये, धान को 2500 रुपये और सोयाबीन को 3600 रुपये दाम दिए जाने की मांग की. भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पहले से ही किसान के आंदोलन का समर्थन कर रही है और उनके कार्यकर्ता, नेता भी सड़कों पर उतर रहे हैं.

इस दरम्यान जिस तरह से कपास, धान व सोयाबीन के दाम बढ़ाने को लेकर नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं उससे यही प्रतीत होता है कि इस मुद्दे को लेकर आंदोलन पूरी तरह विभाजित नज़र आ रहा है. कपास, धान, सोयाबीन को लेकर राजनीति अधिक हो रही है. इसका साफ अर्थ यह है कि गन्ना के लिए हुए आंदोलन की सफलता से सभी को लगने लगा कि कहीं किसानों के हक़ की लड़ाई लड़ने का पूरा श्रेय राजू शेट्टी न ले जाएं. हम कहीं पीछे न रह जाएं. इसलिए तो सभी नेता अचानक कपास उत्पादकों को न्याय दिलाने के लिए अपने–अपने आंदोलन के कार्यक्रमों की घोषणा करने लगे हैं. दूसरी ओर राज्य सरकार की सोच थी कि वह नागपुर में होने वाले विधानमंडल के शीतसत्र में नए दामों की घोषणा कर वाहवाही लूटेगी, लेकिन उसके पहले ही राजू शेट्टी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के गढ़ जाकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया जिससे सरकार का गणित गड़बड़ा गया. किसानों की दुर्दशा से चिंतित सभी नेताओं से जनता यही अपेक्षा करती है कि किसान आंदोलन के नाम पर राजनीतिक रोटी न सेंकी जाए, बल्कि ऐसे उपाय या नीति बनाने के लिए सरकार पर दबाव डालें जिससे उनकी समस्या का जड़ से समाधान हो. उनके उत्पादों की लागत निकलने के साथ ही उनको इतनी आय हो जाए कि वे अपने परिवार का भरण–पोषण करने के साथ ही खेती की उन्नत तकनीक को आसानी से अपना सके. राजनीति होने पर किसानों को तात्कालिक फ़ायदा मिल सकता है पर उसका भविष्य में उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा. इसलिए राजनीति के लिए आंदोलन न हो, बल्कि किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, उनको वर्तमान के साथ ही भविष्य में भी राहत मिले और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, इस दूरदृष्टि से समन्वयकारी आंदोलन हो. तभी उसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे.

feedback@chauthiduniya.com

क़ीमत तय करने से पहले सर्वे ज़रूरी

सरकार कपास, धान, सोयाबीन या अन्य किसी कृषि उत्पाद का समर्थन मूल्य निर्धारित करने से पहले यह सर्वे क्यों नहीं कराती है कि बीज, खाद व अन्य कृषि उपयोगी वस्तुओं के दाम में कितनी वृद्धि हुई. किस कृषि उत्पाद के लिए किसानों को कितना खर्च करना पड़ा. उसको बिक्री केंद्रो या बाज़ार तक ले जाने में कितना व्यय आया. इन बातों का यदि सरकार सर्वे कराती है और उसके बाद जो कृषि उत्पादों की लागत होती है उस पर 10-20 प्रतिशत लाभांश निर्धारित कर समर्थन मूल्य निर्धारित करती है तो किसानों को उचित दाम दिलाया जा सकता है. इससे किसानों को हर साल आंदोलन नहीं करना पड़ेगा. इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि कृषि बीमा की ख़ामियों को दूर कर उसे अधिक सकारात्मक बनाया जाए ताकि प्राकृतिक आपदा में फसल तबाह होने के बाद उन्हें कम से कम इतनी मदद मिल जाए जितना उसका नुक़सान हुआ है. वर्तमान में जो कृषि बीमा योजनाएं है वे बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिहाज़ से बनाई गई हैं न कि किसानों के हितों के लिए.

Postal Regn. No.RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 05 दिसंबर-11 दिसंबर 2011

बिग बॉस में पॉर्न स्टार लाकर भी यह शो लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित तो नहीं कर पाया, लेकिन बॉलीवुड के निर्माता-निर्देशक और कलाकार उनकी तरफ़ तेज़ी से आकर्षित हुए.

ट्विंकल ने जलवे बिखेरे

सुपर स्टार की पत्नी होना कोई मामूली बात नहीं है. बात चाहे शाहरुख़ ख़ान की पत्नी गौरी ख़ान की हो या अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना की. वैसे गौरी ख़ान तो अपने पति की कामयाबी के साथ ग्लैमर का तड़का लगाने में कभी पीछे नहीं रहतीं, लेकिन अब ट्विंकल खन्ना ने भी ग्लैम फेसेस में अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है. मैगजीन कवर फेस बनाना बॉलीवुड का और ग्लैम वर्ल्ड का हॉट ट्रेंड बन गया है और ग्लैमर्स तड़का देने के विचार से ट्विंकल ने इसी ट्रेंड का इस्तेमाल किया है. अपनी बेहतरीन शेप्ड बॉडी और शाइनी एटीट्यूट को उन्होंने लोगों के बीच एक बार फिर से चर्चा का विषय बनाया है. दरअसल, ट्विंकल भी उन अभिनेत्रियों की कतार में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने एक मैगजीन कवर पर अपने जलवे बिखेर कर लोगों के बीच खलबली मचा दी है. ट्विंकल खन्ना देश की मोस्ट गॉर्जियस फेस और बेस्ट ड्रेस्ड वुमेन हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब तक इसे ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया गया था. लेकिन अब मशहूर मैगजीन वर्व ने इस बात को ऑथेंटिक बना दिया है. ट्विंकल खन्ना वर्व मैगजीन की तरफ़ से बेस्ट ड्रेस्ड वुमेन का टैग जीत चुकी हैं और इसी वजह से उन्हें मैगजीन के कवर पेज पर जगह दी गई है. कवर पेज पर उनके हुस्न का जादू बिखेरने के लिए मदद ली गई है फोटोग्राफर डब्बू रतनानी की और उन्हें स्टाइलिश बनाया है निशा जंगियानी ने. इस फोटो में उन्होंने पहना है तदाशी शोजी का वन शोल्डर ड्रेस, जिस पर सिल्वर सिक्यवेंस लगे हैं. इस ड्रेस को एक्सेसराइज किया गया है रोज गोल्ड फिनिश मेटल कफ और बड़े हुप इयरिंग्स के साथ. इसमें उन्होंने कोई ख़ास फैशन ट्रेंड को फॉलो नहीं किया है, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से ड्रेस पहनी है.

अनुष्का सही फ़ैसलों से सफल

बॉलीवुड में नई-नई एंट्री करने वाली कुछ ही ऐक्ट्रेसेस हैं, जो बॉलीवुड में अपने सही फ़ैसलों की वजह से अपनी पहचान बना पाई हैं. कुछ ख़ास ही फिल्मों में करने वाली अनुष्का शर्मा ने अपनी कामयाबी की दास्तां ख़ुद ही लिखी है. अभी हाल में अनुष्का शर्मा को बॉलीवुड सर्कल में अपने जीरो साइज़ फिगर के लिए जाना जा रहा था. लेकिन इसके साथ ही वह मशहूर हो रही हैं अपनी आने वाली फिल्म लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल के लिए भी. हॉट दिखने वाली अनुष्का जल्द ही कॉमेडी गर्ल बनने जा रही हैं. जी हां, वह विशाल भारद्वाज की अगली फिल्म मतरू की बिजली का मन डोला, में कॉमेडी करती हुई दिखाई देंगी. इस नए रोल के लिए अनुष्का बेहद एक्साइटेड हैं. उनका कहना है कि यह रोल मेरी सारी फिल्मों से अलग है, मुझे इस बात की ख़ुशी है कि निर्देशक ने इस फिल्म के लिए मुझे चुना. मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी है और पढ़ते समय हंस-हंस कर पेट में दर्द होने लगा. मुझे यक़ीन है कि दर्शक मेरे इस किरदार को भी काफ़ी पसंद करेंगे. इस फिल्म में अनुष्का के साथ इमरान ख़ान हैं. वैसे दर्शकों को उनकी ज़्यादातर फिल्में पसंद आई हैं. अब तक हर रोल में चाहे वह एक आदर्श पत्नी का रोल हो या एक एस्पायरिंग करियर ओरिएंटेड वुमेन का, चाहे वह एक बदमाश गर्ल का हो या मोटिवेट करने वाली गर्ल फ्रेंड का, सभी रोल्स में वह फिट बैठी हैं और लोगों को अपनी अभिनय प्रतिभा का क़ायल बनाया है. देखते हैं कि अब उनके कॉमेडी रोल को लोग पसंद करेंगे या नहीं.

फिल्म प्रीव्यू

लेडीज वर्सेस रिकी बहल

साल 2010 की सफलतम फिल्म बैंड बाजा बारात की टीम फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल के साथ एक बार फिर धमाका करने के लिए तैयार है. मनीष शर्मा निर्देशित और अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह अभिनीत इस फिल्म का लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है. फिल्म बैंड बाजा बारात और अब लेडीज वर्सेस रिकी बहल में रोमांस करने वाली यह जोड़ी वास्तविकता में भी अपने रिश्ते के कारण ख़बरों में रहता है. हालांकि रणवीर और अनुष्का अपने रिश्ते को सिर्फ़ दोस्ती बताते हैं. पहली फिल्म में दोनों की जोड़ी को सराहा गया था. शाहरुख़ ख़ान के साथ यशराज की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से बॉलीवुड में क़दम रखने वाली अनुष्का इस फिल्म में नए अवतार में नज़र आएंगी. फिल्म में अनुष्का का बिकनी अवतार नज़र आएगा, जिसकी गवाह बनेगी गोवा की ख़ूबसूरत लोकेशन. अपनी पहली ही फिल्म बैंड बाजा बारात से लोकप्रिय हुए अभिनेता रणवीर सिंह की यह दूसरी फिल्म है. फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल में रणवीर सिंह कई रूपों में नज़र आएंगे. दरअसल, फिल्म में रणवीर ने एक कॉन-मैन का किरदार निभाया है, जो अलग-अलग जगहों की लड़कियों के साथ धोखेबाज़ी करता है. महज़ चार फिल्मों से ही अनुष्का बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं. अभिनय और नृत्य कौशल के कारण अनुष्का बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्री होने की क़ाबिलियत रखती हैं. अपनी इस नई फिल्म में अनुष्का एक दिलचस्प भूमिका निभा रही हैं, जिसमें वह धोखेबाज़ी करने में भी बाज़ नहीं आती हैं. लेडीज वर्सेस रिकी बहल में रणवीर ने रिकी बहल का किरदार निभाया है, जो हमेशा ही लड़कियों को धोखा देता रहता है. आख़िरकार उसे भी एक धोखेबाज़ मिल ही जाती है, जो अनुष्का शर्मा हैं. फिल्म में जहां अनुष्का का बिकनी अवतार नज़र आएगा, वहीं रणवीर सात अवतारों में नज़र आएंगे. मनीष शर्मा के निर्देशन में बनी लेडीज वर्सेस रिकी बहल एक कॉमेडी फिल्म है, जो दर्शकों को गुदगुदाएगी. फिल्म का निर्माण आदित्य चोपड़ा के बैनर तले हुआ है. फिल्म में रणवीर, अनुष्का के अलावा परिणीती चोपड़ा और दिपन्निता शर्मा ने भी अभिनय किया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

शर्लिन नए रोल में

काफ़ी वक़्त से शर्लिन चोपड़ा की कोई खोज ख़बर नहीं मिल पा रही थी. दरअसल, वह अपने फैंस के सामने सरप्राइजिंग गुड न्यूज़ के साथ आना चाहती थीं. उनके चाहने वालों के लिए ख़ुशख़बरी है कि जल्द ही शर्लिन लोगों के बीच नज़र आएंगी. बॉलीवुड में सैक्स सिंबल के रूप में अपनी पहचान बना चुकी आइटम गर्ल शर्लिन चोपड़ा अब प्रॉस्टिट्यूट बनेंगी. अरे रियल लाइफ में नहीं रील लाइफ में शर्लिन को उनके एक्पोज के चलते फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर मिल ही गया. काफ़ी दिन से शर्लिन ख़बरों से ग़ायब रहीं, लेकिन एक बार फिर वह सुर्ख़ियों में आ चुकी हैं. वह हमेशा ही ख़बरों में बने रहने के लिए एक नई कंट्रोवर्सी पैदा करती रहती हैं. लेकिन इस बार वह अपनी आने वाली नई फिल्म को लेकर ख़बरों में आ गई हैं. शर्लिन को स्वप्ना जोशी वाघमारे ने अपनी फिल्म के लिए चुना है, जिसमें शर्लिन एक प्रॉस्टिट्यूट का रोल करने वाली हैं. इस फिल्म में इस हॉट एक्ट्रेस के साथ एक नए चेहरे को कास्ट किया जाएगा. वैसे स्वप्ना नसीरुद्दीन शाह के बेटे विवान शाह को इस रोल के लिए साइन करना चाहतीं थीं, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया. आपको बता दें कि फिल्म में शर्लिन के अपॉजिट कैरेक्टर के लिए स्वप्ना विवान को लेना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने रेडलाइट एरिया पर बन रही इस फिल्म में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई. इसके बाद स्वप्ना ने एक नए एक्टर को इस कैरेक्टर के लिए कास्ट करने का फ़ैसला किया है. अभी एक्टर की तलाश चल रही है. वैसे तो शर्लिन बिना किसी फिल्म के ही एक्सपोज़ करती हैं, लेकिन अब वह फिल्म में सैक्स वर्कर का काम करने जा रही हैं, ऐसे में क्या रंग दिखाती हैं, यह तो आने वाली फिल्म में उनका रोल ही बताएगा.

हॉलीवुड से...

रास न आई लियोन

साल 2010 में मैक्सिम पत्रिका द्वारा टॉप 12 पॉर्न स्टार में शामिल की गई इंडो केनेडियन स्टार और अडल्ट फिल्म ऐक्ट्रेस सन्नी लियोन को कई मैगजीन जैसे डेबॉनेयर, पेंटहाउस, हस्लर, हाई सोसायटी और स्वैंक में देखा जा चुका है. उनके माता-पिता मूल रूप से भारत से हैं, उनकी मां हिमाचल से तो पिता दिल्ली के हैं. इसी वजह से सनी को लोग कैरन मल्होत्रा के नाम से भी जानते हैं. सन्नी केवल पॉर्न फिल्मों और मैगजीनों के लिए मॉडलिंग नहीं करतीं, बल्कि कई बिजनेस भी चलाती हैं. बिग बॉस के घर वालों की ही तरह सन्नी को कोई नहीं पहचानता था, जब तक उन्होंने देश के रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में हिस्सा नहीं लिया था. लेकिन बिग बॉस में आने के साथ ही उनकी चर्चा देश के गांव-गांव तक पहुंच गई. अचानक ही बिग बॉस में नया मेहमान देखकर एक बार को तो दर्शकों में भी उत्साह देखा गया, मगर पॉर्न स्टार का नाम सुनते ही लोगों की दिलचस्पी इसमें कम ही हो गई. हालांकि सनी ने अपनी तरफ़ से यह दलील भी रख दी कि भारत में एडल्ट इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री न होने की वजह से यहां पॉर्न स्टार को कलाकार नहीं माना जाता, लेकिन उनकी इस बात से शायद ही आम लोगों की पसंद-नापसंद पर कोई फ़र्क़ पड़ता है. बिग बॉस में पॉर्न स्टार लाकर भी यह शो लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित तो नहीं कर पाया, लेकिन बॉलीवुड के निर्माता व निर्देशक और कलाकार उनकी तरफ़ तेज़ी से आकर्षित हुए. जहां कमाल ख़ान ने उनसे शादी करने की इच्छा रख दी, वहीं महेश भट्ट ने अपनी अगली फिल्म जो फिल्म मर्डर का सिक्वल है, उसमें सनी को कास्ट करने की बात कह दी है. एक के बाद एक आती विदेशी एक्ट्रेसेस और उन्हें भारत की फिल्म इंडस्ट्री से धड़ल्ले से मिलते ऑफर का यह ट्रेंड देखकर लगता है कि जल्द ही भारतीय सिनेमा में उनकी अच्छी पैठ होने वाली है, और दर्शकों को पर्दे पर देशी ब्यॉज के साथ विदेशी बालाओं के रोमांस के क़िस्से देखने को मिलेंगे. बॉलीवुड को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने वाली अभिनेत्रियों जैसे हेमा मालिनी, वैजयंती माला और दूसरी अभिनेत्रियों की ख्याति को क़ायम रखने का सिलसला विदेशी अभिनेत्रियों की पैठ से ख़त्म हो सकता है, ऐसा अंदेशा है. लेकिन इस बात की ज़िम्मेदारी बॉलीवुड के बड़े नामों पर है कि वे भारतीय कला और कलाकारों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाते रहें. बहरहाल, विदेशी बालाओं ने देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

8 दिसंबर, (जन्मदिन पर विशेष)

हिंदी सिनेमा के इतिहास का उज्जवल अध्याय

धर्मेंद्र फिल्म जगत में सपने लेकर आए थे. उनका कोई गॉड फादर नहीं था. उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा. 1960 के दशक में विभिन्न किरदारों से सजीं धर्मेंद्र की 52 फिल्में रिलीज़ हुईं, जिनमें अधितकतर समाज की समस्याओं और रोमांस पर आधारित थीं. यह वह ज़माना था जब फिल्में बनाने का मक़सद केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी देना होता था. 1970 के दशक में फूल और पत्थर की सफलता ने धर्मेंद्र ही मैन के रूप में स्थापित किया. इसी दशक में धर्मेंद्र के हिस्से में इसी इमेज को ध्यान में रखकर फिल्में बनीं. इसी दशक में धर्मेंद्र ने 63 सफल फिल्मों में काम किया. फिल्म शोले ने हिंदी फिल्मों के इतिहास में सफलता के एक नए अध्याय की शुरुआत की. 36 वर्ष गुज़र जाने के बाद भी शोले के वीरू का किरदार लोगों की जुबां पर आम है.1980 के दशक में उन्होंने 75 फिल्मों में काम किया. उस समय धर्मेंद्र की इमेज बॉक्स आफिस पर ऐसी बन चुकी थी, जो पर्दे पर एक साथ 10-20 लोगों से लोहा लेता हुआ नज़र आता था. अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी गुलामी ने धर्मेंद्र को एक अमिट किरदार दिया. ढलती उम्र के बावजूद अपने फिल्मी करियर के चौथे दशक में भी धर्मेंद्र के जोश में कोई कमी नहीं आई. उन्होंने 44 फिल्मों में काम किया.

आज वह उम्र के उस पड़ाव पर हैं, जहां संघर्ष, जुस्तजू, इच्छाओं, शोहरत और कामयाबी कोई मायने नहीं रखती. इन सबके बावजूद धर्मेंद्र फिल्मी पर्दे से अपना रिश्ता ख़त्म करने को तैयार नहीं हैं. इस साल वह टीवी चैनल पर बतौर जज अपनी नई पारी का आगाज़ कर चुके हैं. वह अपनी जीवनी उर्दू में लिख रहे हैं. धर्मेंद्र को फिल्मों मे लाने वाले अर्जुन हिंगुरानी उनकी सादगी के दीवाने हैं.

कमल देवबंदी
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 05 दिसंबर-11 दिसंबर 2011

www.chauthiduniya.com

"संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI STATION
BIT Pithoria, Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9386045623/9470981772

9470943888, 9471763171

नीतीश और शिवानंद के ख़िलाफ़ याचिका

रांची की विशेष अदालत में मिथिलेश प्रसाद सिंह ने चारा घोटाले के मामले में याचिका दायर कर एक नया टिवस्ट पैदा कर दिया है. इस याचिका ने इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है. याचिकाकर्ता की मांग है कि दोनों के खिलाफ भी सम्मन जारी किया जाए.

सरोज सिंह

चारा का चक्कर

बिहार की सत्ता की राजनीति के सूरमाओं के साथ चारा घोटाले का रिश्ता काफी पुराना है. इसी चारा घोटाले ने किसी को सत्ता से बेदखल किया तो किसी के लिए सत्ता का रास्ता तैयार किया. किसी ज़माने में हर एक की जुबां पर चढ़े चारा घोटाले की फाइलें अचानक रफ्तार पकड़ने लगी हैं. रांची व पटना की अदालतों में दायर की गई याचिकाओं से आने वाले दिनों में एक बार फिर सूबे की राजनीति गरमाने के आसार बन गए हैं. पहले से चल रहे मामले के अलावा, इधर इस घोटाले में कुछ नई याचिकाएं डाली गई हैं. इन याचिकाओं से ही तूफान खड़ा हो गया है. रांची की विशेष अदालत में मिथिलेश प्रसाद सिंह ने चारा घोटाले के मामले आरसी 20ए/96 में याचिका दायर कर अदालत से कहा है कि श्याम बिहारी सिन्हा, डॉ. आर के दास और अनुसंधान अधिकारी ए के झा के 161 और 164 के बयान के अलावा कई अन्य बयानों से स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार व शिवानंद तिवारी ने इस घोटाले में पैसा लिया है. याचिका में कहा गया है कि ऐसे ही आरोपों में कई अभियुक्तों को अदालत ने सजा सुनाई है और कई अभियुक्त जेल की हवा खाने के बाद अदालती कार्यवाही से गुज़र रहे हैं. ग़ौरतलब है कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के तहत सीबीआई ने मिथिलेश प्रसाद सिंह को बताया है कि श्याम बिहारी सिन्हा ने अपने बयान में कहा था कि उमेश कुमार सिंह के मार्फत एक करोड़ रुपया नीतीश कुमार के यहां भेजा गया था. लेकिन उमेश कुमार सिंह ने अपने बयान में इस बात से इनकार किया है. इसलिए आगे की कार्रवाई नीतीश कुमार पर नहीं की जा सकी. याचिका में कहा गया है कि अनुसंधान अधिकारी ने गवाही के दौरान स्वीकार किया कि एक करोड़ रुपया विजय मलिक के मार्फत उमेश सिंह के पास नीतीश कुमार को देने के लिए भेजा गया था. इसके अलावा दस लाख रुपया महेंद्र प्रसाद और पांच लाख रुपया आर के राणा के मार्फत नीतीश कुमार को दिया गया. नीतीश कुमार ने पैसा पाने की बात स्वीकार कर श्याम बिहारी सिन्हा को धन्यवाद भी दिया. आर के दास ने गवाही में विदेश जाने वक्त भी नीतीश कुमार द्वारा पैसा लेने की बात कही है. इन बातों के आधार पर मिथिलेश सिंह ने अपने वकील दीनू कुमार से राय कर रांची की सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से प्रार्थना की है कि नीतीश कुमार व शिवानंद तिवारी के खिलाफ सम्मन जारी किया जाए. इसके अलावा वैकल्पिक प्रार्थना यह भी की गई है कि 173/8 के तहत इन दोनों के खिलाफ आगे का अनुसंधान किया जाए.

रांची की अदालत में याचिका दायर करने के मामले में मिथिलेश सिंह ने बताया कि केवल उमेश सिंह के बयान के आधार पर नीतीश कुमार व शिवानंद तिवारी के खिलाफ मामले को रोक देना उचित प्रतीत नहीं होता है. इस मामले में महेंद्र प्रसाद व आर के राणा से पूछताछ क्यों नहीं गई. सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार व शिवानंद तिवारी से पूछताछ क्यों नहीं हुई. पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील दीनू कुमार ने कहा कि रांची की सीबीआई अदालत में आरसी 33 ए/96 और आरसी 38ए/96 मामले में भी याचिका दायर करने की तैयारी पूरी हो चुकी है. चारा घोटाला मामले में छह माह आठ दिन अंदर रह चुके उमेश कुमार सिंह का कहना है कि मुझे अंदर क्यों भेजा गया, यह समझ से परे है. मुझे गिरफ्तार करने का जो आधार बनाया गया, वह नीतीश कुमार व शिवानंद तिवारी पर लागू क्यों नहीं किया गया. सीबीआई ने बाद में कहा कि उमेश सिंह किसी मामले में अभियुक्त नहीं हैं. अगर ऐसा था तो मुझे छह माह आठ दिन अंदर क्यों रखा गया. उन्होंने कहा कि सीबीआई ने नीतीश कुमार व शिवानंद तिवारी से पूछताछ क्यों नहीं की. मुझे सबसे ज़्यादा दिनों तक रिमांड पर रहना पड़ा, इसका ज़िम्मेदार कौन है. उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आएगी तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे.

इधर चारा घोटाले में जमानत पर छूटे अभियुक्तों पर भी एक बार फिर शिकंजा कस सकता है. 15 वर्षों से ट्रायल में लंबित मामले को खुलवाने की कवायद शुरू हो गयी है. पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि किस कारण से 1996 में दर्ज मामले का निष्पादन नहीं हो रहा है. अदालत ने जानना चाहा है कि किस कारण से ट्रायल कोर्ट में स्पेशल केस नं. आरसी 64 ए/1996 ठंडे बस्ते में पड़ा है. कोषागार से अवैध निकासी के इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पूर्व विधायक रवींद्र कुमार राणा, विद्यासागर निशाद, सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र, ए सी चौधरी, आईएसएस अरूमुगम, परमहंस कुमार सिंह आदि लोग अभियुक्त हैं. अदालत को जानकारी दी गयी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में राज्य सरकार से जबाब तलब किया है. अदालत इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी माह में करेगी.

न्यायाधीश टी मीना कुमार एवं न्यायाधीश विकास जैन की खंडपीठ ने मुंगेर के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की लोकहित याचिका पर सुनवाई की, तो 900 करोड़ के चारा घोटाले की विस्तृत जानकारी दी गयी. सांसद का पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी ने कहा कि पशुपालन घोटाले से जुड़े जो मामले बिहार विभाजन के बाद झारखंड में गये, उन पर ट्रायल चल रहा है, किन्तु यहां यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया प्रतीत होता है. सुनवाई में मौजूद सीबीआई के वकील विपिन कुमार सिन्हा का कहना था कि अभियुक्तों द्वारा अनेक प्रकार के आवेदन दायर किये जाते रहते हैं, इस कारण ट्रायल प्रभावित होता रहता है. इतना ही नहीं सीबीआई जज के पद भी रिक्त हैं, इस पर अदालत का कहना था कि खाली पड़े जज के पद को भरने की अधिसूचना जारी हो चुकी है. शेष कार्य राज्य सरकार को करना है.

feedback@chauthiduniya.com

आरोप

उन नेताओं की सूची, जिन पर आरोप है कि इन्होंने चारा घोटाले के सूत्रधार श्याम बिहारी सिन्हा से कथित तौर पर धन प्राप्त किया था

नाम	राशि (रुपयों में)
नीतीश कुमार	1,00,00,000
ज्ञान रंजन	35,00,000
गुलशन लाल अजमानी	57,00,000
भोला राम तूफानी	50,00,000
विद्या सागर निषाद	50,000
राधानन्दन झा	8,00,000
जगदीश शर्मा	5,00,000 प्रति माह
राजो सिंह	1,00,000 प्रति माह
राम दास सिंह (राय)	5,00,000 प्रति माह
धुती पाहन	15,00,000
रामचंद्र बैठा	2,50,000
सूरज मणि सिंह	7,50,000
करमचन्द भगत	5,00,000
निर्व्यास कुमार सिंह	15,00,000
शिवानन्द तिवारी	60,00,000
जेउ सिंह यादव	15,00,000
अमर कुमार सिंह	5,00,000
विवेकानन्द शर्मा	28,50,000
अभय सिंह	20,00,000
उदय शंकर झा	1,00,000

बयान

रांची की सीबीआई अदालत में आरसी 33 ए/96 और आरसी 38ए/96 मामले में भी याचिका दायर करने की तैयारी पूरी हो चुकी है. जल्द ही सही तस्वीर सामने आ जाएगी.

-दीनू बाबू

केवल उमेश सिंह के बयान के आधार पर नीतीश कुमार व शिवानंद तिवारी के खिलाफ मामले को रोक देना उचित नहीं है. इस मामले में महेंद्र प्रसाद व आर के राणा से पूछताछ क्यों नहीं गई?

-मिथिलेश सिंह

सीबीआई ने नीतीश कुमार व शिवानंद तिवारी से पूछताछ क्यों नहीं की? मुझे सबसे ज़्यादा दिनों तक रिमांड पर रहना पड़ा, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? सच्चाई सामने आएगी तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे.

-उमेश कुमार सिंह

याचिका में

- रांची की विशेष अदालत में मिथिलेश प्रसाद सिंह ने चारा घोटाले के मामले आरसी 20ए/96 में याचिका दायर की.
- अदालत से कहा कि श्याम बिहारी सिन्हा, डॉ. आर के दास और अनुसंधान अधिकारी ए के झा के 161 और 164 के बयान से स्पष्ट है कि नीतीश कुमार व शिवानंद तिवारी ने इस घोटाले में पैसा लिया है.
- आरटीआई के तहत सीबीआई ने मिथिलेश प्रसाद सिंह को बताया है कि श्याम बिहारी सिन्हा ने अपने बयान में कहा था कि उमेश कुमार सिंह के मार्फत एक करोड़ रुपया नीतीश कुमार के यहां भेजा गया था.
- अनुसंधान अधिकारी ने गवाही के दौरान स्वीकार किया कि एक करोड़ रुपया विजय मलिक के मार्फत उमेश सिंह के पास नीतीश कुमार को देने के लिए भेजा गया था.
- दस लाख रुपया महेंद्र प्रसाद और पांच लाख रुपया आर के राणा के मार्फत नीतीश कुमार को दिया गया.
- आर के दास ने गवाही में विदेश जाने वक़्त भी नीतीश कुमार द्वारा पैसा लेने की बात कही है.
- इस आधार पर मिथिलेश सिंह ने रांची की सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर कर अदालत से प्रार्थना की है कि नीतीश कुमार व शिवानंद तिवारी के ख़िलाफ़ सम्मन जारी किया जाए.
- इसके अलावा वैकल्पिक प्रार्थना यह भी की गई है कि 173/8 के तहत इन दोनों के ख़िलाफ़ आगे का अनुसंधान किया जाए.